चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

13 जुलाई –19 जुलाई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

जामिया हमदर्द को बर्बाद करने की साजिश

चौथी दुनिया ने वर्ष 2013 में जामिया हमदर्द में चल रहे भ्रष्टाचार और ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों को उजागर करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों की वजह से जामिया हमदर्द आज एक अवैध यूनिवर्सिटी बनकर रह गई है. छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के ऊपर शारीरिक उत्पीड़न का मुक़दमा चल रहा है. कुलपति ने यूजीसी और शिक्षा विभाग के नियम-सिद्धांतों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी नियुक्ति खुद कर ली है. यूनिवर्सिटी की ज़मीन अवैध तरीक़े से बेचने की कोशिश की जा रही है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां एमबीबीएस कोर्स में दाख़िले पर पाबंदी लगा दी है. यूजीसी ने हमदर्द के रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाने वाली सभी फैलोशिप बंद कर दी हैं. आख़िर क्या है पूरी कहानी, पढ़िए चौथी दुनिया की इस विशेष रिपोर्ट में...

डॉ. क़मर तबरेज़

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त रेनु बत्रा ने जामिया हमदर्द के कुलपति डॉ. जीएन क़ाज़ी को नौ सितंबर, 2009 को एक पत्र लिखा. इस पत्र द्वारा रेनु बत्रा ने जीएन क़ाज़ी को सूचना दी कि यूजीसी ने आपकी यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक, एससी-एसटी महिलाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी स्थापित करने को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए सरकार की ओर से कुल 13 करोड़ 95 लाख 38 हज़ार रुपये दिए जाएंगे. छह करोड़ 97 लाख 69 हज़ार रुपये की पहली किस्त जामिया हमदर्द को 15 सितंबर, 2009 को जारी भी कर दी गई, जिसका चेक नंबर था 561029. लेकिन, आज पांच साल बाद भी कोचिंग एकेडमी की वह बिल्डिंग कहीं नज़र नहीं आ रही है. क़रीब सात करोड़ रुपये की वह पहली किस्त न जाने कहां चली गई? जामिया हमदर्द में लोग दबी ज़ुबान से यही कहते हैं कि इस कैंपस में जीएन काज़ी का अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. यूजीसी का वह पैसा शायद उन्होंने अपने इसी प्रोजेक्ट पर ख़र्च कर दिया हो.

हॉस्टल जबरन खाली कराया

अगर आप जामिया हमदर्द में जाएंगे, तो उसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल आपको अपनी ओर ज़रूर आकर्षित करेंगे. यह हॉस्टल किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है. जहां सामान्य श्रेणी के छात्र से प्रतिवर्ष छह लाख रुपये और मैनेजमेंट कोटे के छात्र से प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये लिए जाते हों, वहां ऐसे आलीशान हॉस्टल पर किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए. सवाल यह है कि जामिया हमदर्द को उसके संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद ने केवल अमीरों के लिए नहीं बनाया था, तो फिर जीएन क़ाज़ी ग़रीब छात्रों से उनका हक़ क्यों छीन रहे हैं? मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे पहले तो उन्होंने जामिया हमदर्द की वह बिल्डिंग खाली कराई, जहां पहले मैनेजमेंट की पढ़ाई होती थी. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से यहां एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की अनुमति लेने के लिए कॉलेज में ओपीडी का होना भी अनिवार्य शर्त है. इसलिए इस बिल्डिंग से सटे हुए लड़कियों के दो छात्रावास यानी रजिया सुल्तान और रुफैदा नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल को खाली कराकर उन्हें कॉलेज की ओपीडी और आईपीडी में परिवर्तित कर दिया गया. जामिया हमदर्द की जो लड़कियां उन छात्रावासों में रह रही थीं, वे कहां जाएं, इसका हल जीएन क़ाज़ी ने यह निकाला कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के इब्ने सीना हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से 15 मई, 2015 तक अपने कमरे खाली करने को कहा, ताकि उनमें लड़कियों को शिफ्ट किया जा सके. इसी को लेकर छात्रावास में रहने वाले लड़के यूनिवर्सिटी प्रशासन के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आए.

> **पहली बार यूनिवर्सिटी के सबसे प्रमुख पद पर नियुक्त व्यक्ति ने कैंपस की दो एकड़ ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी को बेचने का षड्यंत्र रचा, लेकिन वह अपने षड्यंत्र में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, क्योंकि समय रहते उसकी भनक यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलाधिपति सैयद हामिद (स्वर्गीय) को लग गई. इसी घटना के कारण वहां के स्टॉफ को पहली बार पता चला कि जिस ज़मीन पर जामिया हमदर्द स्थित है, वह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की है, जिसके लिए जामिया प्रशासन डीडीए को हर वर्ष नियमित किराया देता है.**

प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के दाख़िले पर रोक

जीएन क़ाज़ी की करतूतों के चलते उनके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग चुका है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जामिया हमदर्द के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के दाख़िले पर इस वर्ष पाबंदी लगा दी है. 2012 से शुरू होने वाले इस मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक वर्ष देश-विदेश के 100 छात्र प्रवेश लेते हैं और इस समय कॉलेज में कुल 300 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. अगर इस बार भी दाख़िले की इजाज़त मिल जाती, तो यहां पर कुल 400 छात्र हो जाते. जीएन क़ाज़ी ने पहले ही वर्ष इसके प्रवेश में गड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से चार छात्रों का एडमिशन संदिग्ध हो गया.

मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अदालत ने अपनी ओर से कोई फ़ैसला न सुनाते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस बात की छूट दे दी कि उसे पूरा अधिकार है कि वह जो चाहे फ़ैसला ले. अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले बैच के छात्रों के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा भी रद्द कर दी है यानी लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी उक्त छात्र अब अपने भविष्य को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं.

किराए पर प्लेग्राउंड

लड़कियों के लिए कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है. लड़कों के लिए जो प्लेग्राउंड था, उसे छह वर्ष पहले चार लाख रुपये वार्षिक किराये पर टर्फ नामक कंपनी को दे दिया गया है, जिसने वहां यूनिवर्सिटी के छात्रों के खेलने पर पाबंदी लगा दी है. यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी शाम पांच बजे बंद कर दी जाती है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोताहियों के कारण यूजीसी ने उनकी फेलोशिप बंद कर दी है. आयुष ने

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गन्ना किसानों का बकाया नहीं देंगी चीनी मिलें, बंदी का ऐलान | P-3

चंबल को बचाएंगे पूर्व बागी | P-4

बिहार विधानसभा चुनाव विशेष | P-5

जामिया हमदर्द को बर्बाद करने की साजिश

पृष्ठ 1 का शेष

यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक यूनानी अस्पताल बनाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वह अस्पताल अब तक नहीं बना है.

अवैध यूनिवर्सिटी

सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय जामिया हमदर्द एक अवैध यूनिवर्सिटी कैसे है? जामिया हमदर्द को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए जब जामिया प्रशासन ने 21 दिसंबर, 1988 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार को पत्र लिखा, तो वहां के तत्कालीन उपसचिव गुरबख्श सिंह ने जामिया प्रशासन को 20 मार्च, 1989 को जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार जामिया हमदर्द को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए तैयार है, बशर्ते वह हकीम अब्दुल हमीद की अध्यक्षता में चलने वाले छह संस्थानों इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, हमदर्द तिब्बी कॉलेज, हमदर्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मजीदिया अस्पताल एवं स्कूल ऑफ नर्सिंग का जामिया हमदर्द में विलय कर दे और फिर जामिया हमदर्द को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर कराए. जामिया अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और शिक्षा विभाग की सलाह- मशविरे से तैयार किए गए यूनिवर्सिटी के नियम-सिद्धांत भी रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज के यहां जमा कराए. जामिया हमदर्द ने सरकार की इन शर्तों को पूरा करते हुए 26 अप्रैल, 1989 को रजिस्ट्रार ऑफ सोसयटीज से प्रमाणपत्र संख्या-एस/19910/1989 हासिल किया और उसे शिक्षा विभाग में जमा कराया. इसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने जामिया हमदर्द से कहा कि वह यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी की मदद से नए सिरे से अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स तैयार करे, ताकि यूजीसी की सिफ़ारिश पर उसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा सके. जामिया हमदर्द ने इस शर्त को भी पूरा किया. लिहाज़ा, यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत केंद्र सरकार ने 10 मई, 1989 को जामिया हमदर्द को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होने की घोषणा कर दी और इस सिलसिले में गज़ट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन नंबर एफ.9-18/85-यू.3 भी प्रकाशित करा दिया. जिस पर भारत सरकार के तत्कालीन संयुक्त सचिव जेडी गुप्ता के हस्ताक्षर मौजूद हैं.

लिहाज़ा, यह कहना ग़लत नहीं होगा कि हमदर्द यूनिवर्सिटी जिस दिन शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई उपरोक्त शर्तें पूरा करना बंद कर देगी, उसी दिन से वह एक अवैध यूनिवर्सिटी हो जाएगी. ताज़ा स्थिति भी कुछ ऐसी है. यही कारण है कि 2013 से लेकर आज तक यूजीसी द्वारा जामिया हमदर्द से कई स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी तक कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका है. इसी तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा भी यूजीसी से जामिया हमदर्द के बारे में कई प्रकार की जानकारियां हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है. यही कारण है कि तंग आकर यूजीसी ने अपने अधिकार 2-एफ के तहत पिछले वर्ष से जामिया हमदर्द की न केवल सभी ग्रांट बंद कर दीं, बल्कि अपने अधिकार 12-बी के तहत उसने जामिया हमदर्द के छात्रों एवं रिसर्च स्कॉलर्स को दी जाने वाली सभी फेलोशिप और सुविधाएं बंद कर दी हैं. ज़ाहिर है, इससे जामिया हमदर्द के छात्रों का भविष्य ख़तरे में पड़ चुका है.

दरअसल, यूजीसी के डायरेक्टर विक्रम सहाय ने पूरे भारत की 24 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज (डीयू) को 13 दिसंबर, 2013 को एक सर्कुलर संख्या एफ 9-5/2008 (डीयू) जारी करके बताया था कि यूजीसी ने इन यूनिवर्सिटीज की फंडिंग से संबंधित शर्तों का नए सिरे से निरीक्षण करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी. उस एक्सपर्ट कमेटी ने जो अनुशंसाएं की हैं, उनकी बुनियाद पर सभी 24 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए ज़रूरी है. यह भी कहा गया कि सभी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज वित्तीय वर्ष 2015-16 शुरू होने से पहले यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12-बी के तहत मंजूरी और एनएएसी (नेशनल एनालिसिस एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल) की शर्तें पूरा करके उसका सर्टिफिकेट हासिल कर लें. और, जिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज ने यूजीसी के 2010 के रेगुलेशन के अनुसार अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) में संशोधन नहीं किया है, वे फौरन ऐसा करते हुए यूजीसी एवं मानव संसाधन मंत्रालय से उसकी मंजूरी हासिल करें और सभी आवश्यक शर्तें पूरा करके संपूर्ण विवरण यूजीसी कार्यालय में एक जून, 2014 तक जमा करा दें, वरना यूजीसी की ओर से उन्हें मिलने वाली सभी ग्रांट्स एक अप्रैल, 2015 से रोक दी जाएंगी.

जामिया हमदर्द ने यूजीसी को अपना जवाबी पत्र संख्या- जेएच/यूजीसी/2014 22 मई 2014 को भेजा, जो उसके लिए संतोषजनक नहीं था, इसलिए यूजीसी ने दोबारा जामिया हमदर्द को 26 जून, 2014 को एक पत्र लिखा और पूरा फॉर्मेट भेजा कि कैसे उक्त विवरण भेजने हैं. इस पत्र द्वारा जामिया हमदर्द से एनएएसी सर्टिफिकेट, कोर्स वाइज फीस स्ट्रक्चर और उसका आधार, टीचिंग स्टॉफ का विवरण दाखिल करने के लिए कहा गया कि विभागवार कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर इस समय यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं तथा कितनों की आवश्यकता है. जामिया हमदर्द ने यूजीसी को इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया. लिहाज़ा, यूजीसी ने 9 अक्टूबर, 2014 को तीसरा पत्र लिखकर विवरण दाखिल करने के लिए कहा, लेकिन जब इससे भी जामिया के कुलपति और रजिस्ट्रार पर कोई असर नहीं हुआ, तो नाराज़ होकर यूजीसी ने जामिया हमदर्द की सभी ग्रांट्स बंद कर दीं.

अवैध नियुक्ति

वर्तमान कुलपति डॉ. गुलाम नबी (जीएन) क़ाज़ी पर आरोप है कि वह अवैध रूप से कुलपति के पद पर नियुक्त हैं. क़ाज़ी को 13 अक्टूबर, 2008 को जामिया हमदर्द का कुलपति बनाया गया था. इस पद पर उन्हें अगले पांच वर्षों तक या इससे पहले जब भी उनकी उम्र 65 वर्ष की हो जाए, तब तक रहना था. क़ाज़ी साहब की जन्म तिथि चूंकि 14 अगस्त, 1946 है, लिहाज़ा 14 अगस्त, 2011 को 65 वर्ष के हो जाने के कारण वह कुलपति पद से रिटायर हो गए. जामिया हमदर्द के नियमों के अनुसार उन्हें यूनिवर्सिटी के वरिष्ठतम प्रोफेसर को कार्यकारी कुलपति की ज़िम्मेदारी सौंपते हुए वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. दो दिनों बाद यानी 16 अगस्त को उन्होंने रजिस्ट्रार डॉ. फिरदौस अहमद वानी के हस्ताक्षर वाला एक नोटिफिकेशन जारी कराकर 70 वर्ष की आयु तक स्वयं को जामिया हमदर्द का कुलपति नियुक्त होने की घोषणा करा दी. इसके लिए जीएन काज़ी ने अवैध तौर-तरीकों का सहारा लिया. बहाना तो उन्होंने यह बनाया कि चूंकि यूजीसी ने कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है, इसलिए क़ानून उन पर भी लागू होता है और इसी आधार पर वह अब तक जामिया हमदर्द के कुलपति बने हुए हैं. लेकिन, छह नवंबर, 2008 को कुलपति की आयु बढ़ाने से संबंधित जामिया हमदर्द समेत भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज को भेजे गए अपने पत्र में यूजीसी ने यह भी कहा था कि हर यूनिवर्सिटी ऐसा करने से पहले अपनी रूल बुक या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) में आवश्यक संशोधन कर ले और फिर उस संशोधित कॉपी को रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज के पास जमा करा दे.

जिस समय डॉ. जीएन क़ाज़ी 65 वर्ष की आयु पूरी करने के कारण जामिया हमदर्द के कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए, उस समय तक जामिया हमदर्द के एमओए में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था. यूजीसी के निर्देश मिलने के बाद जामिया हमदर्द की उच्चतम डिसीजन मेकिंग बॉडी, ईसी या कार्यकारिणी की बैठक 14 मार्च, 2009 को बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जीएन क़ाज़ी ने की. ईसी ने कुलपति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने को अपनी स्वीकृति दे दी. लेकिन, यूजीसी के निर्देशों के अनुसार एमओए में कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित संशोधन आवश्यक है, यह बात जीएन क़ाज़ी ने कार्यकारिणी के सदस्यों से छिपा ली. इसके बाद जामिया हमदर्द सोसायटी को ईसी के इस निर्णय से 28 मार्च, 2009 को सूचित किया गया. जामिया हमदर्द सोसायटी की उस मीटिंग की अध्यक्षता तत्कालीन कुलाधिपति सैयद हामिद (स्वर्गीय) ने की और जीएन क़ाज़ी सोसायटी के सदस्य की हैसियत से उसमें उपस्थित रहे. हमदर्द सोसायटी को अंधेरे में रखते हुए जीएन क़ाज़ी ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तो बढ़वा ली, लेकिन एमओए में संशोधन की बात यहां पर भी उन्होंने प्रशासन से छिपा ली. जामिया हमदर्द सोसायटी ने ईसी के निर्णय को केवल सुना और नोट किया, उसे अपनी स्वीकृति नहीं दी. ज़ाहिर है, जब तक सोसायटी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक जीएन क़ाज़ी दोबारा जामिया हमदर्द के कुलपति नहीं बन सकते, लेकिन क़ानून की परवाह न करते हुए उन्होंने रजिस्ट्रार फिरदौस वानी से अपनी पुन: नियुक्ति की घोषणा करा दी, जो अवैध है.

वक़्फ़ नहीं, डीडीए की ज़मीन

जामिया हमदर्द ने यूजीसी को अपना जवाबी पत्र संख्या- जेएच/यूजीसी/2014 22 मई 2014 को भेजा, जो उसके लिए संतोषजनक नहीं था, इसलिए यूजीसी ने दोबारा जामिया हमदर्द को 26 जून, 2014 को एक पत्र लिखा और पूरा फॉर्मेट भेजा कि कैसे उक्त विवरण भेजने हैं. इस पत्र द्वारा जामिया हमदर्द से एनएएसी सर्टिफिकेट, कोर्स वाइज फीस स्ट्रक्चर और उसका आधार, टीचिंग स्टॉफ का विवरण दाखिल करने के लिए कहा गया कि विभागवार कितने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर इस समय यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं तथा कितनों की आवश्यकता है.

अब आइए देखते हैं कि जीएन क़ाज़ी ने कुलपति रहते हुए कैसे यूनिवर्सिटी की ज़मीन पट्टे पर देने की कोशिश की और भांडा फूटने पर कैसे एक निजी कंपनी को यूनिवर्सिटी कैंपस में अपनी प्रयोगशाला बनाने और निजी कारोबार चलाने की अनुमति दी. यह मामला 2010 का है. जामिया हमदर्द के संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद का स्वर्गवास हुए 11 वर्ष बीत चुके थे. पहली बार यूनिवर्सिटी के सबसे प्रमुख पद पर नियुक्त व्यक्ति ने कैंपस की दो एकड़ ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी को बेचने का षड्यंत्र रचा, लेकिन वह अपने षड्यंत्र में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, क्योंकि समय रहते उसकी भनक यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलाधिपति सैयद हामिद (स्वर्गीय) को लग गई. इसी घटना के कारण वहां के स्टॉफ को पहली बार पता चला कि जिस ज़मीन पर जामिया हमदर्द स्थित है, वह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की है, जिसके लिए जामिया प्रशासन डीडीए को हर वर्ष नियमित किराया देता है.

आम तौर पर लोग यही जानते हैं कि जामिया हमदर्द वक़्फ़ की संपत्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि जामिया हमदर्द वक़्फ़ की संपत्ति नहीं है. दूसरा भ्रम यह है कि जामिया हमदर्द की ज़मीन संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद (स्वर्गीय) ने स्वतंत्रता के समय 35 पैसे प्रति गज़ के हिसाब से तुग़लक़ाबाद के तत्कालीन निवासियों से ख़रीदी थी और बाद में उसी ज़मीन पर उन्होंने जामिया हमदर्द की बुनियाद डाली और फिर उसे राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया. यह बात भी सही नहीं है. अब सवाल यह उठता है कि आख़िर इसका सबूत क्या है कि जामिया हमदर्द और उसकी ज़मीन वक़्फ़ की संपत्ति नहीं है? इस सवाल का जवाब हमें दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस रविंदर भट्ट की एक सदस्यीय बेंच द्वारा 23 दिसंबर, 2011 को दिए गए निर्णय से मिल जाता है. जस्टिस भट्ट ने सिविल सूट (ओएस) नंबर 116/1972, 117/1972, 118/1972 एवं 119/1972 के तहत अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड का यह दावा ग़लत और ग़ैर-क़ानूनी है कि हमदर्द दवाखाना (वक़्फ़), हमदर्द नेशनल फाउंडेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज और इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च (ये दोनों संस्थाएं 1989 में जामिया हमदर्द में विलय कर दी गईं) वक़्फ़ की संपत्ति है. दरअसल, दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड ने 12 दिसंबर, 1970 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए उपरोक्त चारों संस्थाओं के वक़्फ़ संपत्ति होने की घोषणा कर दी थी और फिर एक सप्ताह बाद यानी 19 दिसंबर, 1970 को वह नोटिफिकेशन दिल्ली गज़ट में प्रकाशित भी करा दिया था. लिहाज़ा, हकीम अब्दुल हमीद ने उस समय दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत को बताया कि उक्त संपत्ति एवं उक्त सभी संस्थान व्यवहारिक रूप देश की जनता को समर्पित हैं, लेकिन उन पर भारतीय वक़्फ़ एक्ट 1954 लागू नहीं होता, क्योंकि भारतीय वक़्फ़ एक्ट 1954 केवल उन्हीं संपत्तियों पर लागू हो सकता है, जो किसी मुसलमान द्वारा इस्लामी शरीअत के मुताबिक वक़्फ़ की गई हों. हकीम अब्दुल हमीद ने अदालत को स्पष्ट शब्दों में बताया कि हमदर्द दवाख़ाना (वक़्फ़) की आमदनी से फ़ायदा हासिल करने वाले लोग किसी समुदाय विशेष के नहीं हैं, बल्कि यह सबके लिए है. मतलब यह कि हमदर्द द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान, चाहे वह तिब्बिया कॉलेज हो या नर्सिंग होम, उनमें किसी धर्म, जाति या नस्ल का कोई भेदभाव नहीं है. उनसे भारत का हर ग़रीब और पात्र नागरिक लाभांवित हो सकता है.

अब दूसरे सवाल की ओर आते हैं. आम तौर पर भारत समेत पूरी दुनिया के लोग यही जानते हैं कि नई दिल्ली के तुग़लक़ाबाद क्षेत्र में जामिया हमदर्द जिस ज़मीन पर स्थित है, उसे जामिया हमदर्द के संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद (स्वर्गीय) ने अपने पैसों से ख़रीदा था. स्वयं जामिया हमदर्द में पढ़ाने वाले अध्यापक, वहां के छात्र और अन्य कर्मचारी भी अब तक यही समझते आए थे. वर्ष 2010 में पहली बार जामिया के स्टॉफ को इस बात का इल्म हुआ कि हमदर्द यूनिवर्सिटी की ज़मीन उसकी अपनी नहीं, बल्कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) की है, जिसे डीडीए ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से हकीम अब्दुल हमीद को 23 सितंबर, 1970 को लंबे अंतराल के लिए पट्टे (लीज़) पर दिया था. जामिया हमदर्द का कुल क्षेत्रफल 91.60 एकड़ है. इसमें से 60.79 एकड़ ज़मीन राष्ट्रपति की स्वीकृति से डीडीए ने हकीम अब्दुल हमीद को 7,33,647.20 रुपये प्रीमियम राशि जमा करने पर इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च (वर्तमान जामिया हमदर्द) बनाने के लिए लीज़ पर दी थी. लीज़ की शर्तों के अनुसार, प्रीमियम राशि का ढाई प्रतिशत यानी 18,341.18 रुपये जामिया हमदर्द को वार्षिक किराये के रूप में दो किस्तों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने होते हैं. इस किराये की पहली किस्त, जो 9,170.60 रुपये बनती है, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को और इतनी ही राशि की दूसरी किस्त 15 जुलाई को जमा करनी होती है.

जामिया हमदर्द की ज़मीन का दूसरा टुकड़ा 30.81 एकड़ का है, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति से डीडीए ने हकीम अब्दुल हमीद को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज (अब जामिया हमदर्द) स्थापित करने के लिए 23 सितंबर, 1970 को 3,72,801 रुपये प्रीमियम राशि जमा करने पर लीज़ पर दिया था. ज़मीन के इस टुकड़े का भी वार्षिक किराया प्रीमियम राशि का ढाई प्रतिशत है, जिसके अनुसार यह किराया 9,320.10 रुपये बनता है, जिसे जामिया हमदर्द को वर्ष में दो किस्तों में जमा करना पड़ता है. इस तरह अब यह बात साबित हो गई कि जामिया हमदर्द की ज़मीन वक़्फ़ की नहीं है, बल्कि डीडीए द्वारा जामिया हमदर्द को लीज़ पर दी गई ज़मीन है. लीज़ के काग़ज़ात में जो शर्तें दर्ज हैं, उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन शैक्षणिक उद्देश्य के अलावा इस ज़मीन का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकता. ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जामिया हमदर्द का कोई कुलपति यूनिवर्सिटी की ज़मीन को व्यवसायिक उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है और वह भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, जिनकी स्वीकृति से जामिया हमदर्द को डीडीए ने लीज़ पर यह ज़मीन दे रखी है?

(जिन चीज़ों का यहां उल्लेख हुआ, उनके अलावा भी बहुत-सी जानकारियां जामिया हमदर्द के बारे में इस समय चौथी दुनिया के पास मौजूद हैं. अगले अंक में उनका भी खुलासा किया जाएगा.) ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 07 अंक 19
दिल्ली, 13 जुलाई –19 जुलाई 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की केंद्र और राज्य सरकार को खुली चुनौती

गन्ना किसानों का बकाया नहीं देंगी चीनी मिलें

बंदी का ऐलान

प्रभात रंजन दीन

पूरे देश में इस साल चीनी मिलें नहीं चलेंगी और गन्ने की तैयार फसलें खेतों में ही खड़ी रह जाएंगी. देश भर की चीनी मिलों ने यह ऐलान किया है कि 2015-16 के पेराई सत्र में वे बंद रहेंगी. चीनी मिल मालिकों के संघ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इसमा) ने यह खुली घोषणा कर दी है कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा. इसमा ने यह स्वीकार किया है कि किसानों का बकाया 21 हज़ार करोड़ रुपये से भी अधिक है और 50 लाख से अधिक किसानों को भुगतान नहीं हुआ है. इसमा की यह स्वीकारोक्ति खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पर तमाचे की तरह है, क्योंकि वह हमेशा यह भ्रांति पैदा करती रही है कि राज्य में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हो रहा है. इसमा ने केंद्र और राज्य सरकारों के सामने चुनौती फेंकी है कि गेहूं और धान की तरह गन्ना किसानों को भी सीधी सहायता दी जाए. अब तक उत्तर प्रदेश समेत देश भर के गन्ना किसान आत्महत्या कर रहे थे और सरकारें उस पर पर्दा डाल रही थीं, लेकिन अब तो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इसमा) ने गन्ना किसानों को मार डालने की खुली मुनादी ही कर दी है. केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार समेत सभी संबद्ध राज्य सरकारें पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित चीनी मिलों की खुशामद करती रहीं, किसानों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया, सारी सुविधाएं चीनी मिल मालिक भोगते रहे और आख़िरकार चीनी मिल मालिकों के संघ ने ताल ठोंक कर कह दिया कि वे किसानों के बकाये का भुगतान नहीं कर पाएंगे.

इसमा की खुली घोषणा से उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों के गन्ना किसान हताशा से भर गए हैं. इसमा की खुली चुनौती का समुचित जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आया. न केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा कुछ बोला, न प्रदेश सरकार ने कोई जवाब दिया, न कोई जनप्रतिनिधि सामने आया और न मीडिया ने ही इस मसले पर केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया. बीते 30 जून को उत्तर प्रदेश के अख़बारों में प्रकाशित विशाल विज्ञापन के जरिये इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इसमा) ने देश भर के गन्ना किसानों से कहा है कि चीनी की क़ीमतों में सुधार नहीं हुआ, तो कोई भी चीनी मिल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस-एफआरपी) नहीं देगी.

इसमा ने बिंदुवार मुनादी की है कि भारतीय चीनी उद्योग अभूतपूर्व संकट में है और मौजूदा स्थितियों में गन्ने की कटाई नहीं हो सकती. चीनी मिलों की शुद्ध पूंजी समाप्त हो गई है. आर्थिक घाटे का बोझ बढ़ता जा रहा है और ग़ैर उत्पादक आस्तियां (नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स-एनपीए) बढ़ती चली जा रही हैं. लिहाजा, देश भर की चीनी मिलें 2015-16 के पेराई सत्र में बंद रहेंगी और गन्ना बिना कटाई के खेतों में खड़ा रह जाएगा. चीनी मिलों ने कहा है कि वे मिल की मरम्मत, कर्मचारियों को वेतन एवं मज़दूरी देने लायक पूंजी भी जुटाने की स्थिति में नहीं हैं. चीनी मिलों का रोना यह है कि पिछले छह साल में गन्ने का भंडार सबसे अधिक (40 लाख टन) रहा, लेकिन चीनी की क़ीमत सबसे कम रही. चीनी मिल मालिकों का कहना है कि चीनी की क़ीमत प्रति किलो लागत से भी आठ-नौ रुपये कम रही. उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को अपने भंडार की 15 प्रतिशत चीनी बेचने का आदेश दिया था. अदालत ने कहा था कि बेचने से होने वाली आय का 30 फ़ीसद हिस्सा गन्ना किसानों को दे दिया जाए. शेष 70 फ़ीसद धनराशि गन्ना मूल्य खाते में रिजर्व रखी जाए. अदालत ने स्पष्ट कहा था कि चीनी बेचने से मिलने वाली धनराशि ज़िलाधिकारियों की निगरानी में रहेगी. विडंबना यह है कि यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने दिया था, लेकिन इस आदेश को ताक पर रख दिया गया और इस खुली अवमानना पर हाईकोर्ट ने ध्यान भी नहीं दिया. पेराई वर्ष 2014-15 के लिए गन्ना किसानों के बकाये से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सभी चीनी मिलों (सरकारी एवं निजी) को 25 फ़ीसद बकाया 15 जून तक चुकाने का आदेश दिया था और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई मुकर्रर की थी. हाईकोर्ट ने निजी मिलों को 25 फ़ीसद बकाये का भुगतान 15 जून तक और बाकी 75 फ़ीसद का भुगतान 15 जुलाई तक करने का आदेश दिया था. 15 जून तक किसानों को भुगतान नहीं मिला, 15 जुलाई की तो बात ही छोड़ दें. 28 जुलाई आए, उसके पहले ही अख़बारों में विज्ञापन जारी करके इसमा ने किसानों का बकाया देने से ही इंकार कर दिया. इसमा की इस घोषणा पर सरकार चुप्पी साधे हुए है.

किसानों का बकाया देने से चीनी मिलें लगातार कन्नी काट रही हैं. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ़ से चीनी मिलों के लिए किस्म-किस्म के पैकेज और राहत-सुविधाएं प्रदान की गईं, लेकिन गन्ना किसानों को भुगतान नहीं किया गया. अभी तीन महीने पहले भी अप्रैल में चीनी मिलों ने मिल-बैठकर किसानों का बकाया देने से बचने की भूमिका बनाई थी और कहा था कि सरकार खुद उनके भंडार में पड़ी चीनी खरीद ले, तभी किसानों के बकाये की भरपाई हो सकती है. इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि चीनी के दाम नीचे गिरने की वजह से गन्ना किसानों के बकाये की कुल 21,000 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने की चीनी मिलों में शक्ति नहीं बची है. इसमा ने सरकार से कहा है कि वह 25-30 लाख टन चीनी खरीद ले, तो क़रीब सात हज़ार करोड़ रुपये से किसानों का थोड़ा भुगतान हो पाएगा. उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का सबसे ज़्यादा क़रीब 12 हज़ार करोड़ रुपये बकाया है. गन्ना-गणित के विशेषज्ञ एवं किसानों के जुझारू नेता शिवाजी राय का मानना है कि चीनी मिलों द्वारा सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते और उनमें भारी फर्जीवाड़ा किया जाता है. चीनी मिलें घाटे की बात करती रहती हैं, लेकिन अपना उत्पादन बढ़ाती जा रही हैं. चीनी मिलें एक तरफ़ लाभ कमा रही हैं, तो दूसरी तरफ़ अख़बारों में विज्ञापन देकर नुक़सान दिखा रही हैं. हाल में चीनी मिलों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने छह हज़ार करोड़ रुपये का सस्ता कर्ज दिया. पिछले साल भी 11 हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया था. ब्याज रियायत योजना के तहत पहले साल क़रीब 600 करोड़ रुपये का ब्याज भी केंद्र सरकार ही चुकाएगी.

शिवाजी राय कहते हैं कि भारत विश्व का पहला देश है, जहां किसानों के बजाय पूंजीपतियों को सब्सिडी दी जाती है. गन्ना किसानों का बकाया न देने और मिलें बंद करने की घोषणा को शिवाजी राय केंद्र और प्रदेश सरकारों के साथ मिल मालिकों की रजामंदी से की गई घोषणा बताते हैं. वह कहते हैं कि इसी बहाने केंद्र सरकार मज़दूर विरोधी श्रम नीति लाएगी, जिस तरह किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया. राय कहते हैं कि चीनी मिलों की हालत इतनी ही खस्ता है, तो केंद्र सरकार को सारी चीनी मिलों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए. इससे सरकार का बजट बोझ भी कम होगा और किसानों को राहत भी मिल जाएगी. उत्तर प्रदेश सरकार भी चीनी मिलों के हित के आगे आत्मसमर्पित है. किसानों के करोड़ों रुपये के बकाये की बात तो छोड़िए, चीनी मिल मालिकों ने 2013-14 के पेराई सत्र के लिए गन्ने की क़ीमत 260 रुपये प्रति क्विंटल देने का जो वादा किया था, उसे भी पूरा नहीं किया और गन्ना 150 रुपये से 153 रुपये क्विंटल तक के भाव से बिकता रहा. चीनी मिल मालिकों पर आरोप है कि किसानों के बकाये के हज़ारों करोड़ रुपये दूसरे धंधों में निवेश कर दिए गए हैं और उससे भारी मुनाफ़ा कमाया जा रहा है. उद्योगपति धंधा कर रहा है और किसान भुखमरी का शिकार हो रहा है. इसका नतीजा यह निकला कि उत्तर प्रदेश में गन्ना बुआई के क्षेत्रफल में तेजी से गिरावट आई है. सरकारी सर्वेक्षण में भी स्पष्ट हुआ कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गन्ना क्षेत्रफल 1,50,378 हेक्टेयर कम रहा. सहारनपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में किसान अब गन्ना बोने से परहेज कर रहे हैं. पश्चिम में शामली, संभल, मथुरा एवं मुजफ्फरनगर के अलावा सभी ज़िलों में गन्ना क्षेत्र घट गया है. फैजाबाद में भी एक साल में गन्ना क्षेत्रफल 40 फ़ीसद कम हो गया. बाराबंकी, पीलीभीत, हरदोई एवं सीतापुर के किसान भी गन्ने की खेती करने से बच रहे हैं. मध्य क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल 7.6 फ़ीसद कम हुआ है. पूर्वांचल में तो और भी बुरे हालात हैं.

शिवाजी राय कहते हैं कि चीनी मिल मालिकों ने अपना सिंडिकेट (गिरोह) बना लिया है. उनके साथ सरकार की मिलीभगत है और खेतों को कॉरपोरेट फार्मिंग में बदलने की साजिश चल रही है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड), स्पेशल डेवलपमेंट जोन (एसडीजेड) और कॉरपोरेट फार्मिंग आदि खास पूंजी घरानों का हित साधने के लिए हैं. उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बहुत खुशहाल थे. गन्ने की फसल और चीनी मिलों से प्रदेश की गन्ना बेल्ट में कई अन्य उद्योग-धंधे भी फल-फूल रहे थे. चीनी मिलों और किसानों के बीच गन्ना विकास समितियां (केन यूनियन) भुगतान से लेकर खाद, ऋण, सिंचाई के साधनों, कीटनाशकों के साथ-साथ सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल एवं औषधालय तक की व्यवस्था करती थीं. गन्ने की राजनीति करके नेता तो कई बन गए, लेकिन उन्हीं नेताओं ने चीनी मिलों की दलाली करके गन्ना किसानों को बर्बाद कर दिया. गन्ना क्षेत्र से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है और उन्हें महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों में दिहाड़ी करके पेट पालना पड़ रहा है. साजिशों के तहत उत्तर प्रदेश की तक़रीबन सारी सरकारी चीनी मिलें कौड़ियों में बेच डाली गईं. इसमें सारी सरकारें शामिल रही हैं. भाजपा की सरकार ने हरिशंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज को चार मिलें बेची थीं. गंगोत्री इंटरप्राइजेज ने उन्हें चलाने के बजाय मशीनों को कबाड़ में बेचकर ढांचा सरकार के सुपुर्द कर दिया. फिर समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश की 23 चीनी मिलें अनिल अंबानी को बेचने का प्रस्ताव रखा. सपा सरकार ने उन चीनी मिलों को 25-25 करोड़ रुपये देकर चलवाया भी, लेकिन मात्र 15 दिन चलकर वे फिर से बंद हो गईं.

बसपा सरकार में मुख्यमंत्री मायावती ने सपा सरकार के उसी प्रस्ताव को उठाया और चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेचना शुरू कर दिया. मायावती ने पौंटी चड्ढा की कंपनी और आईबीएन कंपनी के हाथों 14 चीनी मिलें बेच डालीं. देवरिया की भटनी चीनी मिल महज पौने पांच करोड़ रुपये में बेच दी गई, जबकि वह 172 करोड़ की थी. कैग ने इसका पर्दाफाश भी किया. देवरिया चीनी मिल 13 करोड़ और बैतालपुर चीनी मिल 11 करोड़ रुपये में बेची गई. अब उन्हीं मिलों की ज़मीनों को प्लॉटिंग करके महंगी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है. चीनी मिलों को किसानों ने अपनी ज़मीनें दी थीं, लेकिन उनके बिकने पर उसकी अधन्नी भी संबद्ध किसानों को नहीं मिली. किसानों के खाते में गन्ने का पैसा डालने की व्यवस्था लागू करके तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने केन यूनियनें पंगु करने की राजनीति की थी. बाद की सपा और बसपा सरकारों ने उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों का बंटाधार करके रख दिया.■

feedback@chauthiduniya.com

शिवाजी राय

चीनी का दाम बढ़ाने की प्रेशर-टैक्टिस

चीनी मिलों का सिंडिकेट अपनी घोषणा के जरिये चीनी की क़ीमत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहा है. चीनी मिलों के अधिकारी खुद इसे प्रेशर-टैक्टिस बता रहे हैं. इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इसमा) का कहना है कि चीनी के दाम कम हैं, इसलिए मिलों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है. ऐसे में चीनी मिलें किसानों को भुगतान नहीं कर पा रही हैं. कई चीनी मिलों पर ताला लगने की हालत है.

35 लाख टन चीनी नष्ट कर देने की सलाह!

चीनी मिलों के मालिक इतने लोकतांत्रिक सोच से भरे हैं कि चीनी के दाम में सुधार के लिए वे स्टॉक में रखी 35 लाख टन चीनी नष्ट करने की सलाह दे रहे हैं. जैसे कभी क़ीमत का संतुलन बनाने के लिए अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया आदि देश समुद्र में गेहूं फेंकवा दिया करते थे, जिसकी दुनिया भर में काफी निंदा हुई. जिस तरह अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया को सलाह दी जाती थी कि गेहूं समुद्र में फेंकने के बजाय उसे ग़रीबों में बांट देते, तो अच्छा होता, वैसे सुझाव अपने देश के पूंजीपतियों को भी समझ में नहीं आते. भारत में अभी भी चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 20 किलो प्रति वर्ष से भी कम है. भारत के ग़रीब को चाय में भी चीनी मिल जाए, तो वह धन्य हो जाता है. ऐसे में 35 लाख टन चीनी नष्ट करने का सुझाव राष्ट्रद्रोह के अपराध में दर्ज होना चाहिए. लेकिन, यह बात न केंद्र को समझ में आएगी और न यूपी की समाजवादी सरकार को. इसमा का तर्क है कि चीनी का स्टॉक नष्ट कर देने से आपूर्ति कम हो जाएगी, जिससे चीनी की क़ीमत बढ़ जाएगी और चीनी मिलों के नुक़सान की भरपाई हो जाएगी. चीनी मिल मालिक चाहते हैं कि अतिरिक्त चीनी नष्ट करने का उन्हें विकल्प दिया जाना चाहिए. भारत के चीनी मिल मालिक ऐसी मांग करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पूंजीपरस्तों की विकृत मानसिकता के बराबर खड़े होना चाहते हैं. भारत की चीनी मिलें ब्राजील से सीख नहीं लेतीं, जहां भारतीय चीनी मिलों के मुकाबले क़रीब नौ रुपये प्रति किलो सस्ती चीनी का उत्पादन होता है और ब्राजील की चीनी मिलें ही वहां का बाज़ार नियंत्रित करती हैं. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में शुगर मिल लॉबी बेहद प्रभावशाली है. राज्य सरकारों पर ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर भी चीनी मिल मालिकों का लगातार प्रभाव और दबाव बना रहता है. लिहाजा, इसमा की घोषणा पर अपेक्षित कार्रवाई कितनी किसानोन्मुखी होगी, यह आप अच्छी तरह सोच-समझ सकते हैं.

हड़ताल का ऐलान नहीं, संकट का खुलासा

अविनाश वर्मा

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इसमा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने चौथी दुनिया से कहा कि इसमा की घोषणा चीनी मिलों की हड़ताल का ऐलान नहीं है, बल्कि यह चीनी मिलों पर छाए संकट का सार्वजनिकीकरण है. इसका उद्देश्य देश को यह बताना है कि चीनी मिलों की वित्तीय हालत इतनी खराब है कि अगर वे चाहें भी, तो पेराई के लिए चालू नहीं हो सकतीं. वर्मा ने कहा कि यदि क़ीमतों में बढ़ोत्तरी न की गई, तो चीनी मिलें गन्ना किसानों को उनकी फसल का उचित एवं लाभकारी मूल्य (फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस-एफआरपी) नहीं दे पाएंगी. गन्ने की क़ीमत और चीनी की क़ीमत में सामंजस्य हो, तभी चीनी मिलें चल सकेंगी.

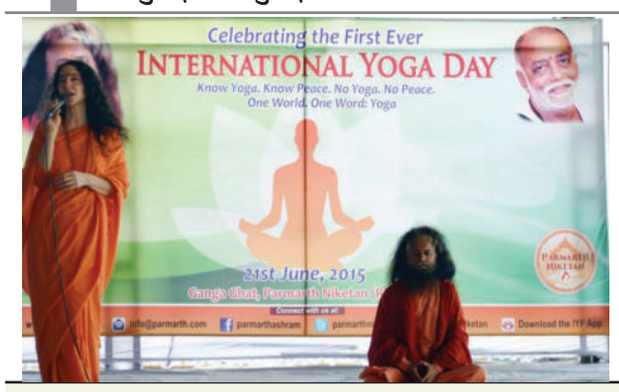

> स्वामी चिदानंद जी ने लोगों को जीवन के सभी उत्सव जन्मदिन, छुट्टियां आदि को हरित उत्सव में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि योग स्थायी जीवन जीने की कुंजी है. हरित जीवन शैली के साथ हम अपने विचारों और कर्मों को संगठित करके प्रकृति के साथ वैश्विक परिवार की सेवा कर सकते हैं. योग, गंगा सेवा, गौ सेवा, ब्रह्म-विद्या की रक्षा और विस्तार केवल किसी वर्ग विशेष की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह धरती के हर मानव का कर्तव्य है.

चंबल को बचाएंगे पूर्व बागी

रिजवान चंचल

चंबल के बीहड़, जो कभी खूंखार डकैतों की शरण-स्थली के रूप में जाने जाते थे, आजकल वीरान-से हैं. कल तक बीहड़ों में दस्यु सरगनाओं एवं दस्यु सुंदरियों के सौतिया डाह के चलते जहां चूड़ियों की खनखनाहट और गोलियों की तड़तड़ाहट आम बात थी, आज वहां सन्नाटा-सा पसरा है. उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के ज़्यादातर दस्यु गिरोहों के ख़ात्मे के चलते दस्युओं का जो खौफ ग्रामीणों के सिर चढ़कर बोलता था, वह अब नज़र नहीं आता! कल तक गोलियों से बीहड़ थर्रा देने वाले डकैत अब वन बचाने की मुहिम में शामिल होने जा रहे हैं. कल के बागी अब लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे. इस मुहिम में चंबल के खूंखार डकैत रहे मोहर सिंह, मलखान सिंह एवं सरला यादव समेत दर्जनों पूर्व डकैत हिस्सा लेंगे. चंबल की सबसे चर्चित दस्यु सुंदरियों में से एक सीमा परिहार भी मुहिम में भागीदारी करेंगी. इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं.

सीमा कहती हैं कि जंगल बहुत ज़रूरी हैं. तरक्की चाहे कितनी भी हो, लेकिन जीवन इन्हीं से है. वह पहले बसाया बीहड़-अब बचाएंगे बीहड़ का नारा देंगी. 13 साल की उम्र में हथियार उठाने वाली सीमा पर लगभग 70 हत्याओं और 150 से ज़्यादा लोगों के अपहरण का आरोप था. 18 मई, 2000 को पुलिस मुठभेड़ में लालाराम के मारे जाने के बाद 2003 में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. औरैया में रहते हुए वह राजनीति में भी सक्रिय हैं. सीमा मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और अपनी कहानी की एक फिल्म में काम कर चुकी हैं. पिछले दिनों वह बिग बॉस में भी देखी गईं. औरैया के दिबियापुर निवासिनी 35 वर्षीय सीमा परिहार ने कहा कि यह एक अच्छी मुहिम है, अब समाज-सेवा ही हमारा लक्ष्य है और पेड़-पौधे जीवन का अहम हिस्सा हैं. वह कहती हैं कि उन्होंने काफी समय जंगल में बिताया है, इसलिए

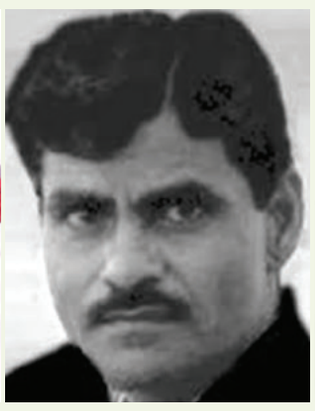

वह पेड़-पौधों की अहमियत अच्छी तरह समझती हैं. सीमा कहती हैं कि मौजूदा वक्त में तेजी से पेड़ काटे तो जा रहे हैं, लेकिन लगाए नहीं जा रहे हैं.

दरअसल, जयपुर में पर्यावरण और वनों को बचाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम में चंबल के पूर्व डकैत भी शिरकत करने वाले हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में 1970-80 के दशक में जो डकैत कभी बीहड़ में रहा करते थे, उनमें से कई अब आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं. ज़ाहिर है, ये लोग जंगल बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये जंगल के भूगोल और हालात को अच्छी तरह समझते हैं. जयपुर के कार्यक्रम में क़रीब दो दर्ज़न से ज़्यादा पूर्व डकैतों के हिस्सा लेने की संभावना है. आज चंबल में न तो दस्यु सुदरियों की चूड़ियां खनकती दिखती हैं और न गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती है. ज़्यादातर डकैत मारे जा चुके हैं. ऐसे में कभी बीहड़ों में गोलियों की तड़तडाहट करने वाले डकैतों द्वारा समाज-सेवा की ओर बढ़ाए जा रहे इस क़दम की सभी लोग सराहना कर रहे हैं. बीहड़ों के आस-पास बसे ग्रामीणों के मुताबिक, चंबल के डाकुओं के भी अपने आदर्श एवं सिद्धांत

> सीमा कहती हैं कि जंगल बहुत ज़रूरी हैं. तरक्की चाहे कितनी भी हो, लेकिन जीवन इन्हीं से है. वह पहले बसाया बीहड़-अब बचाएंगे बीहड़ का नारा देंगी. 13 साल की उम्र में हथियार उठाने वाली सीमा पर लगभग 70 हत्याओं और 150 से ज़्यादा लोगों के अपहरण का आरोप था. 18 मई, 2000 को पुलिस मुठभेड़ में लालाराम के मारे जाने के बाद 2003 में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.

हुआ करते थे. अमीरों को लूटना और ग़रीबों की मदद करना चंबल के डाकुओं का शगल हुआ करता था. ग्रामीणों का मानना है कि अन्याय और शोषण के ख़िलाफ़ विद्रोह करने वाले भले ही पुलिस की फाइलों में डाकू के नाम से जाने जाते हों, लेकिन उनके नेक कामों की वजह से लोग उन्हें सम्मान से बागी ही मानते थे. बागी यानी अन्याय के ख़िलाफ़ बगावत करने वाला.

मानसिंह एवं मलखान सिंह जैसे दस्यु सरगनाओं की गाथाएं और आदर्श की मिसाल यहां के लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनाते हैं. दस्यु मलखान सिंह, जिसे चंबल का राजा माना जाता था, के ख़िलाफ़ 113 मामले हत्या से जुड़े थे. उसने 1982 में आत्मसमर्पण कर दिया. 2003 में वह मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लड़ा. दस्यु मोहर सिंह के ख़िलाफ़ क़रीब 115 मामले दर्ज थे, जिनमें 71 हत्याओं के थे. मोहर सिंह ने आत्मसमर्पण के बाद मेहान गांव नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जनसेवा भी की. दस्यु तहसीलदार सिंह को भी एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया. यह बात दीगर है कि वह चुनाव नहीं जीत सके. फूलन देवी एवं सीमा परिहार ने भी आत्मसमर्पण के बाद राजनीति से नाता जोड़ा. अब ये पूर्व दस्यु अगर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आ रहे हैं, तो इसकी सराहना की जानी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

योग स्वयं से साक्षात्कार कराता है : स्वामी चिदानंद

चौथी दुनिया ब्यूरो

योग, ध्यान एवं अध्यात्म के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले हिमालय की वादियों में पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा. यहां योग दिवस को हरित योग दिवस के रूप में मनाया गया. हज़ारों की संख्या में आए तीर्थ यात्रियों ने स्वामी चिदानंद जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वैदिक मंत्रों के बीच आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया. एक घंटे तक चले योगाभ्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए स्वामी जी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि योग की मदद से उन्होंने पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में जोड़ दिया और वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रबल की. साध्वी सरस्वती ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आज हम पहला विश्व योग दिवस मना रहे हैं. पूरी दुनिया एक साथ योग दिवस मना रही है. यह एकता का पर्व है. हम अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए धन्यवाद करते हैं. इसके लिए हम संयुक्त राष्ट्र और उन सभी देशों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का समर्थन किया. स्वामी जी ने कहा कि योग वह नहीं है, जो आप करते हैं, बल्कि वह है, जो आप स्वयं हैं. योग आपका आपसे साक्षात्कार कराता है.

हिमालय योग की जन्मस्थली है. हिमालय की शांत वादियों में योगाभ्यास मनुष्य के अंदर स्फूर्ति भर देता है. योग नगरी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भारत, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, चिली, कोलंबिया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, इजरायल, लेबनान, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नेपाल, रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड एवं यूक्रेन सहित 30 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लिया. विदेशी साधक यहां योग डे मनाकर काफी खुश थे. गंगा तट पर बड़े उत्साह के साथ योग दिवस की शुरुआत हुई. योग गुरु ने सभी साधकों को योग कलाओं का अभ्यास कराया. योग नगरी के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुके ऋषिकेश में योग दिवस को कुछ अलग अंदाज़ में मनाया गया. इसे हरित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस नाम दिया गया. परमार्थ निकेतन के घाट पर सुबह छह बजे से बड़ी संख्या में देशी-विदेशी योग प्रेमी जुटने लगे और योग की गंगा बहने लगी. 30 देशों के विदेशी साधकों ने भारतीय योग की परंपरा को गंगा के तट पर आत्मसात किया और योग के जरिये स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लिया. साध्वी आभा सरस्वती एवं योगाचार्य इंदु शर्मा ने साधकों को योग के विभिन्न आसन कराए.

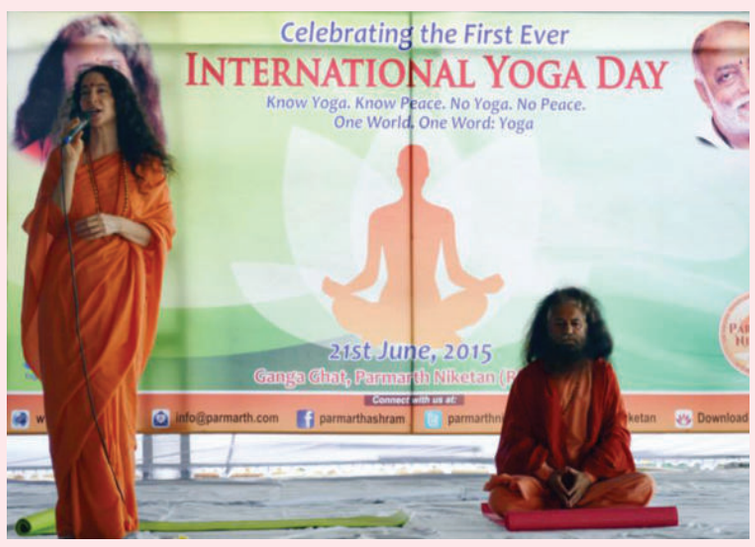

साधकों को संबोधित करते हुए परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज (मुनि जी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि देवात्मा हिमालय के चरण तल में स्थित तीर्थ नगरी ऋषिकेश महर्षि पतंजलि की धरती है. नीलकंठ भगवान ने यहीं पर तप किया. योग विज्ञान की राजधानी कहे जाने वाले ऋषिकेश नगर से योग निकल कर आज दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है. परमार्थ निकेतन के घाट पर सुबह छह बजे से बड़ी संख्या में देशी-विदेशी योग प्रेमी जुटने लगे और योग की गंगा बहने लगी. 30 देशों के विदेशी साधकों ने भारतीय योग की परंपरा को गंगा के तट पर आत्मसात किया और योग के जरिये स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लिया. साध्वी आभा सरस्वती एवं योगाचार्य इंदु शर्मा ने साधकों को योग के विभिन्न आसन कराए.

साधकों को संबोधित करते हुए परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज (मुनि जी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि देवात्मा हिमालय के चरण तल में स्थित तीर्थ नगरी ऋषिकेश महर्षि पतंजलि की धरती है. नीलकंठ भगवान ने यहीं पर तप किया. योग विज्ञान की राजधानी कहे जाने वाले ऋषिकेश नगर से योग निकल कर आज दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है. परमार्थ निकेतन के घाट पर सुबह छह बजे से बड़ी संख्या में देशी-विदेशी योग प्रेमी जुटने लगे और योग की गंगा बहने लगी. 30 देशों के विदेशी साधकों ने भारतीय योग की परंपरा को गंगा के तट पर आत्मसात किया और योग के जरिये स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लिया. साध्वी आभा सरस्वती एवं योगाचार्य इंदु शर्मा ने साधकों को योग के विभिन्न आसन कराए.

साधकों को संबोधित करते हुए परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज (मुनि जी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि देवात्मा हिमालय के चरण तल में स्थित तीर्थ नगरी ऋषिकेश महर्षि पतंजलि की धरती है. नीलकंठ भगवान ने यहीं पर तप किया. योग विज्ञान की राजधानी कहे जाने वाले ऋषिकेश नगर से योग निकल कर आज दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है. इस मौक़े पर साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा कि योग को विश्व योग बनाने में तीर्थ नगरी ऋषिकेश की विशेष भूमिका है. उन्होंने उपस्थित साधकों से योग को अपने दैनिक आचार-व्यवहार में उतारने का आह्वान किया. प्रसिद्ध संत मोरारी बापू ने परमार्थ निकेतन स्वर्गाश्रम में श्रीराम कथा के समापन पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में कहा कि संभवामि युगे-युगे की तरह अब संभवामि योगे-योगे प्रकटा है.

मुरारी बापू ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हैं कि वह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा-संस्कृति के संरक्षण और उसके विस्तार के लिए समर्पित हैं. योग हमारी उसी परंपरा का अमृत है. स्वामी चिदानंद जी ने लोगों को जीवन के सभी उत्सव जन्मदिन, छुट्टियां आदि को हरित उत्सव में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि योग स्थायी जीवन जीने की कुंजी है. हरित जीवन शैली के साथ हम अपने विचारों और कर्मों को संगठित करके प्रकृति के साथ वैश्विक परिवार की सेवा कर सकते हैं. योग, गंगा सेवा, गौ सेवा, ब्रह्म-विद्या की रक्षा और विस्तार केवल किसी वर्ग विशेष की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह धरती के हर मानव का कर्तव्य है. हरित जीवन शैली हमें शांति, प्रेम एवं सद्भाव के साधन के रूप में अपने समुदायों, शहरों, राज्यों और देशों में काम करने की अनुमति देती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

जाति-पार्टी ऊपर मुद्दे नदारद

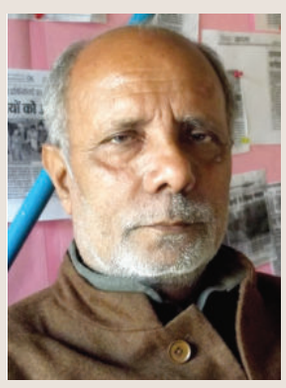

वाल्मीकि कुमार

विधानसभा चुनाव 2015 को लेकर सीतामढ़ी में राजनीतिक माहौल तैयार होने लगा है. लंबे अर्से से चुनावी समर में भाग्य आजमाने का सपना देखने वाले नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के बीच टिकट की दावेदारी को लेकर खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है. जातिवाद के कारण वर्तमान में कोई भी पार्टी अपने बूते चुनावी वैतरणी पार कर पाने की स्थिति में नही है. किसी को जातीय वोटों का गुमान है, तो कोई पार्टी के समर्थन के बल पर ताल ठोंकने को तैयार है. चुनावी समर में अबकी बार पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अपनी दावेदारी को लेकर गतिविधियां बढ़ा दी हैं. अब तक किसी भी दल की ओर से स्थानीय एवं जनहित के मसलों को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने का रास्ता नहीं निकाला गया. सभी जाति और पार्टी के चक्रव्यूह में उलझ कर चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं.

सीतामढ़ी ज़िले की कुल आठ विधानसभा सीटों में से चार सीटों क्रमश: सीतामढ़ी नगर, रीगा, बथनाहा और परिहार पर भाजपा का कब्जा है. इन सीटों पर अब जदयू-राजद गठबंधन की पैनी नज़र है. पिछले चुनाव में जदयू-भाजपा गठबंधन के बूते उक्त सीटें भाजपा के हाथ लगी थीं. अब नए चुनावी गठबंधन में जदयू ने राजद की बदौलत इन सीटों पर कब्जा करने का मंसूबा पाल रखा है. राजद गठबंधन जातिगत आंकड़े जुटाकर उन प्रत्याशियों को इन सीटों पर लड़ाना उचित समझेगा, जो भाजपा के झंडे के डंडे पर तीर अथवा लालटेन लहराने की कूव्वत रखता हो. सीतामढ़ी सीट पर वैश्य बिरादरी के सुनील कुमार पिंटू पिछले चार चुनावों से जीत दर्ज कराते आ रहे हैं. चर्चा है कि अबकी बार वैश्य बिरादरी के ही जदयू के भरत प्रसाद राजद-जदयू गठबंधन से दावेदारी कर रहे हैं. क्षेत्र के जातीय समीकरण पर नज़र रखने वालों का कहना है कि सीतामढ़ी सीट पर कोई ग़ैर भाजपाई वैश्य ही भाजपा के दबदबे को ठिकाने लगा सकता है.

रीगा विधानसभा सीट से वर्तमान में वैश्य बिरादरी के भाजपा विधायक मोती लाल प्रसाद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. अबकी बार उनकी चुनावी नौका डुबोने के लिए दो स्वजातीय महिलाएं चुनावी समर में आने को जी-जान से लगी हुई हैं. चर्चा है कि उनमें एक पूर्व लोजपा विधायक नगीना देवी हैं, तो दूसरी जदयू की किरण गुप्ता. नगीना देवी भाजपा-रालोसपा-लोजपा गठबंधन से, तो किरण जदयू-राजद गठबंधन से चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रही हैं. जदयू-राजद गठबंधन से नागेंद्र प्रसाद सिंह भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं. बथनाहा सुरक्षित सीट से वर्तमान में भाजपा के दिनकर राम विधायक हैं. अबकी बार उनकी सीट पर पूर्व ज़िला पार्षद एवं जदयू नेत्री शोभा देवी और 1974 के आंदोलनकारी राजद नेता मंचित पासवान राजद-जदयू गठबंधन से चुनाव लड़ने का मन बनाए बैठे हैं. जबकि भाजपा से युवा नेता मनोज बैठा टकटकी लगाए हैं. परिहार विधानसभा सीट से भाजपा के राम नरेश प्रसाद यादव विधायक थे. उन्हें पिछले माह 11 अगस्त, 1998 को हुए सीतामढ़ी समाहरणालय गोलीकांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल के सश्रम कारावास की सजा मिली है. नतीजतन, उनकी विधायकी समाप्त हो गई है.

बताया जाता है कि अब उनके स्थान पर उनकी पत्नी गायत्री यादव जनता के बीच न्याय की गुहार लगाकर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं. जबकि राजद-जदयू गठबंधन से प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे पुन: चुनावी समर में उतर सकते हैं. वहीं पूर्व के चुनाव में आजमाइश कर चुके महेंद्र सिंह यादव की पत्नी एवं पूर्व ज़िला पार्षद सरिता यादव बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भाग्य आजमा सकती हैं. शेष तीन सीटों रून्नीसैदपुर, बेलसंड एवं बाजपट्टी पर जदयू की क्रमश: गुड्डी देवी, सुनीता सिंह चौहान एवं डॉ. रंजू गीता विधायक हैं. जबकि सुरसंड से शाहिद अली खान जदयू से हम पार्टी का सफर तय कर चुके हैं. चर्चा है कि रून्नीसैदपुर से राजद-जदयू गठबंधन से पूर्व राजद प्रत्याशी एवं मुखिया राम शत्रुघ्न राय, ज़िला पार्षद संजीत कुमार छोटू, नमोनाथ प्रसाद यादव समेत कई नेता दावेदारी कर रहे हैं. जबकि भाजपा गठबंधन से लोजपा के टिकट पर संतोष झा, आलोक कुमार उर्फ पिंटू चौधरी, त्रिलोकी नाथ झा उर्फ मोहन की दावेदारी की संभावना व्यक्त की जा रही है.

बेलसंड से वर्तमान में जदयू की सुनीता सिंह चौहान विधायक हैं. इस सीट पर भाजपा गठबंधन की पैनी नज़र है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर सीट लोजपा के खाते में आई, तो असीम कुमार सिंह बबलू चुनावी अखाड़े में ताल ठोंक सकते हैं. बाजपट्टी से जदयू की डॉ. रंजू गीता विधायक हैं. उन्हें सीधी टक्कर देने के लिए भाजपा गठबंधन से लोजपा के सवीह अहमद के आने की चर्चा जोरों पर है. सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से अल्पसंख्यक बाहुल्य छह पंचायतों को काटकर बाजपट्टी में मिला दिया गया है. नतीजतन, बाजपट्टी सीट पर अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक साबित हो सकते हैं. चर्चा यह भी है कि अल्पसंख्यक समुदाय से कई अन्य लोग भी टिकट के लिए जोर-आजमाइश में लगे हैं. कुल आठ विधानसभा सीटों पर दावेदारी को लेकर राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन और भाजपा-रालोसपा-लोजपा गठबंधन के संभावित प्रत्याशियों द्वारा क़दमताल शुरू हो चुका है. फिलहाल बहुत सारे संभावित प्रत्याशी पार्टी-गठबंधन की खातिर अपना चेहरा सार्वजनिक करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में टिकट की लालसा अंगड़ाई ले रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र

भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल

राकेश कुमार

पूर्वी चंपारण ज़िले के मोतिहारी एवं पीपरा कोठी प्रखंड को मिलाकर बनी मोतिहारी विधानसभा सीट भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मोतिहारी पूर्वी चंपारण ज़िले एवं संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है. भारत सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह यहां से सांसद हैं. 2005 से 2010 तक के तीन विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा जीतती रही है, लेकिन बदले राजनीतिक माहौल में यह सीट निकालना भाजपा के लिए एक चुनौती जैसा है. इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए जदयू गठबंधन भी पूरी ताकत लगाएगा. भाजपा के प्रमोद कुमार ने फरवरी 2005 एवं अक्टूबर 2005 के चुनाव में राजद प्रत्याशी रमा देवी को हराया था. रमा देवी वर्तमान में शिवहर से भाजपा की सांसद हैं. 2010 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद कुमार ने राजद के राजेश कुमार गुप्ता को परास्त किया. तीनों चुनाव में भाजपा और जदयू साथ थे, लेकिन इस बार स्थितियां भिन्न हैं. भाजपा और जदयू आमने-सामने हैं.

क्षेत्र में कलवार (जायसवाल) मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है. कलवार भाजपा के परंपरागत वोट नहीं रहे. इसीलिए 1985 से 1995 तक यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के त्रिवेणी तिवारी चुने गए. तीनों ही बार भाजपा के लक्ष्मण प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा. 2005 और 2010 के चुनाव में जदयू के साथ होने एवं तत्कालीन घटनाक्रम का फ़ायदा भाजपा को मिला. 2015 का विधानसभा चुनाव कई कारणों से दिलचस्प होगा. इस बार पार्टियों की स्थिति भिन्न है. गठबंधन का रूप बदल गया है. भाजपा के साथ लोजपा है, तो जदयू ने राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया है. गठबंधन के कारण भावी प्रत्याशियों में टिकट को लेकर संशय बना हुआ है. जदयू-राजद गठबंधन के तहत मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के राजद में जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इस सीट पर पिछले कई चुनावों में राजद ही दूसरे स्थान पर रहा है. मोतिहारी सीट से राजद के कई नेता भाग्य आजमाना चाहते हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके विनोद कुमार श्रीवास्तव विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवारी के दावेदार हैं. मोतिहारी लोकसभा चुनाव में वह दूसरे स्थान पर थे. मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें 45,000 से ज़्यादा वोट मिले थे. राजद नेताओं का मानना है कि ये वोट मोदी लहर के दौरान आए थे. इस बार जदयू एवं कांग्रेस का साथ भी है. मोतिहारी में कायस्थों के समर्थन के साथ-साथ राजद के परंपरागत यादव-मुस्लिम वोट भी मिलेंगे. विनोद श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर आला कमान का आदेश मिला, तो चुनाव लड़ूंगा.

मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट के एक अन्य प्रबल दावेदार ई. मनोज कुमार गुप्ता कहते हैं कि वैश्य-कलवार बाहुल्य इस क्षेत्र में कलवार उम्मीदवार ही विजय दिला सकता है. मनोज टिकट और जीत के प्रति आश्वस्त हैं. मनोज कलवार हैं. वह जातीय वोटों के साथ यादव एवं मुस्लिम वोटों को अपना मान रहे हैं. बकौल मनोज, उच्च वर्ग और प्रबुद्ध जनों में भी उनकी अच्छी पकड़ है. वहीं आम जनता भी बदलाव चाहती है. राजद के प्रदेश महासचिव मुख्तार आलम ने स्पष्ट कहा कि किसी भी बाहरी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया जाएगा. ज़िला पार्षद गुलशन बेगम एवं पीपरा कोठी के प्रखंड प्रमुख ने भी बाहरी नेताओं के विरोध का ऐलान करते हुए स्थानीय नेता के समर्थन की बात कही. मोतिहारी में निषादों की संख्या भी निर्णायक है. सहनी समाज से ओम प्रकाश सहनी भी जदयू के टिकट के दावेदार हैं. गत लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने लड़ने का मन बनाया था, लेकिन टिकट नहीं मिल सका था. तब उन्हें विधानसभा चुनाव में स्थान देने का आश्वासन मिला था. वह सहनी समाज के साथ गठबंधन के वोटों की बदौलत जीत का दावा करते हैं.

जदयू के टिकट के लिए युवा जदयू के प्रदेश महासचिव एवं ज़िला प्रवक्ता विशाल कुमार शाह दावेदारी कर रहे हैं. शाह नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय विश्वम्भर नाथ शाह के पुत्र हैं और कलवार हैं. सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने के कारण सभी वर्गों में उनकी पकड़ है. नगर अध्यक्ष कृष्णा कश्यप के अनुसार, यदि पार्टी विशाल शाह को टिकट देती है, तो जीत सुनिश्चित है. जदयू हर मोर्चे पर पूरी तैयारी कर रहा है. इसी के तहत प्रमोद सिन्हा को हटाकर प्रो. दिनेश चंद्र प्रसाद को दोबारा ज़िलाध्यक्ष बनाया गया है. कांग्रेस भी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है. कांग्रेस के ज़िलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल के अनुसार, सभी सीटों पर तैयारी चल रही है और वर्तमान गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव के लिए है. कांग्रेस से टिकट की दावेदारी विजय कुमार जायसवाल उर्फ मुनमुन कर रहे हैं. वह वर्तमान में ज़िला उपाध्यक्ष हैं. आम आदमी पार्टी के ज्ञानेश्वर गौतम उर्फ मुकेश चौधरी भी चुनावी समर में कूदने की तैयारी में हैं. आम आदमी पार्टी

बिहार में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. बकौल चौधरी, लोगों का मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने आम आदमी को छला है. आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में दिखा दिया कि यदि इच्छाशक्ति हो, तो समस्याओं का समाधान हो सकता है. उधर भाजपा नेत्री निर्मला सहनी ने आवाज़ बुलंद की है कि पार्टी महिलाओं को भी मौक़ा दे. वह वर्तमान में भाजपा की ज़िला मंत्री हैं और हरसिद्धि की ज़िला पार्षद रह चुकी हैं. अगर पार्टी ने हरी झंडी दी, तो वह चुनाव लड़ सकती हैं. वर्तमान भाजपा विधायक प्रमोद कुमार टिकट और जीत को लेकर आश्वस्त हैं. उनका विश्वास है कि उनके द्वारा कराए गए कार्यों के कारण जनता उनका समर्थन करेगी. कुल मिलाकर सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं. उनके दावे कितने सही साबित होंगे, यह तो समय बताएगा, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ मसले ऐसे हैं, जिन्होंने शासन-प्रशासन से आम लोगों का विश्वास ख़त्म कर दिया है. केंद्रीय विश्वविद्यालय के आज तक न खुलने और मोतिहारी चीनी मिल की बंदी से जनता का भरोसा काफी हद तक डिगा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

खादी-खाकी-सफेदपोश गठजोड़ का कारनामा

सरकार को लगाई 432 करोड़ रुपये की चपत

सुनील सौरभ

देश के बहुचर्चित जीटी रोड पर ग़ैर क़ानूनी तरीके से ओवर लोडेड ट्रकों को पार कराकर एक साल में क़रीब 432 करोड़ रुपये का चूना सरकार को लगाया गया है. खाकी-खादी-सफेदपोश गठजोड़ बिहार में जीटी रोड पर स्थित समेकित जांच चौकी के अधिकारियों को ओवर लोडेड ट्रकों को बिना जांच किए पार कराने के लिए विवश करता रहा. लेकिन, आठ मई, 2015 को जब गया में मगध क्षेत्र के डीआईजी पद पर पदस्थापित शालिन ने जीटी रोड पर एंट्री माफियाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की, तो बिहार-झारखंड के राजनीतिक-प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मच गया. पता चला कि एंट्री माफिया के साथ झारखंड के चतरा के एक पूर्व सांसद और बिहार पुलिस मुख्यालय के एक एडीजी बाबा की मिलीभगत है. इस राज के खुलासे के बाद मात्र 46 दिनों में ही शालिन का तबादला पटना प्रक्षेत्र के डीआईजी पद पर हो जाना चर्चा का विषय बन गया है.

शालिन ने मगध क्षेत्र में संगठित अपराध के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की. इसी क्रम में पता चला कि जीटी रोड पर गया ज़िले के डोभी में स्थित समेकित जांच चौकी से ओवर लोडेड वाहनों को अवैध रूप से पार कराकर सरकारी राजस्व को बड़े पैमाने पर चूना लगाने का मामला चल रहा है. डीआईजी शालिन ने इस पर कार्रवाई शुरू की, तो सरकारी राजस्व में बढ़ोत्तरी होने लगी. फर्जी कागजात के सहारे जांच चौकी से वाहन पार कराने का मामला भी सामने आया. एक दर्जन से अधिक एंट्री माफिया पकड़े गए, जिनसे पूछताछ में पता चला कि एंट्री माफियाओं का सरगना झारखंड के चतरा निवासी राजू खान उर्फ राजू इराकी उर्फ औरंगजेब है. बताया जाता है कि राजू राजनीतिक-प्रशासनिक संरक्षण पाकर कुछ ही वर्षों में मामूली आदमी से करोड़ों रुपये की संपत्ति का मालिक बन बैठा. जीटी रोड पर उसके एक इशारे पर थाने से लेकर तमाम सरकारी महकमे के अधिकारी नाचते नज़र आते थे. डीआईजी शालिन ने जब एंट्री माफिया पर शिकंजा कसा, तो पता चला कि सिर्फ़ डोभी चेकपोस्ट से ही 432 करोड़ रुपये की राजस्व हानि सरकार को प्रतिवर्ष हो रही है. जब राजू खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि निचले स्तर के दर्जनों पदाधिकारी राजू के पे-रोल पर रहते थे.

एंट्री माफियाओं के सरगना राजू खान और पूर्व सांसद के बीच दोस्ती उस समय हुई थी, जब बिहार पुलिस मुख्यालय में आज एडीजी पद पर तैनात बाबा चतरा में पदस्थापित थे. इस तिकड़ी ने सरकार को प्रतिवर्ष साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का चूना लगाया. पिछले कई वर्षों से यह खेल जारी था. डीआईजी शालिन ने राजू खान पर कार्रवाई करते हुए उसके सारे ठिकानों पर छापेमारी और कुर्की-जब्ती भी की, लेकिन राजू खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका. बीते 20 जून को डीआईजी शालिन का तबादला पटना प्रक्षेत्र के डीआईजी पद पर हो गया. लोगों का मानना है कि एंट्री माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान बिहार पुलिस मख्यालय का नाम बदनाम होने और एक पूर्व सांसद का नाम सामने आने के बाद राज्य सरकार ने दबाववश शालिन को मगध के डीआईजी पद से हटा दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

ज़हरीली शराब का कहर

प्याले से निकली मौत

जनवरी 2012 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के मइलावरम एवं पोरत्रागनर इलाके में ज़हरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गई. नवंबर-दिसंबर 2012 में बिहार के पटना में 12, गया में 13 और आरा ज़िले में 29 लोगों ने ज़हरीली शराब पीकर अपनी जान गंवाई. राज्य सरकारों के भी अपने-अपने तर्क हैं. किसी को शराब पर प्रतिबंध लगाने पर राजस्व का घाटा दिखाई देता है, तो किसी का मानना है कि ऐसा करने से अवैध शराब का कारोबार ज़ोर पकड़ लेगा. जबकि इसके उलट सच्चाई यह है कि ज़हरीली शराब अक्सर सरकारी ठेकों से बिकती पाई जाती है. राज्य अथवा ज़िला कोई भी हो, ज़हरीली शराब के शिकार हमेशा निम्नवर्गीय, अल्प-आय वाले लोग होते हैं.

महेंद्र अवधेश

मुंबई में ज़हरीली शराब ने एक बार फिर कहर बरपा दिया. बीते 17–18 जून को मालवणी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नगर झोंपड़पट्टी स्थित एक लोकल बार से खरीदी गई शराब पीने से 104 लोगों की मौत हो गई, जबकि सवा सौ से भी ज़्यादा लोगों को गंभीरावस्था में विभिन्न अस्पतालों में दाखिल कराया गया. पुलिस ने उक्त शराब की आपूर्ति करने वाले राजू हनुमंता पास्कर उर्फ लंगड़ा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इस हादसे में राठौरी गांव और अंबुज वाड़ी के लोग बड़ी संख्या में शिकार बने. मरने वालों में ज़्यादातर दिहाड़ी मज़दूर एवं ऑटो रिक्शा चालक हैं, जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात के बताए जाते हैं. लापरवाही के आरोप में थानेदार समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मामले की शीघ्र व निष्पक्ष जांच के आदेश दिए, वहीं आबकारी विभाग ने भी अपने अधिकारियों–कर्मचारियों के ख़िलाफ़ जांच बैठा दी. हाल के वर्षों में मुंबई में यह दूसरी बड़ी घटना है. ग़ौरतलब है कि 2004 में भी मुंबई के विक्रोली इलाके में ज़हरीली शराब पीने से 87 लोगों की मौत हो गई थी.

सिर्फ़ मुंबई नहीं, देश के अधिकांश हिस्सों की यही हालत है. हर जगह ज़हरीली शराब के कारोबारी इंसानों की जान से खेल रहे हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं ओडिसा में हर वर्ष जहरीली–नकली शराब के सेवन से बड़ी संख्या में लोग अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं. गुजरात, मिजोरम एवं नगालैंड, जहां शराब पर पूर्ण पाबंदी है, को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में शराब माफिया का एकछत्र राज है. पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान से शराब तस्करी करके दिल्ली समेत देश के बाकी हिस्सों में पहुंचना अब आम बात हो गई है. ज़हरीली, नकली या दीगर राज्यों से तस्करी करके लाई गई शराब की बिक्री का काम करने वालों को इलाकाई पुलिस और आबकारी विभाग की स्थानीय इकाई का संरक्षण परोक्षत: हासिल रहता है. बीते तीन जून को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की शहर कोतवाली अंतर्गत जुराखन खेड़ा में ज़हरीली शराब पीने से दो सगे भाइयों समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी. शासन ने ज़िला आबकारी अधिकारी, पुलिस चौकी प्रभारी एवं सिपाहियों समेत दस लोगों को निलंबित कर दिया, जबकि शहर कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया. ग़ौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में 12–13 जनवरी को उन्नाव और सूबे की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में ज़हरीली शराब पीने से क़रीब तीन दर्जन लोगों की मौत हो गई थी. तब भी शासन ने आबकारी विभाग और पुलिस के क़रीब डेढ़ दर्जन अधिकारियों–कर्मचारियों का निलंबन, विभिन्न ज़िलों में छापेमारी और कुछेक हज़ार लीटर कच्ची–अवैध शराब की बरामदगी, जांच–पड़ताल करके अपना मुंह छिपाने–नाक बचाने की कोशिश की थी.

यह हादसा इस बार सामान्य दिनों में हुआ है. ऐसी घटनाएं अक्सर त्योहारों जैसे होली, दीवाली, क्रिसमस और नया साल आदि आने के एक–दो दिनों बाद सुनने को मिलती हैं. बीते वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कठघर पुलिस थाना परिसर से ही शराब बेचे जाने का मामला सामने आया था. तब एसएसपी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कठघर ने थाना परिसर स्थित ड्राइवर के कमरे पर छापा मारकर कई पेटी हरियाणा मार्का शराब बरामद की. इससे कुछ दिनों पहले चंदौसी–मुरादाबाद के बनियाठेर थाना क्षेत्र के कस्बा नरौली के मुहल्ला मंगलवाला अड्डा में पिता–पुत्र और मूढ़ापांडे इलाके के खाईखेड़ा मुहल्ले में एक दिहाड़ी मज़दूर को ज़हरीली शराब के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी. 2014 में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गीता कालोनी इलाके में पुलिस ने सोनीपत (हरियाणा) से लाई गई शराब की एक बड़ी खेप समेत एक युवक को गिरफ्तार किया था. दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान से तस्करी करके शराब लाने का धंधा अर्से से जारी है. अवैध, ज़हरीली, नकली शराब का कारोबार देश के विभिन्न हिस्सों में धड़ल्ले से चल रहा है. अवैध शराब का कारोबार न सिर्फ़ अनगिनत जानें लेता है, बल्कि सरकार को भी राजस्व का नुक़सान पहुंचाता है.

यदि ग़ैर सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करें, तो अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के भीतर क़रीब छह–सात सौ लोग ज़हरीली शराब के सेवन के चलते अपने प्राण गंवा बैठे. ऐसे अधिकतर मामलों में तो स्थानीय प्रशासन अपने स्तर से आर्थिक सहायता देकर अथवा दबाव बनाकर इस तरह हुई मौतों को मीडिया की नज़र से बचा लेने में कामयाब हो जाता है. राज्य के आजमगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बहराइच, गाजीपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर एवं जालौन में अवैध शराब का कारोबार होली–दीवाली जैसे त्योहारों के समय चरम पर होता है. नतीजतन, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं अथवा आंख की रोशनी गंवा बैठते हैं. कानपुर शहर में कुछ ठेके ऐसे हैं, जहां चौबीसों घंटे शराब उपलब्ध रहती है. सरकारी बंदी के बावजूद पुलिस की कृपा से वहां कोई पाबंदी या रोक–टोक नहीं है. आबादी के बीच मौजूद उक्त ठेके समाज के लिए नासूर हैं, लेकिन प्रशासन को परवाह इसलिए नहीं है, क्योंकि नज़राने का मामला थोड़ा संवेदनशील होता है! जबकि नियम यह है कि घनी आबादी के बीच, स्कूल–कॉलेज एवं धार्मिक स्थल के नज़दीक शराब ठेके नहीं होने चाहिए, लेकिन इस प्रावधान का पालन शायद ही कभी होता हो!

आबकारी विभाग एवं पुलिस की भूमिका मात्र इतनी रहती है कि वे ऐसी कोई घटना होने के बाद ही छापेमारी और गिरफ्तारी का काम अंजाम देते हैं. कई बार तो सरकारी ठेकों से ज़हरीली शराब बेचे जाने की घटनाएं सामने आई हैं. 2011 में होली के अवसर पर गाजीपुर में ज़हरीली शराब पीकर जान गंवाने वाले दो युवकों के कब्जे से मिली बोतल पर लगे रैपर पर मार्का मिस इंडिया, निर्माता यूबायो केमिकल्स अलीगढ़ दर्ज पाया गया था. त्योहारों पर बिकने वाली शराब पर अक्सर बैच नंबर तक लिखा नहीं होता. सवाल यह है कि सरकारी ठेकों पर ज़हरीली शराब आती कैसे है? क्या सरकारी ठेकेदार ज़हरीली शराब बनवाते हैं या ज़हरीली शराब बनाने वालों से उनकी साठगांठ है? अवैध शराब भट्ठियां किसके संरक्षण में चलती हैं? जानकारों का मानना है कि शराब ठेकेदार एवं सिंडिकेट अधिक लाभ के लालच में दूसरे राज्यों से तस्करी करके लाई गई शराब अवैध रूप से बेचते हैं और जब तस्करी की सस्ती शराब कम पड़ जाती है, तो वे कच्ची एवं ज़हरीली शराब बेचने से भी गुरेज नहीं करते. 2011 में आजमगढ़ में भी मिलावटी शराब पीने से 22 लोग मारे गए थे.

जनवरी 2012 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के मइलावरम एवं पोरत्रागनर इलाके में ज़हरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गई. नवंबर–दिसंबर 2012 में बिहार के पटना में 12, गया में 13 और आरा ज़िले में 29 लोगों ने ज़हरीली शराब पीकर अपनी जान गंवाई. राज्य सरकारों के भी अपने–अपने तर्क हैं. किसी को शराब पर प्रतिबंध लगाने पर राजस्व का घाटा दिखाई देता है, तो किसी का मानना है कि ऐसा करने से अवैध शराब का कारोबार ज़ोर पकड़ लेगा. जबकि इसके उलट सच्चाई यह है कि ज़हरीली शराब अक्सर सरकारी ठेकों से बिकती पाई जाती है. राज्य अथवा ज़िला कोई भी हो, ज़हरीली शराब के शिकार हमेशा निम्नवर्गीय, अल्प–आय वाले लोग होते हैं. आंध्र प्रदेश की घटना भी जनजातीय इलाकों में हुई थी. बिहार में भी मज़दूर, रिक्शा चालक, फेरी–खोमचे वाले ही जानलेवा शराब के शिकार बने. फरवरी 2012 में ओडिसा के कटक ज़िले में ज़हरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत हो गई और पांच दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार हुए. इसी तरह 2009 में खुदरा ज़िले में 33 और 1992 में कटक में 200 लोग ज़हरीली शराब के शिकार बनकर अपनी जान गंवा बैठे थे. दिसंबर 2011 में पश्चिम बंगाल में 171, फरवरी 2010 में तमिलनाडु में 10 और जुलाई 2009 में गुजरात में 107 लोग मिलावटी–ज़हरीली शराब पीने से मारे गए थे.

उक्त घटनाएं बताती हैं कि तमाम नियम–क़ानून व प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद अवैध शराब बनाने एवं बेचने वालों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और ग़रीब–अल्प आयवर्गीय जनता क्षणिक सुख की खातिर किस तरह मौत के मुंह में जाने को विवश है. देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों एवं स्थानीय प्रशासन की नींद तभी खुलती है, जब ज़हरीली शराब पीकर लोग मरने लगते हैं. तब भी उनकी भूमिका सिर्फ़ सख्त कार्रवाई के वादे और मुआवजा वितरण से आगे नहीं बढ़ पाती. देश के लगभग हर हिस्से में आबकारी विभाग की इकाइयां हैं और मद्य निषेध विभाग की भी. दोनों ही सक्रिय हैं, उनका लंबा–चौड़ा अमला है, मोटी–मोटी तनख्वाहें हैं, सुविधा शुल्क तो बहती हुई गंगा है. लेकिन, बाहर कौन से नियम–प्रावधान टूट रहे हैं, इससे उन्हें कुछ भी लेना–देना नहीं है. शासन–प्रशासन भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आने के बाद अपने चेहरे पर पड़ी ओढ़नी हटाता है, ज़हरीली–नकली शराब से सावधान करता है, अख़बारों–टीवी में विज्ञापन देता है–शराब पीजिए, लेकिन केवल सरकारी ठेकों से खरीद कर, इधर–उधर से नहीं. फिर भी ज़हरीली–नकली शराब का कहर मौत बनकर लोगों पर टूट रहा है.■

mahendra.awdhesh@gmail.com

होम डिलीवरी और उधारी की सुविधा

राजू लंगड़ा के इस काले धंधे की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उसके द्वारा अपने ग्राहकों को शराब की होम डिलीवरी और उधारी की सुविधा थी. जानकारी के मुताबिक, फोन पर ऑर्डर देने पर लंगड़े, उसकी पत्नी या फिर किसी अन्य द्वारा संबंधित ग्राहक तक शराब पहुंचा दी जाती थी. जिन ग्राहकों के पास पैसे नहीं होते थे, वे दो–चार दिनों में अपनी सुविधानुसार भुगतान कर देते थे. लंगड़े का कारोबार इसलिए भी चल निकला था, क्योंकि लाइसेंसी शराब की दुकानों पर आबकारी कर काफी बढ़ गया है. साथ ही उसे इलाकाई पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारियों का संरक्षण हासिल बताया जाता है. लंगड़े को उक्त नकली–ज़हरीली शराब की आपूर्ति संजय गांधी राष्ट्रीय इद्यान, वसई और विरार के दूरदराज के इलाकों से होती थी. राजू लंगड़े का यह धंधा पिछले दस वर्षों से बेरोक–टोक चल रहा था. पुलिस आयुक्त राकेश मारिया भी आश्चर्य जताते हैं कि इस अवधि में लंगड़े के ख़िलाफ़ एक भी मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ?

यूं तैयार होता है मौत का सामान

नकली–ज़हरीली शराब कई तरीकों से बनाई जाती है. महुआ और गुड़ के सीरे से बनाई गई शराब में नशा पैदा करने के लिए यूरिया खाद और ऑक्सीटोन भी मिलाया जाता है. ऑक्सीटोन वह इंजेक्शन है, जो गाय–भैंसों से दूध आसानी से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो प्रतिबंधित है. इसके अलावा कपड़ा धोने वाले सस्ते सर्फ (वॉशिंग पाउडर), मिथाइल एल्कोहल और विभिन्न तरह के घातक रसायनों का प्रयोग भी किया जाता है. ऐसी शराब जानलेवा होती है. अगर पीने वाला किसी तरह बच भी जाए, तो वह विभिन्न असाध्य बीमारियों का शिकार हो जाता है. मिथाइल एल्कोहल बगैर लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन मौत के सौदागरों के लिए इसे हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है. जानकारों का मानना है कि एक लीटर रसायन से सौ–सवा सौ लीटर शराब तैयार की जा सकती है.

यह हादसा इस बार सामान्य दिनों में हुआ है. ऐसी घटनाएं अक्सर त्योहारों जैसे होली, दीवाली, क्रिसमस और नया साल आदि आने के एक–दो दिनों बाद सुनने को मिलती हैं. बीते वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कठघर पुलिस थाना परिसर से ही शराब बेचे जाने का मामला सामने आया था. तब एसएसपी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कठघर ने थाना परिसर स्थित ड्राइवर के कमरे पर छापा मारकर कई पेटी हरियाणा मार्का शराब बरामद की.

चौथी दुनिया परिवार की ओर से नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में 29 जून की शाम को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जिन गणमान्य लोगों ने शिरकत की, उनमें विदेश राज्य मंत्री जनरल(रिटा.) वी के सिंह, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुबोध कांत सहाय, मणिशंकर अय्यर, मीम अफजल, सलीम शेरवानी, सुनील शास्त्री, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैय्यद सिब्ते रज़ी, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रो. जे एस राजपूत, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व उप-कुलपति शाहिद मेंहदी, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, विनोद शर्मा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे रूशैद प्रमुख थे. भारत सरकार के कई सचिव स्तर के अधिकारियों, विभिन्न दरगाहों के प्रतिनिधियों, इमामों और बुद्धिजीवियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस विशेष मौक़े को हमारे **फोटो जर्नलिस्ट प्रभात पांडेय** ने अपने कैमरे की नज़र से कुछ यूं देखा...

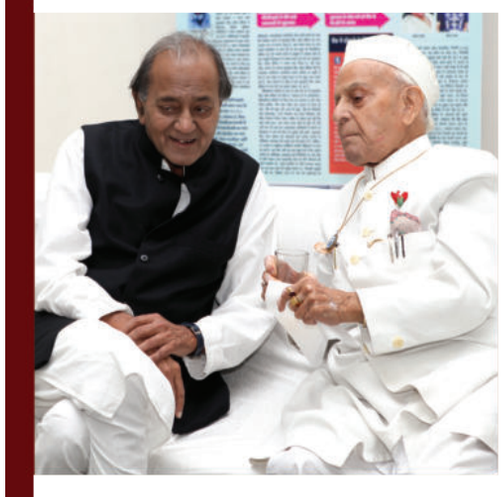

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

दिल्ली सरकार की तरह हाल है. दिल्ली पूर्ण राज्य भी नहीं है. यह एक केंद्र शासित प्रदेश है. लेकिन हर रोज यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं और जनता द्वारा निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच बहस जारी है. यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है. भाजपा और आरएसएस के भीतर से भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि केवल तीन-चार लोगों को ही पता होता है कि क्या हो रहा है. मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा परिवर्तन आवश्यक है. भारत जैसे विशाल देश में यदि किसी चीज को सफल करना है, जहां विकास जैसा काम बहुत धीमी गति से होता है, अगर उसे तीन या चार लोगों के बंद समूह में रखा जाता है, तो अपेक्षित परिणाम नहीं आएगा.

विपक्ष को ज़िम्मेदार और सरकार को उत्तरदायी होना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी धूमधाम के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की. असल में मनमोहन सिंह सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ पूरे देश को कनेक्ट करने के लिए क़दम उठाए थे और अब यह उसी का एक विस्तार है, जिसे एक फैंसी नाम डिजिटल इंडिया दिया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2019 तक 2,50,000 गांवों को इससे जोड़ दिया जाएगा. तकनीक का हमेशा स्वागत हुआ है, जैसा हमने इंटरनेट और सेल फोन आदि के मामले में देखा है. लेकिन सवाल यह नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि प्राथमिकताएं क्या हैं? यह सरकार 13-14 महीने पहले सत्ता में आई. महंगाई अभी भी एक समस्या है. हम रोज छोटी-छोटी ऐसी राजनीतिक ख़बरें पढ़ रहे हैं, जो बताती हैं कि राजनीतिक प्रबंधन अभी भी अयोग्य है.

दिल्ली सरकार की तरह हाल है. दिल्ली पूर्ण राज्य भी नहीं है. यह एक केंद्र शासित प्रदेश है. लेकिन हर रोज यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं और जनता द्वारा निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच बहस जारी है. यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है. भाजपा और आरएसएस के भीतर से भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि केवल तीन-चार लोगों को ही पता होता है कि क्या हो रहा है. मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा परिवर्तन आवश्यक है. भारत जैसे विशाल देश में यदि किसी चीज को सफल करना है, जहां विकास जैसा काम बहुत धीमी गति से होता है, अगर उसे तीन या चार लोगों के बंद समूह में रखा जाता है, तो अपेक्षित परिणाम नहीं आएगा. अभी यहां देखना है कि डिजिटल इंडिया क्या करता है, लेकिन ब्रॉडबैंड नेटवर्क की गति यहां बहुत धीमी है. कांग्रेस के समय राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नामक एक कंपनी लाई गई थी. वास्तव में उसका क्या उद्देश्य था, कहां तक उस पर काम हुआ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. जब तक आपको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नहीं मिलता, तब तक उपयोगकर्ताओं के बीच कोई उत्साह नहीं होगा. धीमी गति वाले लोग पहले से ही खराब नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में अलग समस्या है. वहां बिजली नहीं है. यदि एक दिन में बिजली कुछ घंटे भी न रहे, तो कैसे ये उपकरण या तकनीक काम करेंगे? इसलिए प्राथमिकता तो बिजली है. सही बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिजली को लेकर बड़ा कार्यक्रम है और इस कमी को दूर किया जाएगा. लेकिन, यहां हो उल्टा रहा है. मैं समझता हूं कि यही वक्त है, जब प्रधानमंत्री साप्ताहिक बैठक करके बिजली और अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की प्रगति पर बात करें, रिपोर्ट लें.

एक अन्य कहानी है ललितगेट (ललित मोदी प्रकरण) की. राजस्थान में सबको मालूम है कि 2003-2008 में, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं, तब सरकार के अधिकारी भूमि सौदों से जुड़े मामलों में ललित मोदी से आदेश लेते थे. तब यह एक बहुत बड़ा घोटाला था, लेकिन उस समय भाजपा या आरएसएस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न अशोक गहलोत सरकार ने सत्ता में आने के बाद कोई कार्रवाई की. खैर, राजे अब दोबारा सत्ता में आई हैं. उनके और ललित मोदी के बीच अब तल्खी है. यह तल्खी किस बात को लेकर है, नहीं मालूम और ललित मोदी क्या खेल खेलना चाहते हैं, इसका भी पता नहीं है. मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ललित मोदी निजी तौर पर लोगों से कहते रहे हैं कि उनकी सारी समस्याएं कांग्रेस, शशि थरूर और सोनिया गांधी की वजह से हैं. अब भाजपा सत्ता में है, तो उनकी मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाना चाहिए, लेकिन अब वे हर रोज किसी न किसी भाजपा नेता का नाम लेकर पार्टी को मुसीबत में डाल रहे हैं. मैं क्रिकेट प्रशासन से जुड़ा रहा हूं. मैं जानता हूं कि उनकी भूमिका कैसी थी, अच्छी, बुरी या सबसे अलग. लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वह कोई हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं? ललित मोदी भारत में अपनी सभी कंपनियों से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, क्योंकि उनके पिता एक भारतीय व्यापारी हैं, जो सरकार के ख़िलाफ़ नहीं उतर सकते और वह भारतीय कॉरपोरेट मानदंडों के अनुसार अपनी कंपनियां चलाते हैं. इसलिए वह इस राजनीति और क्रिकेट में उलझना नहीं चाहते. लेकिन वास्तव में लंदन से ललित मोदी करना क्या चाहते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? खैर, उनका उद्देश्य जो भी हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि भारतीय मीडिया बहुत बुद्धिमानी भरा काम कर रहा है. उन्हें ज़रूरत से अधिक महत्व देकर आप भारतीय राजनेताओं की छवि खराब कर रहे हैं. सुषमा स्वराज ने क्या किया? उन्होंने ललित मोदी को अपनी पत्नी को देखने के लिए पुर्तगाल जाने में मदद की. इसके बाद मोदी लंदन वापस आ गए. बात यही ख़त्म हो जाती है. अब सुषमा स्वराज को क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उनकी ईमानदारी आदि एक सवाल है, लेकिन यह सब इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, जिसे इतना खींचा जाए.

इसी तरह वसुंधरा राजे ने एक पत्र लिखा और उन्होंने यह कहकर मूर्खता कर दी कि इस पत्र को भारत सरकार से छिपाकर रखा जाए. उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा पत्र उन्होंने क्यों लिखा, मुझे नहीं मालूम. उन्होंने यह सिफारिश की कि ललित मोदी को वहां रहने दिया जाए. तब वह मुख्यमंत्री नहीं थीं. यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसके परिणाम बड़े हो सकते हैं. हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि ललित मोदी के सुषमा की बेटी, सुषमा के पति के साथ क्या संबंध हैं? इन रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं. यह स्वस्थ राजनीति के लिए ठीक नहीं है. प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सब रोकना चाहिए. प्रवर्तन निदेशालय कई वर्षों से इस मामले की जांच कर रहा है. उसने अब तक क्या किया है? मोदी को वापस क्यों नहीं लाया जा सका? मोदी को वापस लाने के लिए उचित क़दम क्यों नहीं उठाए जाते? अगर दो साल पहले यह काम कर लिया गया होता, तो यह मामला उठता ही नहीं. सब कुछ संदिग्ध दिखता रहा है. प्रधानमंत्री हमेशा एक अच्छे शासन पर जोर देते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि हर काम में पारदर्शिता रहे. कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे. आप यह नहीं कह सकते कि हमने मानवता के आधार पर मदद की और अब क़ानूनी बुनियाद पर उन्हें वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं. मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को राजनीतिक और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में इस सब पर चर्चा करके इस विवाद को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए.

संसद सत्र आने वाला है. कांग्रेस ने साफ़ कर दिया है कि यदि इन दोनों महिलाओं का इस्तीफ़ा नहीं होता है, तो वह संसद नहीं चलने देगी. यह अपने आप में अलोकतांत्रिक है. इस मामले का संसद की कार्यवाही से क्या संबंध हो सकता है? भाजपा ने भी पहले ऐसा किया है. कांग्रेस ने भी पहले ऐसा किया है, जब वह जॉर्ज फर्नांडीस का सामना नहीं करना चाहती थी. यानी विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने कांग्रेस के साथ जो किया, अब वही उसे वापस मिलने वाला है. यदि जीएसटी विधेयक को पारित किया जाना है, तो ठीक है कि कांग्रेस उस बिल का विरोध उसके गुण-दोष के आधार पर करे, न कि उसे विदेश मंत्री के इस्तीफ़े से जोड़े. हम संसद नहीं चलने देंगे, यह कहना मुझे लगता है कि बहुत दुःखद बात है. लोकतंत्र को फलने-फूलने का मौक़ा मिलना चाहिए, हर पक्ष की बात सुनी जानी चाहिए और सर्वसम्मति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पहले से यह कहना कि हम सत्र नहीं चलने देंगे, ग़लत है. मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस को ऐसी सलाह कौन दे रहा है. कांग्रेस भारत की एक बहुत पुरानी पार्टी है. उसने लंबे समय तक शासन किया है. उसे शासन की सीमा रेखा मालूम है.

संसद सत्र आने वाला है. कांग्रेस ने साफ़ कर दिया है कि यदि इन दोनों महिलाओं का इस्तीफ़ा नहीं होता है, तो वह संसद नहीं चलने देगी. यह अपने आप में अलोकतांत्रिक है. इस मामले का संसद की कार्यवाही से क्या संबंध हो सकता है? भाजपा ने भी पहले ऐसा किया है. कांग्रेस ने भी पहले ऐसा किया है, जब वह जॉर्ज फर्नांडीस का सामना नहीं करना चाहती थी. यानी विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने कांग्रेस के साथ जो किया, अब वही उसे वापस मिलने वाला है.

भाजपा और नरेंद्र मोदी को उनके वैसे वादों के लिए माफ़ किया जा सकता है, जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है. संसदीय लोकतंत्र के मानकों के हिसाब से कांग्रेस को एक स्पष्ट लाइन लेनी चाहिए. इसके बाद सरकार पर निर्भर करता है कि वह संसद चलाना चाहती है या नहीं. किसी भी लोकतंत्र में संसद को चलाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है. नियम यह है कि विपक्ष को ज़िम्मेदार होना चाहिए और सरकार को उत्तरदायी. अगर सरकार उत्तरदायी नहीं है, तो विपक्ष भी अपनी ज़िम्मेदारी की भावना खो देता है. जितनी जल्दी हम ब्रिटेन से सीखे गए संसदीय नियमों की ओर लौट जाएं, उतना ही अच्छा होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पुलिस अधिकारी को किसने गोली मारी-2

समुचित जांच-पड़ताल के बगैर आरोपी को क्लीन चिट

राजीव वर्मा 1954 में चंडीगढ़ में पैदा हुए, वहीं से उन्होंने एमए पास किया तथा नवंबर 1975 से भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें देहरादून का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया. बाद में वह आगरा में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के रूप में रहे. आगरा के बाद उनकी नियुक्ति पीएसी की 31वीं बटालियन के कमांडेंट के रूप में रुद्रपुर (नैनीताल) में हुई तथा गत अप्रैल से 31वीं बटालियन के कमांडेंट थे. सरदार प्रकाश सिंह का जन्म 1946 में अमृतसर में हुआ था. उनकी शिक्षा बीएससी तक हुई. उन्होंने 1976 में भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश किया. उनकी प्रथम नियुक्ति सीतापुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई थी. गत जुलाई में वह पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर लखनऊ आए. श्री सिंह को पुलिस लाइन में फ्लैट मिला, जहां राजीव वर्मा भी रहते थे. सत्ताइस साल के राजीव वर्मा एक ज़िंदादिल इंसान थे, कुछ-कुछ दिलफेंक किस्म के भी. उन्होंने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद भी उनका दूसरी औरतों के साथ हंसना-बोलना कम नहीं हुआ था. देहरादून में उनके साथ रहे एक अधिकारी के अनुसार, राजीव वहां लड़कियों में काफी लोकप्रिय थे. राजीव वर्मा की पत्नी मंजू वर्मा को यह सब अच्छा नहीं लगता था. उनके एक पारिवारिक मित्र के अनुसार, मंजू एवं राजीव वर्मा के बीच पिछले तीन साल से तनाव चल रहा था. इस तनाव की जड़ में जहां राजीव वर्मा का दिलफेंक स्वभाव हो सकता है, वहीं मंजू वर्मा की बीमारी भी, जिसका इलाज पिछले दो साल से चल रहा है. तनाव की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन उसका असर उन दोनों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता ही था. मसलन दो संतानों वाले वर्मा दंपत्ति को शायद ही किसी ने साथ घूमते या सिनेमा देखने जाते देखा होगा. राजीव कभी अपनी पत्नी को साथ लेकर दौरे पर नहीं जाते थे. प्रकाश सिंह के परिवार से, विशेषकर उनकी पत्नी से राजीव बहुत ज़्यादा घुले-मिले थे. शुरू में एक महीने तक तो मंजू व प्रकाश सिंह की पत्नी में बहिनापा-सा था, लेकिन यह संबंध बहुत दिनों तक नहीं चला.

इधर पिछले कुछ दिनों से मंजू वर्मा तो तनाव में थीं ही, पड़ोसियों का कहना है कि प्रकाश सिंह भी तनाव से ग्रस्त नज़र आ रहे थे. 28 सितंबर को राजीव प्रकाश सिंह के घर फोन करने गए, संभवतः प्रकाश सिंह उस समय बाथरूम में थे. अचानक बाहर आने पर उन्होंने क्या देखा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन गोली उसके बाद ही चली. शुरू में इसे आत्महत्या का मामला बताया गया, लेकिन थोड़ी ही छानबीन से ज़ाहिर हो गया कि यह अनुमान ग़लत है. उस समय कमरे में राजीव वर्मा के अलावा सिर्फ़ प्रकाश और उनकी पत्नी थीं. श्री वर्मा को इन दोनों में से ही किसी ने गोली मारी या किसी ने आसमान से हमला किया, यह अभी तक रहस्य बनाकर रखा गया है. वारदात के दिन से अब तक जांच-पड़ताल की स्थिति में फ़र्क़ सिर्फ़ इतना आया है कि पहले आत्महत्या की संभावना के आधार पर खोजबीन की जा रही थी, अब दुर्घटना के सिद्धांत को भुनाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राजीव वर्मा की मौत को एक दुर्योग बताते हुए कहा कि प्रकाश सिंह अपने को आग्नेयास्त्रों का एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) मानते हैं, उन्होंने रिवाल्वर का चैंबर खाली करने के इरादे से गोलियां निकालीं, लेकिन उन्हें गिना नहीं. शायद एक गोली चैंबर में ही रह गई थी. दुर्घटना के दिन राजीव वर्मा उनकी रिवाल्वर उलट-पुलट रहे थे, तभी उसका ट्रिगर दब गया और चैंबर में रह गई गोली उनकी कनपटी को छेदती हुई निकल गई. अगर यह माना जाए कि राजीव वर्मा ने प्रकाश सिंह के घर में पड़ी रिवाल्वर को खाली समझ कर उसका घोड़ा दबाया और अनजाने में रिवाल्वर के चैंबर में रह गई गोली के दगने से उनकी मौत हुई, तो सवाल उठता है कि उनकी कनपटी की चमड़ी क्यों नहीं झुलसी थी? नज़दीक से गोली चलने पर उसका प्रहार जिस अंग पर होता है, वहां की चमड़ी झुलस जाती है. ज़ाहिर है, गोली कुछ दूर से चलाई गई थी. संदेह पैदा करने वाली दूसरी बात यह है कि राजीव वर्मा के सिर में लगी गोली न तो अंत्य-परीक्षण के दौरान मिली और न उसे घटनास्थल पर पाया जा सका. गोली चूंकि कनपटी को छेदकर बाहर निकल गई थी, इसलिए उसे घटनास्थल पर ही मिलना चाहिए था. गोली को किसने गायब कराया? गोलीकांड के बाद प्रकाश सिंह ने टेलीफोन, बिस्तर आदि को ठीक कर घटनास्थल पर पहले जैसी स्थिति लाने की चेष्टा क्यों की? उन्होंने जांच से पहले ही रिवाल्वर की सफाई क्यों कराई? इन प्रश्नों का विश्वसनीय उत्तर ढूंढना आवश्यक है, जो विस्तृत जांच के बगैर संभव नहीं. अगर विस्तृत जांच नहीं हुई, तो पुलिस और सरकार से लोगों का विश्वास तो उठेगा ही, बड़े अधिकारियों के बीच झगड़ों का निपटारा करने के लिए रिवाल्वरबाजी की परंपरा शुरू हो जाएगी.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिताः नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी ने इस संवाददाता को बताया कि उन्हें शक है कि प्रकाश सिंह सिख उग्रपंथियों से संबंध रखते हैं और सिख उग्रपंथियों के निर्देश पर उन्होंने राजीव वर्मा को गोली मारी! उक्त अधिकारी के अनुसार, राजीव वर्मा ने आगरा में अपने कार्यकाल के दौरान कहीं फायरिंग कराई थी, जिसमें कई सिख मारे गए. उसका बदला लेने के लिए प्रकाश सिंह ने राजीव वर्मा पर गोली चलाई. गुप्तचर विभाग के सामने एक तथ्य यह आया है कि प्रकाश सिंह और राजीव वर्मा, दोनों का ही कैलाश हॉस्टल की एक लड़की से संबंध था तथा उस लड़की के सवाल पर राजीव वर्मा ने एक बार प्रकाश सिंह को धमकी भी दी थी. राजीव वर्मा की पत्नी मंजू वर्मा का कहना है कि प्रकाश सिंह उन दोनों से जलते थे, क्योंकि वे खाते-पीते घर के थे तथा उन्हें हैंडसम पेयर माना जाता था. जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस ने ये जानकारियां प्राप्त कर लीं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पुलिस श्रीमती प्रकाश सिंह को बिल्कुल भूल गई है, जबकि प्रकाश सिंह के अलावा एकमात्र वही हत्या या दुर्घटना की चश्मदीद गवाह हैं. दरअसल, पुलिस श्री वर्मा की मौत के संबंध में कई तथ्यों की उपेक्षा कर रही है, जैसे कि नक्शा-ए-वारदात में इसका ज़िक्र नहीं किया गया कि जिस रिवाल्वर से गोली चली, वह पलंग पर मृतक की बेल्ट के नीचे पड़ी थी तथा टेलीफोन का रिसीवर नीचे लटका हुआ था. संयोग से हमारे छायाकार ने इस दृश्य की तस्वीर खींच ली थी. जिस साक्ष्य को झुठलाया नहीं जा सकता. शायद पुलिस महानिरीक्षक नरेश कुमार वर्मा नहीं चाहते कि उनके कार्यकाल में आईपीएस अधिकारियों की बखिया उधेड़ी जाए और उन्हें आईपीएस अधिकारियों के असंतोष का केंद्र बनना पड़े. उनके रुख से संकेत पाकर ही अन्य अधिकारी जांच-पड़ताल को भ्रमजाल में फंसाना चाह रहे हैं.

इस घटना का सबसे विस्मयकारी पहलू प्रकाश सिंह का पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर बने रहना है. इससे पहले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मामूली शिकायत पर भी कार्रवाई हो जाती थी. कुछ समय पहले ही दो पुलिस अधीक्षकों को बिना सफाई का मौक़ा दिए नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया, जबकि उनमें से किसी के ऊपर हत्या का आरोप नहीं था. इस तरह का दोहरा मानदंड अपना कर शायद यह प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है कि प्रकाश सिंह ने राजीव वर्मा की हत्या नहीं की. लेकिन, उत्तर प्रदेश शासन अगर यह साबित करना चाहता है, तो उसे टाल-मटोल करने के बजाय सबूतों के साथ यह बताना चाहिए कि राजीव वर्मा को गोली किसने मारी? ■

(2 नवंबर, 1981)

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी, देश की उम्मीदें टूटने न पाएं

"प्रधानमंत्री जी, देश की प्राथमिकताएं, जो आपने तय की हैं, वे सही हैं, लेकिन उनका क्रम ग़लत है. जो आप आज कर रहे हैं, वह आपको तीसरे-चौथे साल करना चाहिए और आज आपको बुनियादी तौर पर इस देश के नौजवानों को विकास के कामों में लगाने के रास्ते तलाशने चाहिए. उद्योगों की इकाई गांवों के पास यानी हर ब्लॉक में पहुंचानी चाहिए. अनाज संग्रह करने के लिए हर ब्लॉक में भंडारण के तरीके तलाशने चाहिए. लोग निजी तौर पर किस तरह भंडारण गृह का निर्माण कर सकते हैं और जिन्हें सरकार किराया देकर अपनी निगरानी में रखे, इसकी योजना बनानी चाहिए."

हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा था, जिसे हमने इसी जगह छापा भी था. उस पत्र की पावती यानी एक्नॉलेजमेंट तक हमें नहीं मिला. प्रधानमंत्री कार्यालय इतना सक्षम कार्यालय है, इतना एफिशिएंट कार्यालय है कि वह कहां तो एक महीने बाद होने वाली घटना पर उसी तारीख में अपनी चिट्ठी बनाकर भेज देता है और वहीं वह एक पत्र की पावती भेजने की जहमत तक नहीं उठाता. क्या हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई भी शख्स या संगठन पत्र भेजेगा, तो प्रधानमंत्री कार्यालय उसका जवाब देगा या प्राप्ति की रसीद भेजेगा? भारतीय जनता पार्टी के सांसद या कार्यकर्ता जब यह कहते थे कि ऐसा होता है, तो हमें विश्वास नहीं होता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह के हाव-भाव दिखाए थे, उनसे यह लगता था कि मौजूदा प्रधानमंत्री कुछ अलग ढंग से काम करेंगे और उनका कार्यालय भी. पर खैर, यह मसला प्रधानमंत्री का है.

इसके बावजूद हम प्रधानमंत्री से एक दूसरा निवेदन कर रहे हैं. हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री इसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के अपने दिमाग की प्राथमिकताएं और उनके सलाहकारों की सलाह देश की प्राथमिकताओं से कुछ अलग हैं. प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया बनाने की घोषणा कर दी और एक बड़ा इवेंट किया. इस समारोह में देश के सारे प्रमुख उद्योगपति मौजूद थे, जिन्होंने साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के इंवेस्टमेंट की घोषणा कर दी. प्रधानमंत्री की पहली योजना स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री के कारण ही कूड़े में चली गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसके फॉलोअप का कोई तरीका नहीं बनाया. उन संस्थानों को उन्होंने मजबूत नहीं किया, जिनके ऊपर सफाई की ज़िम्मेदारी है. और, लोगों ने इसे प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने या उनके साथ नाम जोड़ने का एक अवसर मान लिया. प्रधानमंत्री ने देश के जाने-माने नामों को इस अभियान में जोड़ा. सबने एक दिन झाड़ू उठाई, वे चाहे सिनेमा के रहे हों, खेल के रहे हों या उद्योग जगत के, और फोटो खिंचवा ली तथा अपना कर्तव्य पूरा मान लिया. सारा देश गंदगी से बजबजा रहा है. स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च हुए, लेकिन अभियान ठप्प पड़ा है. प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया को देश का मोटो बनाया और सारी दुनिया में यह कहते घूमे कि हमारे यहां श्रम सस्ता है, इसलिए आप हमारे यहां सामान बनाएं. लेकिन, बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में कितनी आईं, इसका जवाब सरकार नहीं दे रही है. जितने इंवेस्टमेंट की घोषणा हुई थी, उसमें से कितना सचमुच हुआ, इसके कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं. दूसरी तरफ़ भारत का निर्यात अवश्य कम हो गया. यह आंकड़ा उपलब्ध है. प्रधानमंत्री जी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और अब डिजिटल इंडिया...

प्रधानमंत्री को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जिस देश के गांव में लोग अंग्रेजी का ए और हिंदी का अ नहीं जानते हैं, निरक्षर हैं और पिछली सरकारों ने अरबों रुपये साक्षरता अभियान में खर्च किए, लेकिन वे लोगों की जेब में चले गए, हम उस भारत में इंटरनेट की सुविधा देने की बात कह रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लैपटॉप बांटे. वे लैपटाप बहुत सारी जगहों पर एक महीने के भीतर दोबारा बाज़ार में पहुंच गए. और जिनके पास हैं भी, वहां वे धूल फांक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना का ए नहीं आता. ट्रेनिंग का कोई इंतजाम नहीं है. उस भारत में प्रधानमंत्री अरबों रुपये खर्च करके लोगों के पास इंफॉर्मेशन हाइवे पहुंचाना चाहते हैं. योजना बहुत अच्छी है, लेकिन यह वैसी ही योजना है, जैसे कि आप बंजर खेत में बिना खाद-पानी डाले, बिना उसे खेती के लिए तैयार किए, बीज डाल दें. लेकिन प्रधानमंत्री हैं, उनके सलाहकार हैं, टेलीविजन है, ताली बजाने वाले हैं और निवेश की घोषणा करने वाले हैं. यह तय है कि जिसने ढाई सौ करोड़ रुपये की घोषणा की, वह ढाई हज़ार करोड़ रुपये कमाएगा. और, यह टोटल साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट, जिसकी घोषणा डिजिटल इंडिया के कॉन्क्लेव में पूंजीपतियों ने की, वे इसका सौ गुना कमाकर यानी सरकार को लूटकर बाहर निकल जाएंगे.

प्रधानमंत्री को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जिस देश के गांव में लोग अंग्रेजी का ए और हिंदी का अ नहीं जानते हैं, निरक्षर हैं और पिछली सरकारों ने अरबों रुपये साक्षरता अभियान में खर्च किए, लेकिन वे लोगों की जेब में चले गए, हम उस भारत में इंटरनेट की सुविधा देने की बात कह रहे हैं.

प्रधानमंत्री जी, क्या यह नहीं होना चाहिए कि आप सबसे पहले सारे स्कूलों-कॉलेजों को प्रोत्साहित करते, प्रेरित करते कि वे हिंदुस्तान के गांवों में साक्षरता अभियान को अपनी प्राथमिकता बनाएं? हाईस्कूल से लेकर डिग्री तक के छात्रों को, जो इस देश में पढ़ रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट तब मिलेगा, जब वह दो महीने गांव में साक्षरता अभियान में जुड़ें. और, प्रत्येक 10 किलोमीटर क्षेत्र के स्कूलों-कॉलेजों को यह ज़िम्मेदारी दी जाती कि अगर उनके क्षेत्र में कोई भी निरक्षर पाया गया, तो उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता बंद कर दी जाएगी. देश के लोगों को साक्षर बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है. अगर वे साक्षर बनेंगे, तभी उन्हें आप कंप्यूटर इस्तेमाल करने की जानकारी दे पाएंगे. नहीं तो कंप्यूटर अश्लील फिल्म देखने का साधन बन जाएंगे और कंप्यूटर अपराध का कारण बन जाएंगे. एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि अपराधों की बढ़ती संख्या के पीछे फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है. हिंदुस्तान का देहात पिछली सरकार की कई योजनाओं की वजह से भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया. पूरी की पूरी पंचायत भ्रष्ट हो गई. भ्रष्टाचार दिल्ली और राज्यों की राजधानी से निकल कर गांवों की पंचायत तक पहुंच गया. क्या अब अपराध राज्यों की राजधानी से गांवों में पहुंच जाएगा? यह सवाल प्रधानमंत्री जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके बारे में मेरी यह धारणा है कि आप इन सारी चीजों को नहीं पसंद करते. लेकिन, अगर आपके द्वारा किए हुए कामों की वजह से यही नतीजा निकलने वाला है, तो क्या सोचने की ज़रूरत नहीं है?

होना तो यह चाहिए था कि हम सबसे पहले गांवों को साक्षर करते. लोगों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की योजनाओं में शामिल होने के लिए हम देश के पूंजीपतियों को प्रेरित करते और तब डिजिटल इंडिया जैसे ग्लैमरस प्रोग्राम की शुरुआत करते. लेकिन, आपने आईटी सेक्टर को पैसा देने के लिए जो योजना बनाई है, वह हिंदुस्तान को बहुत आगे नहीं ले जाएगी. यह इस तरह की योजना है कि आपने रन-वे बनाया नहीं और हवाई जहाज खरीदने की तैयारी करने लगे.

प्रधानमंत्री जी, देश की प्राथमिकताएं, जो आपने तय की हैं, वे सही हैं, लेकिन उनका क्रम ग़लत है. जो आप आज कर रहे हैं, वह आपको तीसरे-चौथे साल करना चाहिए और आज आपको बुनियादी तौर पर इस देश के नौजवानों को विकास के कामों में लगाने के रास्ते तलाशने चाहिए. उद्योगों की इकाई गांवों के पास यानी हर ब्लॉक में पहुंचानी चाहिए. अनाज संग्रह करने के लिए हर ब्लॉक में भंडारण के तरीके तलाशने चाहिए. लोग निजी तौर पर किस तरह भंडारण गृह का निर्माण कर सकते हैं और जिन्हें सरकार किराया देकर अपनी निगरानी में रखे, इसकी योजना बनानी चाहिए. गांव के स्कूल किस तरीके से शिक्षकों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे साक्षर ग्रामीण पैदा कर सकते हैं, यह देखना आवश्यक है. उतना ही आवश्यक है कि गांवों के स्वास्थ्य केंद्र सही ढंग से काम करें. लेकिन, यह नहीं हो रहा है.

माननीय प्रधानमंत्री जी, हम यह बात इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अभी भी यह छाप है कि आप हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं. धार्मिक विचारों के ऊपर किसी का आपसे मतभेद हो सकता है, पड़ोसियों से रिश्तों की नीति के ऊपर मतभेद हो सकता है, लेकिन आपसे यह अपेक्षा हर एक की है कि आप देश में जहां कहीं भी भ्रष्टाचार से लड़ने का सवाल है, वहां आप चट्टान की तरह खड़े होंगे. और, यह भी अपेक्षा है कि देश की प्राथमिकताओं, जिनमें गांव, खेती, किसान, नौजवान और मज़दूर प्रमुख हैं, को आप सबसे पहले हल करेंगे, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं. आपने प्राथमिकताओं का क्रम उलट दिया है. और, जब क्रम उलटते हैं, तो यह बिल्कुल वैसा होता है, जैसे कहीं की यात्रा पर निकलने से पहले आप अपने पैर के जूतों या पैजामे का ध्यान न दें, बल्कि पॉर्लर में जाकर फेशियल कराएं और बाल ठीक कराएं. और, सिर्फ़ बाल और चेहरा ठीक कराने के बाद जब यात्रा पर कोई निकलता है, तो पैर में कांटे गड़ते हैं, कंकड़ चुभते हैं, पैर यात्रा नहीं कर पाते. मेरा आग्रह है कि आप प्राथमिकताओं के बारे में सोचिए, नहीं तो साल भर बीत गया, तीन महीने और बीत गए हैं, आपको लेकर देश में एक दूसरी तरह की राय बनने लगेगी और लोग मानने लगेंगे कि आप भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो इतिहास में शायद ही दर्ज हो पाएं. ■

editor@chauthiduniya.com

अमेरिका का ऐतिहासिक ज़ख्म

आज देश का बड़ा हिस्सा नस्लवाद और नस्ली भेदभाव से मुक्त है. दक्षिण से संबंध रखने के बावजूद राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने सिविल राइट्स से संबंधित क़ानून बनाने की शुरुआत की. उसके बाद के पचास वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है. अश्वेतों का एक मध्यम वर्ग उत्पन्न हो गया है और मध्यम वर्ग में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए रंग और नस्ल कोई मायने नहीं रखता है. लेकिन, जहां तक ग़रीबी का सवाल है, तो अश्वेत अपनी आबादी के अनुपात में अधिक ग़रीब हैं.

मेघनाद देसाई

अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुए 150 साल हो चुके हैं. इस युद्ध में संघ (यूनियन) से अलग हुए कंफेडरेट को उत्तर की सेना ने पराजित कर दिया था. यह अमेरिकी मानसिकता पर लगा ऐसा ज़ख्म था, जो आज भी ताज़ा है. कंफेडरेसी का कहना था कि वह राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए यूनियन से अलग हुआ था, जबकि अब्राहम लिंकन और उत्तर के लोग इसे गुलामी की प्रथा से जोड़कर देख रहे थे. दक्षिण के राज्य गुलामी प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहते थे. वे युद्ध में हार गए और युद्ध के दौरान ही लिंकन ने एमंशिपेशन (मुक्ति) डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए थे. पिछले दिनों डेलन स्टॉर्म रूफ नामक एक नवजवान ने पुराने कंफेडरेट स्टेट के चार्ल्सटन (साउथ कैरोलिना) के एक शांत और अलग-थलग स्थित चर्च में घुसकर बाइबिल पाठ कर रहे नौ अश्वेत श्रद्धालुओं को गोली मार दी, जबकि अश्वेतों ने चर्च में उसका स्वागत किया था. वह इस पूर्वाग्रह से ग्रसित था कि अश्वेत अमेरिका पर क़ब्ज़ा कर लेंगे. वह एक नस्ली जंग शुरू करना चाहता था. इस घटना में हताहत लोग किसी तरह की जंग की शुरुआत करने की स्थिति में नहीं थे. हताहतों के रिश्तेदारों ने रूफ को माफ़ कर दिया.

अगर कोई डेलन रूफ की वेबसाइट पर जाएगा, तो वह उसे वहां कंफेडरेट झंडे के साथ मिलेगा. इससे यह ज़ाहिर होता है कि कंफेडरेट राज्यों में गुलामी प्रथा जारी रखने की इच्छा आज भी विद्यमान है. दरअसल, दक्षिण के कई राज्य यह झंडा अपने दफ्तरों पर फहराते हैं. आख़िरकार दक्षिण कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि कैपिटल बिल्डिंग्स पर अब कंफेडरेट झंडे न फहराए जाएं. ज़ाहिर है, ऐसा करने के लिए उन्हें काफी हिम्मत जुटाने की आवश्यकता पड़ी होगी. झंडा फहराने की यह रस्म न केवल गृह युद्ध में हारे हुए पक्ष की तरफ़ से हिस्सा लेने वाले बहादुर सैनिकों के सम्मान से संबंधित है, बल्कि यह श्वेत नस्लवाद की प्रतीक भी है. 1962 में सिविल राइट्स आंदोलन ने जब दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करना शुरू किया, तो उसकी प्रतिक्रिया में इस झंडे को एक नया जीवन मिला. ज़ाहिर है, अमेरिका द्वारा नस्लवाद जिस तरह रद्द किया जा रहा था, उससे दक्षिणी राज्यों के श्वेत (सभी नहीं, लेकिन उनकी अच्छी खासी तादाद) खुश नहीं थे.

अमेरिका में नस्लवाद आज भी एक विभाजनकारी ताक़त है. जेलों की आबादी के लिहाज से या पुलिस कार्रवाई में घायल या मारे जाने के मामले में अश्वेतों की संख्या उनकी आबादी की तुलना में अधिक होने की संभावना रहती है. यहां तक कि ग़रीबी और ख़राब सेहत से पूर्व कंफेडरेट राज्य उत्तर की तुलना में अधिक प्रभावित हैं. और ये वही राज्य हैं, जहां ग़रीबों के लिए जारी ओबामा केयर (ओबामा का स्वास्थ्य कार्यक्रम) का सर्वाधिक विरोध हुआ. बहरहाल, एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति, जिसके माता-पिता श्वेत और अश्वेत थे, के सत्ता में आने के बावजूद अमेरिका नस्लवाद की समस्या से उबर नहीं पाया. जैसा कि अमेरिका की पहली महिला अश्वेत विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने कहा था कि नस्लवाद अमेरिका का पैदायशी निशान है. दरअसल, आज अश्वेत अमेरिकियों की हालत 1960 के दशक (जब मैं वहां गया था) से बहुत बेहतर है. उस समय पूरे देश में नस्ली भेदभावपूर्ण क़ानून मौजूद थे.

भारत के भी अपने जन्मजात ज़ख्म के निशान हैं. बंटवारा एक ऐसा ज़ख्म है, जो अभी तक नहीं भरा है. यह ज़ख्म अभी भी टीस पैदा करता है. संघ परिवार हमेशा मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने पर आमादा रहता है. हाल के दिनों में उन्हें पाकिस्तान भेजने का कारण योग में हिस्सा लेने से इंकार करना था. अगर कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, जो नाथू राम गोडसे के नाम पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो उसके पीछे भी पाकिस्तान ही है, क्योंकि यह गांधी जी ही थे, जिनका मत था कि संपत्ति के बंटवारे में पाकिस्तान के साथ न्याय होना चाहिए, जिसकी वजह से नाथू राम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी.

आज देश का बड़ा हिस्सा नस्लवाद और नस्ली भेदभाव से मुक्त है. दक्षिण से संबंध रखने के बावजूद राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने सिविल राइट्स से संबंधित क़ानून बनाने की शुरुआत की. उसके बाद के पचास वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका है. अश्वेतों का एक मध्यम वर्ग उत्पन्न हो गया है और मध्यम वर्ग में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए रंग और नस्ल कोई मायने नहीं रखता है. लेकिन, जहां तक ग़रीबी का सवाल है, तो अश्वेत अपनी आबादी के अनुपात में अधिक ग़रीब हैं. दरअसल, चार्ल्सटन की त्रासदी ने अमेरिकियों को अपने इतिहास पर पुनर्विचार पर मजबूर किया है. डेलन रूफ की घिनौनी हरकत की वजह से अनेक श्वेत अमेरिकी कंफेडरेट झंडे से अपनी वफादारी समाप्त कर रहे हैं. साथ ही जिस चर्च में उक्त हत्याएं हुई थीं, उसकी उदारता ने भी बहुतों के दिल पिघला दिए. दरअसल, अमेरिका में नस्लवाद का मुद्दा अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है. यह देश बहादुरों और स्वतंत्र लोगों का देश उस वक्त तक नहीं बन सकता, जब तक कुछ लोगों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और कुछ को कम.

भारत के भी अपने जन्मजात ज़ख्म के निशान हैं. बंटवारा एक ऐसा ज़ख्म है, जो अभी तक नहीं भरा है. यह ज़ख्म अभी भी टीस पैदा करता है. संघ परिवार हमेशा मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने पर आमादा रहता है. हाल के दिनों में उन्हें पाकिस्तान भेजने का कारण योग में हिस्सा लेने से इंकार करना था. अगर कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं, जो नाथू राम गोडसे के नाम पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, तो उसके पीछे भी पाकिस्तान ही है, क्योंकि यह गांधी जी ही थे, जिनका मत था कि संपत्ति के बंटवारे में पाकिस्तान के साथ न्याय होना चाहिए, जिसकी वजह से नाथू राम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी. हमें आशा करनी चाहिए कि भारत अपने ज़ख्म अमेरिका से पहले किसी जान-माल के नुक़सान के बिना भर लेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

तीस के दशक के बीच उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ज्वाइन की. जब 1936 में यह पार्टी टूट गई तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली. हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात की भनक बहुत बाद नहीं लगी कि वे कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्य हैं. साल 1935 में उन्हें केजीबी में शामिल करने के लिए अूमोदित किया गया. साल के आखिरी में उन्होंने हिलेरी नुसाबॉम, जो एक गणित के शिक्षक थे, से शादी कर ली. हिलेरी के माता-पिता रूसी मूल के थे. हिलेरी भी एक कम्युनिस्ट नेता थे.कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनने के बाद उन्होंने ब्रिटेन में रहकर सोवियत के लिए जाासूसी की शुरुआत कर दी.

मलेरिया एक गंभीर बीमारी है

मोनिशा भटनागर

बरसात का मौसम मच्छरों के तेजी से पनपने का कारण बनता है और इसलिए इस मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया काफी बढ़ जाती हैं. मलेरिया का मच्छर सामान्यतया उन गर्म इलाकों में पाया जाता है जिनमें बारिश होती है या फिर गंदा पानी ठहरा हुआ रहता है. ऐसी जगहों पर मलेरिया होने की आशंका ज्यादा रहती है. ऐसी जगहें हमारे देश में बहुतायत से पाई जाती हैं. मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है. मलेरिया के विषाणु से संक्रमित मच्छर अपनी लार के साथ इस विषाणु को इंसान के शरीर में पहुंचा देता है. खून के जरिए शरीर में घुसते ही विषाणु लीवर तक पहुंच जाता है. विषाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही शरीर बीमार होने लगता है. यह मच्छर आमतौर पर रात के समय काटता है. मलेरिया एक गंभीर रोग है. यदि इसका सही समय पर इलाज न हो तो परिणाम गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं. मलेरिया की शुरुआत में रोगी को शरीर में दर्द के साथ बुखार, सिरदर्द, उल्टी या गले में सूखे कफ की शिकायत होती है. ऐसा होने पर अगर खून की जांच कराई जाए तो मलेरिया का पता आसानी से चल जाता है. लापरवाही बरतने या समय से इलाज न कराये जाने पर यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है.

लक्षण

मलेरिया के लक्षण मच्छर काटने के 8 से 25 दिन में (औसतन 14 दिन) दिखने लगते हैं. मलेरिया होने पर बुखार, कंपकंपी, खांसी-जुकाम, भूख ना लगना, उल्टियां होना, पेट में दर्द होना, हाइपोथर्मिया और सांस तेज चलने जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. ठंड लगकर तेज बुखार आना, सिरदर्द और शरीर में ऐंठन खासकर जोड़ों में दर्द आम लक्षण हैं. बीमारी बिगड़ जाने पर बेहोशी जैसे लक्षण भी हो सकते हैं. अगर शरीर में पानी की कमी हो जाये तो अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है.मलेरिया के लक्षण मच्छर काटने के 10वें दिन से शुरू होकर 4 सप्ताह तक बने रहते हैं. इसके लक्षण 5 साल से कम आयु के बच्चों में ज्यादा गंभीर होते हैं. ध्यान देने वाली बात है कि मलेरिया में बुखार एक दिन छोड़कर आता है. अगर एक दिन बुखार आता है तो अगले दिन शायद न हो पर उससे अगले दिन फिर बुखार होता है. बुखार उतारने के लिए ठंडे पानी से बदन पोंछें और मरीज को

सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें. भारत के गांवों और छोटे शहरों में लंबे समय से मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाता रहा है. विश्व स्वास्थ संगठन और तमाम वैज्ञानिक भी यह कहते हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल और दवा का छिड़काव मलेरिया से निपटने का अब तक सबसे कारगर तरीका है.

पीने के लिए तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में दें.

मलेरिया का अगर तुरंत इलाज न किया जाए,तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जैसे फेफड़े में सूजन और सांस लेने में तकलीफ. गुर्दे खराब होना, शरीर में खून की कमी होना और लिवर का बढ़ना भी इस बीमारी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. मलेरिया का निदान साधारण से ब्लड टेस्ट के जरिये किया जा सकता है. कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत खून की जांच करवाएं. समय से पता लगने पर मलेरिया का इलाज़ पूर्णतः संभव है. शीघ्र इलाज से इस रोग से होने वाली जटिलताओं से बचा जा सकता है.

मलेरिया होने पर बीमार को बहुत आराम करना चाहिए, कई डॉक्टर तो टोटल बेडरेस्ट की सलाह देते हैं. साथ ही हल्का और स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना चाहिए और पानी भी उबालकर पीना चाहिए. मलेरिया के लिए कई तरह की दवाएं दी जाती हैं लेकिन डॉक्टर के कहे अनुसार ही मलेरिया के लिए दवाई लें. बिना डॉक्टर की सलाह के कोई उपचार नहीं करना चाहिए. समय पर बीमारी का पता चलने पर और ठीक प्रकार की चकित्सा मिलने पर हर तरह का मलेरिया ठीक हो सकता है.

मलेरिया से बचाव

किसी भी बीमारी के उपचार से ज्यादा ज़रूरी है उससे बचाव. इस बीमारी से बचाव करना कोई भारी चुनौती नहीं है. कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है जैसे अपने आस-पास सफाई का ध्यान रखें क्योंकि साफ-सुथरी जगह पर मच्छर कम पनपते हैं.मच्छर खासकर मलेरिया फैलाने वाले मच्छर रुके पानी में पनपते हैं इसलिए नालियों की सफाई कराते रहें और गड्ढे आदि भरवाते रहें. अगर पानी भराव रोकना संभव न हो, तो उसमें कीटनाशक दवा या क्रोसिन का तेल डालें. घर में या आसपास पड़े बर्तन, मटके, डब्बे, गमले, टायर आदि में पानी इकठ्ठा न होने दें. इसके अलावा घरों के अंधेरे कोनों में जमा गैरजरूरी पुराने सामान को भी अगर हटा दिया जाए तो मच्छरों को छिपने की जगह नहीं मिलती है.

सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें. भारत के गांवों और छोटे शहरों में लंबे समय से मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाता रहा है. विश्व स्वास्थ संगठन और तमाम वैज्ञानिक भी यह कहते हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल और दवा का छिड़काव मलेरिया से निपटने का अब तक सबसे कारगर तरीका है. मच्छर भगाने वाली क्रीम और मशीनों को भी इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए. मलेरिया क्योंकि एक आम बीमारी बन गयी है इसलिए इसे लेकर कई तरह के भ्रम भी है, जैसे अगर आपको एक बार मलेरिया हो जाता है तो आप आजीवन इस बीमारी से प्रभावित रहते हैं या मलेरिया के कुछ प्रकार की चिकित्सा नहीं हो सकती. कई लोग यह भी मानते हैं कि स्वस्थ लोगों के लिए मलेरिया कोई गंभीर संक्रमण नहीं होता. इस प्रकार के भ्रम इस बीमारी को और गंभीर बनाते हैं. विश्व भर में फैली हुई इस जीवन संक्रामक बीमारी के बारे में जागरूकता भी इससे बचाव का एक रास्ता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ब्रिटेन की आंखों में धूल झोंकती रहीं नॉरवुड

अरुण तिवारी

मेलिटा स्टेडमैन नॉरवुड का जन्म 25 मार्च 1912 को हुआ था. वे एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थीं. वे केजीबी की एजेंट भी थीं और लगभग चालीस सालों तक उन्होंने केजीबी के लिए काम किया. 1937 में उनकी नियुक्ति सोवियत रूस में एक केजीबी एजेंट के तौर पर की गई थी. इसके बाद वे ब्रिटेन में ब्रिटिश नॉन फेरस मेटल्स रिसर्च एसोसिशन में काम करने लगीं. इस जगह काम करते हुए उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां सोवियत रूस तक पहुंचाईं. कुछ रूसी विद्वान लोगों ने नॉरवुड को सोवियत की सबसे महत्पूर्ण महिला जासूस के उपनाम से भी नवाजा है.

नॉरवुड लातिवाई पिता एलेक्जेंडर सिरनिस और ब्रिटिश मां गरटूड की संतान थीं. उनका जन्म हैंपशायर में हुआ था. उनके माता पिता ब्रिटेन समाजवादी नेताओं के बीच काफी चर्चित थे. उनके पिता एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था द साउदर्न वर्कर एंड लेबर एंड सोशलिस्ट जर्नल था. इस अखबार में सोवियत नेता लेनिन और ट्रॉस्की के लेख छपा करते थे. इस अखबार को स्थानीय कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों के बीच बांटा जाता था. यह अखबार कम्यूनिस्ट सदस्यों के बीच मशहूर भी बहुत था. नॉरवुड ने साउथंपटन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और एक साल के भीतर ही लंदन में नौकरी करने के लिए शिक्षा अधूरी ही छोड़ दी.

तीस के दशक के बीच उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ज्वाइन की. जब 1936 में यह पार्टी टूट गई तो उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली. हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों को इस बात की भनक बहुत बाद नहीं लगी कि वे कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्य हैं. साल 1935 में उन्हें केजीबी में शामिल करने के लिए अूमोदित किया गया. साल के आखिरी में उन्होंने हिलेरी नुसाबॉम, जो एक गणित के शिक्षक थे, से शादी कर ली. हिलेरी के माता-पिता रूसी मूल के थे. हिलेरी भी एक कम्यूनिस्ट नेता थे.

कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य बनने के बाद उन्होंने ब्रिटेन में रहकर सोवियत के लिए जाासूसी की शुरुआत कर दी. लेकिन उनकी शुरुआत ही ठीक नहीं रही उनके साथ के तीन जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों पर केस चलाया गया और तीन महीने की जेल के लिए भेज दिया गया. इस वजह से नॉरवुड को शुरुआती दिनों में संगठन के कमजोर हो जाने जैसी परिस्थिति से जूझना पड़ा. लेकिन चूंकि वे ब्रिटेन में बहुत दिनों से रह रही थीं और उनके तार वहां बहुत गहरे तक जुड़े हुए थे, इस वजह से किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ. नॉरवुड को उनके पिता के समाजवादी सर्किल में मशहूर होने का बहुत फायदा मिला. ब्रिटेन में इन नेताओं की वजह से वे आसानी से किसी तक भी अपनी पहुंच बना सकती थीं. इसके अलावा से खुद भी ब्रिटेन में एक सिविल सर्वेंट थीं जिस वजह से उनका ज्यादातर समय देश के राजनीतिक संभ्रांत वर्ग के साथ ही गुजरता था. वे लगभग हर राजनीतिक कार्यक्रम में शिकरत किया करती थीं जिसका प्रमुख उद्देश्य किसी भी तरह गोपनीय सूचनायें निकालना हुआ करता था.

ब्रिटेन के एटोमिक रिसर्च प्रोग्राम के डिपार्टमेंट में वे डायरेक्टर पद पर तैनात की गईं. इसके बाद रूस के लिए ब्रिटेन के एटोमिक रिसर्च कार्यक्रम के बारे में जानना ज्यादा आसाना हो गया क्योंकि शायद ही इस रिसर्च प्रोजेक्ट से संबंधित कोई ऐसी फाइल थी जो नॉरवुड की डेस्क से होकर नहीं गुजरती थी. सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है अन्य जासूसों से इतर नॉरवुड की जासूसी को कभी कोई पकड़ नहीं पाया. वो अपना काम आसानी के साथ कर रही थीं. वे 1972 में जब इस पद से रिटायर हुई तब तक सारी जानकारियां सोवियत को पहुंचाती रहीं.

नॉरवुड अपना जीवन रिटायरमेंट के बाद ब्रिटेन में आसानी के साथ जी रही थीं. उन्हें खिलाफा रिटायरमेंट के बाद भी किसी ब्रिटिश एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की. साल 1992 में सोवियत में आर्काइव डिपार्टमेंट में काम करने वाले वालिसी मितरोखिन ने नॉरवुड के बारे में खुलासा किया. उन्होंने बताया कि नॉरवुड पर सोवियत सरकार बहुत ज्यादा भरोसा किया करती थी. सावियत सरकार का नॉरवुड पर भरोसे का स्तर यह था कि ब्रिटेन में मौजूद जासूसों की टीम, जिसे कैंब्रिज फाइव के नाम से जाना जाता था, से भी ज्यादा विश्वास नॉरवुड की खबरों पर किया जाता था. वालिसी ने यह भी बताया कि कई ब्रिटिश अधिकारियों को नॉरवुड के कार्यों के बारे में शक हो गया था लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. जब उनके कार्यों के बारे में नॉरवुड से पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इस बात कोई गम नहीं है. उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कुछ किया वह एक ऐसे नए सिस्टम के बारे में किया जो गरीबों को लेकर काम कर रहा था. वह गरीबों को शिक्षा दिलाने और उन्हें भोजन दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था. इस वजह से मैंने उसकी मदद की. नॉरवुड का मानना था कि सावियत रूस ऐसे गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहा था जो पूंजीवाद की वजह से अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे. वे ये भी कहती थीं उन्होंने जासूसी के काम के लिए कभी सोवियत से कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की यह काम उन्होंने सिर्फ विचाराधारा के समर्थन में किया. वे सावियत रूस में लेनिन की अगुवाई में लाई गई रूसी क्रांति की समर्थक थीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

नमाज पढ़ रहे लोगों को मौत के घाट उतारा

उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में बोको हराम के आतंकवादियों का आतंक जारी है. आतंकियों ने यहां के एक गांव में हमला कर करीब 150 लोगों की हत्या कर दी. बताया जा रहा है आतंकियों ने घरों और मस्जिदों पर हमला किया और लोगों को मौत केघाट उतारना शुरू किया. शवों की गिनती करने वाले कुकावा गांव केकोलो नाम केएक निवासी ने बताया कि हमलावरों ने कम से कम 100 लोगों की हत्या कर दी है. हमले का गवाह रहे एक मछुआरे ने मरने वालों की संख्या 150 बताई. मैदुगुरी से बचकर निकले एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी बाबामी अलहाजी ने बताया कि हमला बोरनो राज्य की राजधानी में हुआ और 50 से अधिक आतंकवादियों ने गांव पर हमला बोल दिया था. आतंकियों ने लोगों को घर से निकालकर मारा इतना ही नहीं मस्जिदों पर भी उनकेद्वारा हमला किया गया और लोगों को मारा गया. उस दौरान वे लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे.

पनडुब्बी की तैनाती भारत केलिए खतरा नहीं

हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की तैनाती पर भारत की चिंताओं के बीच पीएलए केएक शीर्ष नौसेना अधिकारी ने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि ये पोत दस्युरोधी अभियानों का हिस्सा हैं. शंघाई नेवल गैरीसन के चीफ ऑफ स्टाफ वेई शियानदोंग ने कहा कि दस्युरोधी अभियानों में पनडुब्बियां क्यों भाग नहीं ले सकतीं. अन्य बेडों केसाथ साथ पनडुब्बियां भी दस्युरोधी अभियानों में भाग ले रही हैं. उनसे पूछा गया था कि जब दस्युरोधी अभियानों के लिए विमान या युद्धपोतों की जरुरत होती है तो फिर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने ऐसे अभियानों केलिए पनडुब्बियां क्यों भेजीं. भारतीय पत्रकारों से वेई ने कहा कि ऐसे अभियानों में अलग-अलग पोतों की अलग-अलग भूमिका होती है और भविष्य में चीन तथा भारत की नौसेनाएं सहयोग एवं यात्रा को विस्तार देंगी, नौवहन खोज एवं बचाव अभियानों को अंजाम देंगी तथा दोनों देशों केबीच अधिक करीबी रिश्ते बताएंगी. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा प्रकाशित एक श्वेत पत्र हाल ही में जारी किया गया जिसकी पृष्ठभूमि में पीएलए नौसेना की हिंद महासागर में बढ़ती उपस्थिति खुले समुद्री भाग में पहली बार इसकी नौसेना केदायित्व विस्तार की नई सैन्य रणनीति को रेखांकित करती है. पिछले साल कोलंबो में और हाल ही में कराची में चीनी पनडुब्बियों की उपस्थिति से भी भारत की चिंताएं बढ़ गईं.

रोबोट ने इंसान को मारा

जर्मनी में अपने तरह की अनोखी घटना में रोबोट ने एक व्यक्ति की जान ले ली. जर्मनी की कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगेन केसंयंत्र में यह घटना घटी. किसी रोबोट द्वारा इंसान की जान लेने की दुनिया की यह संभवत: पहली घटना है. कंपनी के प्रवक्ता हीको हिलविग ने बताया कि रोबोट को तैयार करने वाली टीम में शामिल 22 वर्षीय ठेकेदार जब काम में जुटा था, तभी रोबोट ने उसे पकड़ लिया और पटक कर उसे मार डाला. घटना केलिए कंपनी ने मानवीय चूक को जिम्मेदार माना है. शुरुआती जांच केबाद कंपनी ने दावा किया है कि रोबोट में कोई गड़बड़ी नहीं थी. कंपनी का कहना है कि उस दौरान एक और ठेकेदार वहां मौजूद था किंतु रोबोट ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. उन्होंने बताया कि कार की असेंबलिंग केविभिन्न कामों के लिए रोबोट तैयार किया गया है. आम तौर पर वह एक सीमित क्षेत्र में काम करता है. उसका काम ऑटो पार्ट्स को पकड़ना और उन्हें जोड़ना होता है. प्रवक्ता ने इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी देने से इंकार कर दिया और कहा कि अभी जांच चल रही है. जर्मनी की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अभियोजक यह विचार कर रहे हैं कि इस मामले में क्या आरोप दाखिल किया जाए और यदि ऐसा किया भी जाए तो किसकेखिलाफ.

लखवी पर भारत से बातचीत करेगा चीन

मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकी-उर रहमान लखवी केमसले पर उभरे गहरे मतभेद को खत्म करने केलिए चीन ने भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा था, जिसे चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर रोक दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे को चीनी नेतृत्व केसमक्ष उठाया था. बीजिंग की ओर से अब जाकर इस पर बयान आया है. विदेश मंत्रालय केदक्षिण एशियाई विभाग केउप-महानिदेशक हुआंग शिलियान केमुताबिक दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं. उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद केहर रूप का विरोध करते हैं, लेकिन बहुपक्षीय मंच पर इसे उठाने से पहले व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत होती है. इस मसले पर हमें और बात करने की जरूरत है, ताकि दोनों पक्षों केबीच बेहतर समझ बन सके व उस पर बेहतर तरीकेसे काम किया जा सके. ■

ग्रीस आर्थिक संकट

आमदनी अट्ठनी, खर्च रुपया का नतीजा

शफीक आलम

ग्री स या यूनान को पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थान कहा जाता है. लेकिन आज यह दीवालिया होने वाला विश्व का पहला विकसित देश बन गया है. यह सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है. इसकी शुरुआत वर्ष 2009 के आखिरी दिनों में ही हो गई थी. जिसके लिए बहुत हद तक 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी जिम्मेदार थी. वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया जूझ ही रही थी कि ग्रीस की आर्थिक समस्या ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया था. 2010 के आते ग्रीस दीवालिया होने की कगार पर पहुंच गया. जिसकी वजह से एक नए वैश्विक आर्थिक संकट की आशंका व्यक्त की जाने लगी. इस संकट से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष(आईएमएफ), यूरोपीय सेंट्रल बैंक और यूरोपियन कमीशन (जिसे ट्रोइका भी कहा जाता है) ने ग्रीस केलिए 240 अरब यूरो केदो बेलआउट पैकेज दिए. ये बेलआउट पैकेज ग्रास को इस शर्त पर दिए गए थे कि ग्रीस अपने खर्च में कटौती करेगा. टैक्स कलेक्शन की प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ कर चोरी रोकने केउपाय करेगा और व्यापार केलिए देश में बेहतर माहौल बनायेगा. इस पैकेज का मक़सद ग्रीस को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त समय मुहैया करवाना भी था. लेकिन इन कदमों के कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आए. इसके उलट पिछले पांच वर्षों में ग्रीस की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई. दरअसल इस पैकेज में मिली राशि का उपयोग ग्रीस ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के बजाये अंतरराष्ट्रीय क़र्ज़ चुकाने में लगा दी. लेकिन इसकेबावजूद क़र्ज़ का बोझ ज्यों का त्यों बना रहा. बहुत से अर्थशास्त्री और ग्रीस के नागरिक खर्च में कटौती के उपायों और मितव्ययता को आर्थिक संकट केलगातार जारी रहने का कारण मानते हैं. जबकि जर्मनी जैसे कर्जदाता यह आरोप लगते हैं कि एथेंस ने बेलआउट पैकेज से संबंधित समझौतों का पालन नहीं किया इसलिए यह स्थिति पैदा हुई है.

बहरहाल, ग्रीस के मौजूद हालात की वजह देश की पेंशन पॉलिसी, सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ, शीघ्र सेवानिवृति, अत्यधिक बेरोज़गारी और कर चोरी आदि शामिल हैं. जहां तक पेंशन पर खर्चे का सवाल है तो यूरोस्टेट 2012 के आंकड़ों केमुताबिक ग्रीस अपनी कुल आमदनी का 17.5 फीसद पेंशन पर खर्च करता था, जो कटौती केबाद भी 16 प्रतिशत था. सरकार अपने कर्मचारियों को अनेक तरह केलाभ देती थी, जैसे पिता की मृत्यु केबाद भी उसकी अविवाहित पुत्री पेंशन का लाभ उठा सकती थी. इस पॉलिसी को 2010 में समाप्त कर दिया गया था. जो कर्मचारी समय पर अपने काम पर आते थे उन्हें बोनस देने का प्रावधान था. उसी तरह जल्द सेवानिवृति केबाद भी पेंशन की सुविधा बहाल रखने का प्रावधान था. इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक तंगी केबाद ग्रीस में बेरोज़गारी की दर 25 प्रतिशत से अधिक हो गई. हालात ऐसे हो गए कि सरकार पेंशन भोगियों को भी पेंशन उपलब्ध कराने में असमर्थता महसूस करने लगी. अखबारों में छपी रिपोर्टों केमुताबिक बैंक बंद हो रहे हैं. लोग एटीएम से 66 यूरो से अधिक की निकासी नहीं कर सकते. कई अर्थशास्त्री इसकेलिए पिछले पांच वर्षों से चल रहे मितव्ययिता केउपाय को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं. यूरोपियन यूनियन ने इस संकट के लिए देश की कर टैक्स पॉलिसी को जिम्मेदार मान रहा है. उसका कहना है कि ग्रीस अपने नागरिकों से कर उगाही करने में असफल रहा है. इन सभी परिस्थितियों का नतीजा यह हुआ कि ग्रीस का कर्ज कुल उसकी जीडीपी का 177 प्रतिशत हो गया है.

वर्ष 2001 में काफी विचार विमर्श केबाद ग्रीस यूरोपियन करेंसी जोन (यूरोजोन) में शामिल हुआ था. इसके बाद देश में निवेश की वजह से जबरदस्त आर्थिक उछाल आया था. इसी बीच साल 2004 में एथेंस में ओलिंपिक खेलों का आयोजन भी हुआ. कुछ विशेषज्ञ ओलिंपिक को भी इस देश की आर्थिक संकट का कारण मानते हैं. बहरहाल, विश्व आर्थिक मंदी ने साल 2009 के आखिरी दिनों में अपना असर दिखाना शुरू किया. चूंकि ग्रीस यूरोपियन यूनियन का सबसे गरीब और सबसे अधिक कर्ज में डूबा हुआ देश था इसलिए इस मंदी कि मार यहां अधिक महसूस की गई और साल 2010 के आते-आते देश को आर्थिक सहायता की जरुरत महसूस होने लगी. जिसपर आईएमएफ, यूरोपीयन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन कमीशन की ट्रोइका ने 240 अरब यूरो का कर्ज दिया. 30 जून,2015 तक ग्रीस द्वारा आईएमएफ को 1.7 अरब यूरो का क़र्ज़ लौटना था, जिसे वह समय सीमा बीत जाने केबावजूद नहीं लौटा सका. इसकेसाथ ही ग्रीस आईएमएफ का कर्ज़ न चुकाने वाला पहला विकसित यूरोपीय देश बन गया. बहरहाल इस संबंध में यूरोपियन यूनियन और ग्रीस केबीच चल रही वार्ता भी नाकाम हो गई. इसके बाद जर्मनी सहित दूसरे कर्ज दाताओं ने ग्रीस को और कर्ज देने से इंकार कर दिया है. कर्जदाता देशों की तरफ से ग्रीस से आर्थिक नीतियों में मूलभूत परिवर्तन करने को भी कहा गया. जिसकेजवाब में अब ग्रीस की वामपंथी सरकार बेलआउट पैकेज के बदले मितव्ययिता बरतने पर जनमत संग्रह करा रही है. लेख लिखे जाने तक प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास का पक्ष भारी था. यदि जनमत संग्रह में उनकी सरकार असफल रहती है तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिप्रास अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. 5 जुलाई को होने वाला यह जनमत संग्रह देश के आर्थिक और राजनीतिक भविष्य का भी फैसला करेगा.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सिप्रास की सरकार मितव्ययिता केसवाल के मुद्दे पर ही सत्ता में आई थी. सिप्रास का कहना था कि सत्ता में आने केबाद उनकी सरकार नए सिरे से बेलआउट पैकेज पर बातचीत करेगी. लेकिन हालिया बातचीत की नाकामी का और क़र्ज़ दाता देशों केसख्त रुख के बाद प्रधानमंत्री सिप्रास ने ऋणदाता देशों केसमक्ष कुछ नए प्रस्ताव रखे हैं. एक अख़बार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस के प्रधानमंत्री उन सभी शर्तों को मानने केलिए तैयार हैं जो बातचीत की नाकामी का कारण बने थे. जहां तक ग्रीस केकर्ज संकट के अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले परिणामों का सवाल है, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव यूरोपियन यूनियन और उसके सदस्य देशों पर पड़ने की आशंका है. यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक संघ है. साल 1999 में संघ के देशों ने यूरोपियन संट्रल बैंक के तत्वाधान में एक साझी मुद्रा (यूरो) जारी करने पर सहमती जताई थी, लेकिन बजट और टैक्स पॉलिसी को संबंधित देशों पर छोड़ दिया था. 2009 में ग्रीस क़र्ज़ संकट के शुरू होते ही अधिकतर अंतरराष्ट्रीय बैंकों और निवेशकों ने अपने ग्रीक बांड बेच दिए थे इसलिए ग्रीस में होने वाले आर्थिक संकट से वे प्रभावित नहीं होंगे. वहीं पुर्तगाल, आयरलैंड, और स्पेन जैसे देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों में मूलभूत परिवर्तन किए हैं, इसलिए वे भी मौजूदा संकट से प्रभावित होने से बच जायेंगे. लेकिन जब तक इस संकट का हल नहीं हो जाता है तब तक यूरोपियन यूनियन और यूरो के भविष्य पर खतरा मंडराता रहेगा. ■

ग्रीस संकट का भारत पर प्रभाव

कुछ दिनों पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि ग्रीस संकट का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रीस केदीवालिया घोषित होने के बाद राजन ने आशंका व्यक्त की है कि ग्रीस संकट की वजह से रुपये पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है. भले ही भारत का यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के मामले सीमित प्रत्यक्ष निवेश है. साथ में यह भी आशंका जताई जा रही है कि ग्रीस के आर्थिक संकट की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों के बाजारों से पूंजी बाहर जाएगी. इस वजह से भारत को सावधान रहने की जरूरत है. भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रीस से बहुत अधिक संबंध नहीं है लेकिन इस संकट का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है. भारत शेयरबाजार भी इससे अछूते नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

इस बार ब्राहमण को राजा पर क्रोध आ गया. वह कुछ कहना ही चाहता था कि काम बिगड़ जाने की आशंका से चुपचाप लौट आया. घर जाकर वह राजा के आग्रह पर गंभीरता से सोचने लगा. आखिर क्या बात है, जो राजा बार-बार बड़े विश्वास के साथ कह देता है कि अभी और अध्ययन करो. जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया, तो वह पहले से भी अधिक मनोयोग से अध्ययन करने लगा. धीरे-धीरे उसे गूढ़ार्थ स्पष्ट होने लगा. परिणाम स्वरूप धन और यश-लिप्सा से उसे विरक्ति होने लगी. उसका अहं भाव घटने लगा. वह राजा के आश्रय में जाना ही भूल गया.

साई की आराधना श्रद्धा और सबूरी के साथ करनी चाहिए

चौथी दुनिया ब्यूरो

क्या *सदगरु से सांसारिक मांगे करना अनुचित हैं?*

बाबा भक्तों की मांगों को पूरी करते रहे और आज भी पूरी कर रहे हैं, जिसका अनुभव असंख्य लोगों को है. श्री साई ने इस प्रकार की मागों की पूर्ति के लिए आनेवाले भक्तों को कभी हतोत्साहित नहीं किया. एक बार जब श्री साई के एक भक्त ने इस प्रकार की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आनेवाले भक्तों के बारे में पूछा तो श्री साई ने कहा कि प्रारम्भ में मेरे भक्त ऐसे ही कारणों से आते हैं. तत्पश्चात जब उनकी ये इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में स्थिरता आ जाती है, तो वे मेरा अनुगमन कर आध्यात्मिक दिशा में प्रगति करते हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि बाबा सांसारिक विषयों की मदद प्राप्त करने से बढ़कर आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी मांगों को बढ़ाते चले जाएं और आध्यात्मिक प्रगति को गौण विषय बनाएं. जो लोग वस्तुवादी आवश्यकताओं को सीमित रखकर, अपने जीवन में दुख को सहकर बाबा से केवल आध्यात्मिक उन्नति मांगते हैं, ऐसा समझा जाएगा कि वे एक उच्चतर सोपान पर पहुंच चुके हैं.

इस प्रकार के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाबा उनकी मदद करते हैं, यह मेरा अनुभव है. प्रगति के रास्ते पर चलने वाली इस आध्यात्मिक उन्नति की अभिलाषा को बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु इस विचार एवं मन में बाबा को धारण करते हुए जो सबूरी के साथ चलते रहते हैं, वही अंततोगत्वा लाभवान होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि एक दो साल मंदिर जाकर पूजा करने से, लंगर लगाने से या अन्य कुछ कार्य करने से आध्यात्मिक प्रगति के सोपान में पहुंच जाएंगे, तो उनकी ऐसी धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि यह लोग अपने द्वारा परिकल्पित इच्छा, परिकल्पित समय के अंदर पूरी नही होने से फिर अन्य रास्तों की तलाश में लग जाते हैं. इसलिए बाबा की सेवा करते समय ऐसी इच्छाएं बाधक बन सकती हैं.

पश्चाताप

क्या पश्चाताप करने पर ईश्वर-कृपा या गुरु-कृपा प्राप्त होती है?

अच्छे इंसान के हृदय में भगवान मेहमान बनते हैं. स्वच्छ हृदय से भक्ति के साथ निरंतर आह्ववान करने पर ईश्वर-शक्ति या गुरु-शक्ति का हृदयपीठ पर अवतरण होता है. वास्तव में कृपा शब्द का अर्थ यही है. जब एक बार यह कृपा-स्त्रोत प्रवाहित होता है, तो फिर रुकता ही नहीं. हां यह जरुरी है कि व्यक्ति द्वारा ही अपनी मंदबुद्धि से प्रेरित भावनाओं से अपने अतं:करण को अपवित्र करने पर उस कृपा-शक्ति की गाति बाधित हो जाती है. यह दिव्य-शक्ति- स्त्रोत रुक जाने पर उस व्यक्ति का आनन्द भाव विलुप्त हो जाता है और वह फिर भव-जंजाल में फंसकर पश्चाताप करने लगता है. पश्चाताप का अर्थ है- मन और चित्रवृति का शोधन करना. जब पश्चाताप की आग से उसके मन का मैल जलकर राख हो जाता है. तब फिर से गुरु-शक्ति, या ईश्वर-शक्ति अबाधित गाति से उसमें प्रवाहित होने लगती है. पश्चाताप का सही अर्थ यह है कि वे कर्म जिनके लिए वह पश्चाताप करता है, उनको पुन: न दोहराए.

आत्म-विश्लेषण

आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए इस बात को जान लेना अनिवार्य है कि आत्मविश्लेषण सदगुरु की कृपा द्वारा ही संभव है. उनकी कृपा के कारण ही व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ता है. इसके लिए उनके प्रति असीम श्रद्धा और धैर्य रखते हुए अपने हृदय को पूर्णत: शांत रखना होगा. ऐसे में अपनी किसी भी व्यक्तिगत इच्छा या भावना का त्याग करना होगा. क्या हमें अच्छा लगता है और क्या नहीं. इस भावना से अपने को दूर रखना होगा क्योंकि आत्मविश्लेषण करते समय अपनी किसी व्यक्तिगत भावना के आते ही उद्वेग उत्पन्न होने की सम्भावना होती है. जिससे सूक्ष्म भावदशा बिगड़ जाती है. ऐसे में अपने को पूर्णत: सद्गुरु को सौंपना होगा, ताकि उनकी बात सुन सकें और वे हमें सत्य मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता पहुंचा सकें. भीतर से भाव को वैसे ही नष्ट कर देता है, जैसे खेतों को बाढ़ नष्ट कर देती है. अत: मनमुखी न होकर गुरुमुखी होना चाहिए क्योंकि उससे व्यक्ति आत्ममुखी होता है और उसके भीतर आध्यात्मिक भाव-तरंग उत्पन्न होती है, फिर दृश्यमान एवं अदृश्यमान शक्तियों का द्वारा गुरु अपने शिष्य को प्रभावित करते हुए उसे मानसी स्थितियों से निकालकर ईश्वरमुखी करते हैं.

आस्था और सहजता

अंधेरे में हम रहने वाले उजाले की पहली किरण जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं और वापिस अंधेरे में जाना चाहते हैं. उस समय हम क्या करें? सद्गुरु किसी भी परिस्थिति में अपने भक्तों को छोड़ नहीं सकते चाहे भक्त इसको अनुभव कर सकें या न कर सकें. इसी कारण बाबा ने कहा था कि श्रद्धा और सबूरी के साथ उनकी आराधना करनी चाहिए. जब भी किसी व्यक्ति ऊपर साई-कृपा होती है, तो प्राय: यह देखने को मिलता है कि वह अपने हो हवाश खो बैठता है. उन प्रथम अनुभवों से कुछ पा गए हैं या आध्यात्मिक ज्ञान पा चुके हैं. वे यह समझ बैठते हैं.

इस प्रारंभिक अवस्था को आखिरी अवस्था समझकर इस प्रकार व्यवहार करने लगते हैं. बहुत से लोग इस कारण प्रगति न कर पाते. और जीवन को एक नाटकीय रूप से बिताने का प्रयास करते हैं. कुछ दिन बाद किसी कारण और उन्हें विपत्ति घेरती है, तो फिर से दूसरी ओर मुड़ जाते हैं. कुछ लोगों की ऐसी परिस्थिति में कई प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिली है. कच्चे घड़े में पानी जैसे उसे तोड़ देता है. उसी प्रकार उनकी आस्था अतिशीघ्र टूट जाती है. जो व्यक्ति बाबा की कृपा प्रथम बार प्राप्त करने के बाद अपने को सामान्य स्थिति में रखते हैं और भक्ति का प्रर्दशन नहीं करते हैं, वह धीरे-धीरे बाबा की निकटता पा लेते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

ऐसे नहीं खत्म होगा भ्रष्टाचार

कवर स्टोरी-ऐसे लोकायुक्तों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा (29 जून -05 जुलाई 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. मनीष कुमार ने सही कहा है कि जब अन्ना हजारे लोकपाल और लोकायुक्त के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो कई लोगों को लगता था कि लोकपाल और लोकायुक्त बनते ही देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है. लोकायुक्त के एक फैसले के कारण एक विधायक की विधानसभा की सदस्यता चली जाती है और जब मामला सुप्रीमकोर्ट के पास जाता है, तो पता चलता है कि लोकायुक्त द्वारा लिया गया फैसला ही गलत था. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर सुप्रीमकोर्ट न होता तो विधायक को लोकायुक्त के गलत फैसले की कीमत उसे अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवा कर चुकानी पड़ती, जिसे सुप्रीमकोर्ट ने बहाल किया. इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकारों की नीयत सही होनी चाहिए. अगर सरकारों की नीयत सही होगी, तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा.

-विश्वजीत सिंह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश.

चन्द्रशेखर जी मिसाल थे

आलेख-चंद्रशेखर जी सादगी और ईमानदारी की मिसाल हैं (29 जून -05 जुलाई 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तजेक है. मुलायम सिंह ने सही कहा है कि चन्द्रशेखर जी का आचरण, सादगी और ईमानदारी एक मिसाल हैं. चन्द्रशेखर जी की सादगी और ईमानदारी हमेशा संसद के भीतर भी दिखाई देती थी. चन्द्रशेखर जी हमेशा दूसरों का सम्मान करते थे. जब वे प्रधानमंत्री थे, तो सभी की बात सुनते थे. सत्ता का लालच उनके मन में कभी भी नहीं था. चन्द्रशेखर जी की सरकार के दौरान कांग्रेस प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री कमल मोरारका को हटाने की मांग कर रही थी. लेकिन चन्द्रशेखर जी ने बिना सत्ता का लालच किए कांग्रेस की इस मांग को खारिज कर दिया. आज के नेताओं को चन्द्रशेखर जी सीखने की जरूरत है.

-वीर बहादुर सिंह, बलिया, उत्तर प्रदेश.

खतरे में पत्रकारिता

रिपोर्टस विदआउट वॉड्स की प्रेस फ्रीडम सूची में भारत 180 में 136वें पायदान पर है, लेकिन जिस तरह शाहजहांपुर में एक निर्भीक स्वतंत्र पत्रकार जगेन्द्र सिंह की आग लगाकार हत्या कर दी गई तथा पीलीभीत में एक टी.वी चैनल के पत्रकार को मोटर साइकिल से बांधक घसीटा गया, उससे हिन्दी भाषी छोटे शहरों में पत्रकारिता की मुश्किल को समझा जा सकता है, यद्यपि पत्रकारिता के बहुआयामी विस्तार से इस क्षेत्र में कुछ दलालों का भी प्रवेश हो गया, जिसके कारण पत्रकारिता बदनाम हो रही है. लेकिन उसकी आड़ में सच को उजागर करने वाले निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारों पर लगातार प्रताड़ना व हमलों से पत्रकारिता खतरे में है. पत्रकारति को हल हाल में बचाया जाना चाहिए.

-सत्य प्रकाश शिक्षक, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

बैंक मैनेजर्स को जेल भेजा जाए

बैंकों का एन.पी.ए प्रबंधन फिसड्डी साबित हो चुका है. मार्च 2015 तक भारीतय बैंकों का सकल अरबों तक पहुंच चुका है, पर मूल बिन्दु पर किसी का ध्यान नहीं है. एन.पी.ए का अर्थ वह कर्ज है, जो वसूल नहीं हो पा रहा है. कर्ज वही वसूल नहीं हो पाता जो बैंक प्रबंधक व ऋणी की दूरामी संधि के चलते दिया जाता है. बैंक को अधिकार है कि वह ऋण लेते समय ऋणी ने बैंक के पास जो भूखंड/कृषि भूमि मकान बंधक रखा है, उसे नीलाम कर अपनी पूंजी वसूल ले, उदाहरण के तौर पर अगर रमेश ने बैंक प्रबंधन को रिश्वत देकर सुरेश के दस्तावेजों पर ऋण लिया, तो बैंक सुरेश की जमीन तो नीलाम कर नहीं सकता. अभी तक यही होता आ रहा है कि जो ऋण वसूल नहीं हो पा रहा है उसे एन.पी.ए में डाल दो. जिस ऋण को जिस बैंक मैनेजर ने स्वीकृत किया है, उस प्रबंधक की जमीन, प्लांट, मकान, गाड़ी नीलाम कर सरकार अपनी पूंजी वसूले तथा उस भ्रष्ट प्रबंधक को जेल भेजे

-राजकिशोर पांडेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

जातिवाद के सहारे राजनीति

नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस जाति के थे या फिर लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जाति क्या थी? बिहार की राजनीति के संदर्भ में इन सवालों में कोई प्रतिकुलता नहीं है. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में जुट गये हैं, तो दूसरी ओर वे जाति के सहारे भी अपनी राजनीति साधने में लगे हैं. इनमें लगभग सभी दल शामिल हैं. खास बात यह है कि राजद जिस पर जातिवाद करने का आरोप परंपरागत तौर पर लगता रहा है, उसने अभी तक जाति के आधार पर सार्वजनिक स्तर पर कोई भी कार्यक्रम करने से परहेज किया है.

-नवल कुमार, ई-मेल के द्वारा.

सच्चा ज्ञान

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक राजा था. उसी राज्य में एक ब्राहमण भी था. एक दिन वह ब्राहमण राज-दरबार में जा पहुंचा. राजा ने उसके आने का प्रयोजन पूछा. ब्राहमण ने कहा, महाराज, मैने धर्मग्रंथों का गहन अध्ययन किया है. मैं आपको भागवत पढ़ाना चाहता हूं. ब्राहमण की बात सुनकर राजा मुस्कराया. उसने सोचा जिसने भागवत या अन्य धर्मग्रंथों का अध्ययन किया होगा. वह आत्म-चिन्तन करेगा, जगह-जगह अपनी विद्वता नहीं जताएगा. उसने ब्राहमण से कहा, आचार्य, मेरे विचार से अभी आपको और भी गहन अध्ययन-मनन की आवश्यकता है. राजा का यह कथन ब्राहमण को एकदम अपमानजनक लगा. उसने सोचा कि यह राजा तो निट मूर्ख है. भला, जिसने भागवत का एक-एक शब्द रटा हो, उसे और अधिक अध्ययन की क्या आवश्कता! पर चूंकि उसे राजा के यहां नौकरी चाहिए थी, अत: वह चुपचाप अपनी कुटिया पर लौट आया. वह औ भी मनोयोग से भगवत आदि ग्रंथो का अध्ययन करने लगा. कुछ दिन बाद वह फिर राज-दरबार में उपस्थित हुआ. राजा ने उसे फिर वही उत्तर दिया. इस बार ब्राहमण को राजा पर क्रोध आ गया. वह कुछ कहना ही चाहता था कि काम बिगड़ जाने की आशंका से चुपचाप लौट आया. घर जाकर वह राजा के आग्रह पर गंभीरता से सोचने लगा. आखिर क्या बात है, जो राजा बार-बार बड़े विश्वास के साथ कह देता है कि अभी और अध्ययन करो. जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया, तो वह पहले से भी अधिक मनोयोग से अध्ययन करने लगा. धीरे-धीरे उसे गूढ़ार्थ स्पष्ट होने लगा. परिणाम स्वरूप धन और यश-लिप्सा से उसे विरक्ति होने लगी. उसका अहं भाव घटने लगा. वह राजा के आश्रय में जाना ही भूल गया. जब बहुत दिनों तक राजा के उस ब्राहमण के दर्शन न हुए, तो वह उसे खोजने निकला. बहुत दौड़-धूप के बाद उसे वह ब्राहमण मिल ही गया. ब्राहमण भौतिक आकर्षणों से परे जा चुका था. राजा ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, आचार्य, मैं आपका शिष्य बनने आया हूं. मुझे अपनी शरण में लें. अब आप धर्मग्रंथों के पारंगत विद्वान बन चुके है. ब्राहमण ने उत्तर दिया, राजन आपको ज्ञान के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. सच्चा ज्ञान तो आपने मुझे दिया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

संगीतकारों की मदद की पहल

अनंत विजय

भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को जब एक बार कोई पुरस्कार मिला था, तो उन्होंने कहा था कि सम्मान और पुरस्कार से कोई फ़ायदा नहीं होता है. इसके स्थान पर यदि धन मिल जाता, तो बेहतर होता. बाद में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला, लेकिन उनकी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उनके जीवनकाल तक बहुत बेहतर नहीं हो पाई. बनारस में उनसे मिलने जाने वाले उनकी मृत्यु के कई साल बाद तक उनकी आर्थिक बदहाली और कला के इस महान साधक की पीड़ा के बारे में बातें करते रहते थे. कुछ इसी तरह की बात रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी कही जाती है. उन्हें जब साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तब उन्होंने संभवत: अपनी डायरी में लिखा था या किसी से कहा था कि चलो, पुरस्कार की राशि से उनके घर की एक लड़की का ब्याह हो जाएगा. भारत रत्न बिस्मिल्ला खां और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बयान में शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन भाव लगभग एक समान है. एक पुरस्कार में धन की आकांक्षा कर रहा है, तो दूसरा पुरस्कार में धन मिलने से इस वजह से खुश है कि घर की एक बेटी का ब्याह हो जाएगा. एक भारत रत्न से सम्मानित कलाकार और दूसरा राष्ट्रकवि. यह सोच कल्पना से परे है कि जब इतने बड़े कलाकार और लेखक की यह स्थिति है, तो मंझोले एवं छोटे कलाकारों, लेखकों की आर्थिक स्थिति कैसी होगी? क्या हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारे कलाकार इतने समर्थ नहीं हो पा रहे हैं कि वे अपने हुनर के बूते एक सम्मानित ज़िंदगी जी सकें. हम लाख अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की बात करें, लाख इस बात का ढिंढोरा पीटें कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी कला विश्व में श्रेष्ठ है, लेकिन अगर यह श्रेष्ठ कला कलाकारों को सम्मान से जीने लायक माहौल और धन मुहैया नहीं करा पाती है, तो फिर उसका कोई अर्थ रह जाता है क्या? इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है.

यह भी कहा जाता है कि कलाएं संरक्षण में ही फलती-फूलती और विस्तार पाती हैं. हमारे देश में कलाओं को राजाओं ने खूब सहेजा. आज़ादी के बाद जब रजवाड़े ख़त्म हुए, तो कलाकारों एवं कलाओं को संभालने का ज़िम्मा भारत सरकार पर आ गया. भारत सरकार में अलग से संस्कृति मंत्रालय का गठन हुआ, कला अकादमियां बनाई गईं. हमारे देश का संस्कृति मंत्रालय अवश्य हर साल कलाकारों को कुछ फेलोशिप देता है, लेकिन वह राशि पर्याप्त नहीं है और न पर्याप्त है फेलोशिप की संख्या. फिर उसमें जिस तरह से चयन होता है, वह भी बहुधा सवालों के घेरे में आता रहता है. साहित्य और कला अकादमियों का हाल सबके सामने है. ये अकादमियां चंद अफसरों की ज़मींदारी बन गई हैं, जहां कलाकारों के बजाय उन अफसरों का भला होता है. ललित कला अकादमी में पिछले दिनों जिस तरह से भ्रष्टाचार के गंभीर मसले सामने आए, उससे तो साफ़ हो गया है कि कला के विकास के नाम पर उस संस्था में लंबे समय से लूट चल रही थी. स्वायत्तता का ढोल पीटने वालों ने उसकी आड़ में ललित कला अकादमी में जमकर मलाई काटी. कलाकार बेचारा ग़रीब रहा. साहित्य अकादमी का हाल भी सबके सामने है. इस बात की पड़ताल होनी चाहिए कि हमारे देश में कलाकारों और साहित्यकारों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? सरकार को भी इस दिशा में व्यापक विमर्श के बाद एक ठोस और नई सांस्कृतिक नीति बनानी चाहिए, जिसमें कलाकारों और साहित्यकारों की आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए. इस वक्त तो हालत यह है कि कई कलाकार गुमनामी में अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं और गुमनामी में ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. भारत कला और संगीत को लेकर भी बहुत समृद्ध है, लेकिन उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और फिर उसे बढ़ाने में हम लगभग नाकाम रहे हैं.

संगीत हमारे समाज में जन्म से लेकर शवयात्रा तक का अंग है, अलग-अलग रूपों में. जीवन में संगीत की इस अहमियत को हम नहीं समझ पा रहे हैं, लिहाजा संगीतकारों को उचित सम्मान तो कभी-कभार मिल भी जाता है, लेकिन उन्हें आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है. इन्हीं स्थितियों की अभिव्यक्ति बिस्मिल्ला खां और दिनकर के कथन में मिलती है. हाल के दिनों में संगीतकारों की मदद के लिए कुछ निजी प्रयास शुरू हुए हैं. इन्हीं प्रयासों में से एक है संगीतम संस्था का एक प्रयास रहमतें. इस कार्यक्रम में देश भर के पचास ज़रूरतमंद कलाकारों को एक लाख रुपये का जीवन बीमा कराकर दिया जाता है. पिछले साल मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में जितना पैसा इकट्ठा किया गया, वह संगीतकार खैय्याम और ग़ज़ल गायक राजेंद्र मेहता को दिया गया. इसके अलावा कई ज़रूरतमंद और युवा कलाकारों को भी संगीतम मदद करता है. अच्छी बात यह है कि कवयित्री स्मिता पारिख के इस प्रयास में गायक हरिहरन, भजन सम्राट अनूप जलोटा और ग़ज़ल गायक तलत अजीज का सहयोग हासिल है. स्मिता के साथ सौरभ दफ्तरी भी कलाकारों की मदद की मुहिम में जोर-शोर से लगे हैं. इस तरह के निजी प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए. इस साल भी मुंबई में जगजीत सिंह की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम रहमतें से होने वाली आय से कलाकारों की मदद की जाएगी. देश भर के ज़रूरतमंद कलाकारों की सूची विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाती है.

स्मिता और सौरभ दफ्तरी के इस साझा प्रयास की तरह इस मुहिम को देश भर में फैलाने की ज़रूरत है. अब अगर हमें बिहार की मधुबनी पेंटिंग को बचाना है, तो उसके कलाकारों को आर्थिक मदद देनी होगी. अगर उस कला को वैश्विक मंच देना है, तो उसके लिए राज्य सरकार के अलावा निजी कारोबारी संस्थाओं को भी अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह के तहत आगे बढ़कर काम करना होगा. अगर भारत में संगीत और कला को आगे बढ़ाकर कलाकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, तो इसके लिए सरकार, निजी संस्थाओं और कारोबारी समूहों को साझा तौर पर काम करना होगा. इसके अलावा ललित कला अकादमियों एवं साहित्य अकादमी को अफसरों और ग़ैर साहित्यकारों-कलाकारों के चंगुल से मुक्त करना होगा. अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो यह एक बेहतर स्थिति होगी, अन्यथा भारत रत्न से सम्मानित कलाकार भी मुफलिसी में ज़िंदगी बिताने और ग़रीबी में मौत को गले लगाने के लिए अभिशप्त रहेगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

कहानी

दोराहे

सला जानकीदास! समझता क्या है अपने आपको? स्टीयरिंग पर सुचित्रा रंगनाथन की पकड़ कस गई. चेहरे की त्वचा की ओट से तनाव की लकीरों ने फिर झांका. ट्रैफिक हाजी अली से बांद्रा के लिए घूमते सिग्नल पर उतर गया था. लेकिन दिमाग? जैसे शांत स्थिर झील में कोई चट्टान टूटकर गिरी हो.

अपनी नालायकी छुपाने के लिए कितनी आसानी से कोई आपकी पूरी शख्सीयत को ही संदेह के घेरे में डाल देता है. आपकी चूलें हिल जाएं, उसकी बला से...चिपटने के लिए वह फिर कोई दामन ढूंढने लगेगा...जवां गुदाज और मादक...पर अदाकारी...उसका तुम क्या करोगे जानकीदास...तुम्हारी दलाली से वे तो नहीं आ जाएगी, केवल फिगर और ताजे जिस्म वाली किसी गुड़िया में!

सुचित्रा रंगनाथन ने घोर नफ़रत से सिर को एक झटका दिया. सिग्नल खुल गया था. बायां हाथ स्वत: गेयर बदलने लगा था. पैर एक्सलेटर दबाने को बेचैन. आसमान में घने बादल थे.

...घर लौटकर आदमकद आईने में चेहरा देखने को हिम्मत नहीं हुई. क्या सही कह रहा था जानकीदास?...पिछली चार-पांच फिल्मों की नाकामयाबी और टूटते प्रेम संबंधों ने वाकई क्या उसके चेहरे की रौनक छीन ली है? वह पलटकर धम्मड़ से बिस्तर पर औंधे पर मुंह गिर पड़ी. बाहर तेज बरसात होने लगी थी. पर शरीर में, दिल में इस समय आग लगी हुई थी.

-मैडम, मैं सही कह रहा हूं. इस पूरे एपीसोड में क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता.

- 'लेकिन आप मेरे सेक्रेटरी हैं. वह भी इतने सीनियर. फिर भी प्रोजेक्ट में मेरी जगह हेलेना मीरचंदानी के नाम की चर्चा का मतलब? आप काम नहीं करते बस सोते हैं? फिर आपको पैसा भला मैं किस बात का देती हूं?'

-'देखिए मैडम, जब मैंने आपका काम हाथ में लिया था तब आप बेशक फिल्में कर रही थीं, पर कैसी फिल्में? फिसलन, चुंबन, आलिंगन और मतवाली जैसी? वहां से हटाकर मैंने आपको 'जीवन संध्या', 'समर्पण', 'वास्ता', 'सुबह की धूप' और 'परछाईयों के शहर में' जैसी सोशल फिल्मों की हिरोइन बनवाया, आपको प्रोड्यूसर्स ने मेरे क्रेडिट पर साइन किया...'

... 'गलत, गलत कह रहे हैं आप जनकीदास. आपके कहने पर जिन प्रोड्यूसर्स ने मुझमें इंटरेस्ट लिया, उन्होंने दरअसल मेरी बोल्ड सस्ती फ़िल्मों के चलने के कारण ऐसा किया. अगर मैं उन फिल्मों की वजह से लाइमलाइट में न होती तो आप क्या कोई प्रोड्यूसर अपनी रखैल को भी हिरोइन नहीं बनाता, मुझे क्या बनाता?'

जानकीदास ने हैरान होकर पलकें झपकायीं, 'मतलब मेरा कोई कांट्रिब्यू शन नहीं?'

- 'मेरे ख्याल से तो कोई खास नहीं है. अगर है, तो सौमित्र चोपड़ा के इस प्रोजेक्ट में मेरी वापसी करके दिखाइए, वरना...'

...सुबह से ही फोन की घंटी बजने लगी थी, अरे ये क्या पढ़ रहा हूं या रही हूं?...टाइम्स ने, मिड डे या अमुक न्यूज पेपर ने मुख्य खबर बनाकर छापा है, 'सुचित्रा रंगनाथन इज आउट ऑफ परदा'. चिंता जताने में भी मजा लेने का अंदाज. रिसीवर उठाकर अलग रख दिया था उसने. सेलफोन ऑफ.

पर मन बेचैन था. सौमित्र की फिल्म से बड़ी उत्साहित थी वह. उसे जीवन में पहली बार अपने सबसे पसंदीदा हीरो अजय खन्ना के साथ काम करने का मौका मिल रहा था. वह भी उसके अपोजिट. इस कल्पना से रोम-रोम सिहर गया था उसका. काफी दिनों से दिल के किसी कोने में पलती हसरत के पूरा होने का वक्त. एग्रीमेंट साइन करके बताया था उसने गैरी को. गैरी को सुचित्रा की हसरत की जानकारी थी. वह नहीं चाहता था यह हसरत पूरी हो. पब में उस रात थोड़ी-थोड़ी बियर अंदर जाते ही यह सच बाहर आया था. एग्रीमेंट की बात पता होते ही गैरी ने आपा खो दिया था. काफी झगड़ा तो पब के शोरगुल में विलीन हो गया. पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था.

...देर रात पब से लौटते हुए बीच रास्ते में ही गैरी ने अपनी कार रोक दी थी, 'सुचिइइइ आय एम आस्किंग लास्ट चांस! तू एग्रीमेंट फाड़ेगी या नहीं?... या तो तुम अजय खन्ना के साथ फिल्म करोगी या फिर मेरे साथ डेटिंग! दोनों इश्क एक साथ नहीं चलेंगे डियर.'

-'हम इस पर फिर बातें करेंगे गैरी. फिलहाल तुम घर चलो. तुम्हें चढ़ गई है.' सुचित्रा रंगनाथन ने हालात संभालने की जुर्रत की.

-'ओ ऽऽऽ शटऽऽऽ प... यू एम्बीशस बिच! आय एम नॉट ड्रंक नार आय एम फूल! तुम्हारी जैसी लड़कियों की असलियत खूब जानता हूं मैं. सक्सेस और अपनी अय्याशी के लिए कहीं भी गिर सकती हैं तुम्हारे जैसी साफिस्टिकेटेड होर्स!'

- 'गैरीईईई!' सुचित्रा रंगनाथन की चीख निकली तो जरूर पर गले में ही घुट कर रही गई. गैरी ने उसका गला दबोच लिया था, 'डोंट शाउट लाइक अ स्ट्रीट होर! एंड गेट डाउन.' उसने उसे गेट खोलकर कार से नीचे उतार दिया था. बीच रास्ते में. रात के ढाई बजे, 'आइंदा मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं. जाओ अपने अजय खन्ना का बिस्तर गर्म करो. एंड गेट लॉस्ट बास्टर्ड बिच.''

उसकी गाडी चली गई थी. रात के सन्नाटे में जुहू गली के मोड़ पर अकेली लुटी-पिटी हालत में खड़ी हिरोइन सुचित्रा रंगनाथन. अपमान, लांछन, बदतमीजी की पीड़ा आंखों में पानी बनकर उभरने लगी. एक ऑटोरिक्शा वाले ने आकर रिक्शा रोका. चेतना लौटी. चेहरा घुमाकर यंत्रवत बैठ गई थी वह, 'लोखंडवाला चलो.'

हर चीज की हद होती है. गैरी ने पहले भी कई हदें तोड़ी थीं. वह बर्दाश्त करती गई थी. आखिर कितनी बार रिश्ते बदलेगी वह? हर बार जुड़ना-टूटना. फिर उस टूटन से उबरना आसान नहीं होता. गैरी से पहले के तीन रिश्ते आज तक रिसते जख्मों की तरह हैं. पर कौन मानेगा इसे? छवि तो लड़की की ही खराब होती है-मर्द बदलू लड़की की छवि. फिर नया मर्द कौन टिकेगा? हालांकि उसने कहां बदले मर्द? बदला तो मर्दों ने था उसे. तभी गैरी के मामले में वो फूंक-फूंक कर कदम उठा रही थी. पर सब धरा का धरा रह गया. तबसे गैरी की कोई सूचना नहीं. वह अपनी तरफ से तो हिम्मत भी नहीं कर सकती. कई दिनों तक कड़वाहट घुलती रही मन तन बदन में. कई तरह के ख्याल आते रहे, जाते रहे. अगर सौमित्र चोपड़ा की फिल्म छोड़ दे तो क्या गैरी वापस आ जाएगा? अगर आ भी जाए तो क्या उसका नज़रिया बदल जाएगा? वह कल फिर किसी और नाम के साथ काम करने पर आपत्ति नहीं करेगा? अब यह कोई बात हुई? अजय खन्ना की वह फैन है. इसका मतलब यही कि काम करने अवसर मिलते ही वह उसके साथ...हुंह! इनसेक्योर गैरी! तुमने सब उगल डाला. कुछ भी न छोड़ा. इससे तो बेहतर था, वह भी सिर्फ प्रोफेशनली सोचती. दूसरी लड़कियों की तरह. अपने कैरियर के बारे में. सिर्फ़.

फोन की घंटी बजते लगी थी. उधर सौमित्र चोपड़ा था. खुद. वह बेहद हैरान, 'अरे आप? कैसे अचानक? शूटिंग डेट्स बदल रही हैं क्या? जानकीदास जी ने तो कुछ भी...'

'ओ नो-नो!... नथिंग इज़ विद हिम. मुझे तो आपसे बात करनी थी. एनी डिस्टर्बेंस?'

-'कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बेसब्री से शूटिंग का इंतजार कर रही हूं.'

-'ओ.के. फाइन!...हम भी यही चाहते हैं. इसीलिए शूटिंग से पहले एक छोटा सा गेट-टुगेदर रखा है मेरे घर पर. कल शाम को क्या कर रही हैं आप? फुर्सत हो तो आए. सभी आयेंगे. अजय भी.'

-'ओह श्योर! ' वह चहकी. मूड बदल गया था. इरादा भी. क्या सिर्फ गैरी की फीलिंग्स के लिए वह कामकाज छोड़ दे?...पर गैरी जैसों का भरोसा?

सौमित्र के यहां गेट-टुगेदर में सिर्फ पांच-छह लोग ही थे. अजय खन्ना सहित. वह रोमांचित थी. थोड़ी चकित भी. सौमित्र ने तस्वीर साफ की थी 'ये बस टॉप क्रू की मीटिंग थी. इसलिए हीरो हिरोइन भी मिल लें तो अभी से अच्छा रहेगा.' वह हंसा. अजय भी. वह भी मुस्कराकर रह गई.

रात परवान चढ़ी. कमरे में दोनों अकेले रह गए. अजय और सुचित्रा. बाकी मेहमानों को विदा करने सामित्र भी बाहर निकल गया था. सुचित्रा की धड़कन तेज हुई.उत्सुकता भी. अजय ने मुस्कराकर सहज किया.

'सुना है आप मेरे साथ फिल्म नहीं करना चाहतीं? '

'अवाक होकर देखा अजय का, 'ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो फ़ैन हूं आपकी. फैन. आपकी फिल्मों को तो 'इंस्पिरिशेन' मानती हूं मैं. मेरी तो हसरत थी आपके साथ काम करने की. आज तो हसरत पूरी हो रही है. मैं तो जमीन पर हूं ही नहीं.' खुशी से आवाज रुंध गई. ■

क्रमश:

लेखक परिचय- *सलिल सुधाकर 80 के दशक के उत्तरार्ध से कथा लेखन में सक्रिय हैं. अब तक 50 से अधिक कहानियां देश की शीर्ष पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हुई हैं. अपने लेखन वैविध्य के कारण हिंदी कथा जगत में चर्चित हैं. मीडिया में कई वर्षों तक सक्रिय भागीदारी निभाई है. उपसंपादक से लेकर संपादक व ब्यूरोचीफ की भूमिका का सफलता पूर्वक निर्वहन किया. चार महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और तपते कैनवास पर चलते हुए नामक उपन्यास प्रकाशित. उपन्यास के लिए महाराष्ट्र हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित. इसके अलावा बीते कई वर्षों से अभिनय की दुनिया में चर्चित कलाकार के रूप में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते आ रहे हैं.*

feedback@chauthiduniya.com

इस फोन में शानदार सेल्फी कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए है. इस फोन को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बाजारों से खरीद सकते हैं. इस फोन का प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वॉड कोर मीडिया टेक है. इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम 5.0 लॉलीपॉप है. इस फोन 5 इंच का डिस्प्ले है, जो 720 1280 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इसके साथ ही फोन का रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल है.

क्या है क्लाउड कम्प्यूटिंग

श्याम सुन्दर प्रसाद

अगर कम्प्यूटर और इंटरनेट की बात करें, तो एक तकनीक का नाम बार-बार आता है वो है क्लाउड कम्प्यूटिंग. वैसे वर्तमान दौर की बात की जाए तो अधिकतर इंटरनेट सेवाएं किसी न किसी रूप में क्लाउड कम्प्यूटिंग से जुड़ती जा रही हैं और यही रफ्तार रही तो आने वाले समय में दुनिया लगभग सभी कार्यों के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग पर ही निर्भर होगी. आइए जानते हैं कि क्लाउड कम्प्यूटिंग क्या है? कौन सी तकनीक प्रयोग में लायी जाती हैं? इसका इतिहास कितना पुराना है? इससे जुड़ी लोगो में क्या क्या भ्रांतियां हैं और इसके फायदे क्या हैं?

क्लाउड कम्प्यूटिंग किसे कहते हैं?

क्लाउड कम्प्यूटिंग यानी डिजिटल डाटा स्टोरेज स्पेस. अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस प्रकार हम अपने कम्प्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट पर कोई फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उस डिवाइस के स्टोरेज ड्राइव का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही किस भी दूसरे डाटा को इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे जगह मौजूद कम्प्यूटर पर सेव करने की प्रक्रिया को क्लाउड कम्प्यूटिंग कहते हैं. क्लाउड कम्प्यूटिंग के नाम से कई बार लोगों को यह भी भ्रम हो जाता है कि इसके नामकरण में बादलों का भी कोई हाथ है. हालांकि इसका सीधा संबंध बादलों से तो नहीं है लेकिन इस तकनीक के बारे में अगर गहनता से समझा जाए तो यह कुछ-कुछ बादलों से मेल खाती है. इसमें फर्क केवल इतना है कि बादलों में पानी होता है और हम जिस क्लाउड की बात कर रहे हैं, उसमें डिजिटल डाटा होता है. डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. वो चाहे डॉक्यूमेंट फाइल हो, ऑडियो हो या वीडियो हो. यह बेहद शक्तिशाली और तेज प्रोसेसिंग करने वाले कम्प्यूटरों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें सर्वर कहा जाता है.

क्लाउड कम्प्यूटिंग कोई नई चीज नहीं है. अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे काफी पहले से जुड़े हुए हैं. हो सकता है आपने क्लाउड कम्प्यूटिंग के बारे में विचार नहीं किया होगा. आज के दौर में लगभग सभी लोग ई-मेल सेवा का प्रयोग करते हैं, वह भी क्लाउड कम्प्यूटिंग का एक हिस्सा है. क्योंकि वह भी ई-मेल यूजर के कम्प्यूटर पर सेव नहीं रहता है, बल्कि किसी अन्य सर्वर पर सेव रहता है. ज्यादातर लोग ई-मेल को अपने कम्प्यूटर पर डाउनलोड नहीं करते हैं. इंटरनेट पर देख कर उसे वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग हार्ड ड्राइव को ई-मेल से नहीं भरना चाहते हैं. यह सारी चीजें किसी दूसरे कंपनी के सर्वर(क्लाउड) पर रहती हैं. वहीं दूसरी ओर फेसबुक या अन्य किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर हम अपना पिक्चर, यू-ट्यूब पर कोई वीडियो या ब्लॉग पर कुछ लिखकर अपलोड करते हैं, तो इन सभी चीजों में क्लाउड कम्प्यूटिंग का ही इस्तेमाल है. आज दुनियाभर में बहुत सी कंपनियां क्लाउड कम्प्यूटिंग का इस्तेमाल अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर रही हैं. सभी कंपनियां अपने-अपने तरीके से यूजर को लुभाने की कोशिश कर रही हैं. जैसे कोई कंपनी अपने यूजर के मनपसंद गानों को उसकी क्लाउड सर्विस पर रखने का मौका देती है, तो कुछ कंपनियां यूजर की पसंदीदा पिक्चर को रखने का मौका देती हैं. कई कंपनियां डाटा को रखने और उसे शेयर करने का ऑप्शन भी दे रही हैं. इस पूरे मामले में यूजर के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर क्लाउड कम्प्यूटिंग सर्विस मुफ्त में हासिल हो सकती है.

इस मायने से देखें तो क्लाउड कम्प्यूटिंग के बिना सभी तरह के कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज सिर्फ खिलौने भर हैं. इंटरनेट सुविधा और इसमें मौजूद अलग-अलग फीचर्स क्लाउड कम्प्यूटिंग के जरिये ही कार्य करते हैं. वेब सर्च इंजन हो या कोई दूसरी अन्य साइट सभी क्लाउड कम्प्यूटिंग के माध्यम से ही यूजर तक पहुंचती हैं. गूगल सर्च हो, याहू मेल या फिर फोटो शेयर करनेवाली वेबसाइट, क्लाउड कम्प्यूटिंग के बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है.

जिस प्रकार हम अपने कम्प्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट पर कोई फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उस डिवाइस के स्टोरेज ड्राइव का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही किस भी दूसरे डाटा को इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे जगह मौजूद कम्प्यूटर पर सेव करने की प्रक्रिया को क्लाउड कम्प्यूटिंग कहते हैं. क्लाउड कम्प्यूटिंग के नाम से कई बार लोगों को यह भी भ्रम हो जाता है कि इसके नामकरण में बादलों का भी कोई हाथ है.

क्लाउड कम्प्यूटिंग का प्रयोग कैसे करें?

क्लाउड कम्प्यूटिंग को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप जिस क्लाउड सर्विस प्रदाता का चयन करना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट बनाएं. उसके कुछ देर बाद आप उसकी इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं. यह इस्तेमाल करने में बहुत आसान हैं.

क्लाउड सर्विस देने वाली कंपनियां

वेमवेयर (Vmware), सन माइक्रोसिस्टम्स (Sun Microsystems), रेकस्पेस यूएस (Rackspace US), आईबीएम (IBM), अमेज़न (Amazon), गूगल (Google), बीएमसी (BMC), माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और याहू (Yahoo) यह प्रमुख क्लाउड कम्प्यूटिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां हैं. सभी कंपनियां अपने यूजर को शुरू के कुछ जीबी स्पेस फ्री में प्रदान करती हैं. यह व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए काफी होता है, पर अगर आपको इसको बिज़नेस या खुद के प्रयोग के लिए फ्री स्पेस से ज्यादा स्पेस चाहिए, तो आप संबंधित कंपनी को पेमेंट कर और अधिक स्पेस खरीद इस सेवा का लाभ ले सकते हैं.

क्लाउड कंप्यूटिंग को कई भागो में बांटा गया हैं

पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग

1. पब्लिक क्लाउड- नाम के हिसाब से यह क्लाउड आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होता है. इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर सर्विस प्रदाता के नियंत्रण में होता है. इसमें यूजर न तो सर्वर कम्प्यूटर को देख सकता है और न ही सर्वर पर उसका कंट्रोल होता है. यूजर को यह भी जानकारी नहीं होती है उसका डाटा कहां और किस सर्वर पर रखा गया है. सामान्यत: क्लाउड सर्विस प्रदाता कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और सन माइक्रोसिस्टम्स इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती हैं. अगर आप बिज़नेस के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके लिए आर्थिक तौर पर ज्यादा किफायती होता है, क्योंकि इसमें मौजूद सभी यूजर में बराबर भागों में खर्च को बांट दिया जाता है, जिससे कम खर्चे में आपका काम हो जाता है. सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें आपको सर्वर की देख-रेख और रख-रखाव से छुटकारा मिल जाता है.

कब पब्लिक क्लाउड कम्प्यूटिंग को चुनें

- जब आपके आर्गेनाईजेशन में किसी एप्लीकेशन पर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हों. जैसे ईमेल का प्रयोग.
- सर्वर पर कोई एप्लीकेशन रखा हो और आपके संस्थान के सभी लोग उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हों. जैसे टैली
- अगर कोई सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग कई जगह से कई लोगों के द्वारा करनी हो.

अगले अंक में पढ़िए-क्लाउड कम्प्यूटिंग के फायदे और नुकसान

smart7973@gmail.com

हीरो की नई बाइक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स

हीरो मोटोकॉर्प ने 150 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा धूम मचाने वाली बाइक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को लॉन्च किया है. यह कंपनी की लोकप्रिय 150 सीसी बाइक एक्सट्रीम का ही अपग्रेड वर्जन है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक केवल 4.7 सेकेंड्स में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. नई हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स अपने पिछले वर्जन से काफी अलग है, इसमें डुअल फिनिश कलर का इस्तेमाल किया गया है. यह बाइक पांच शानदार रंगों में मौजूद है. स्पिलिट सीट डिजाइन के साथ कंपनी ने इसमें कई एडवांस फीचर्स जैसे अंडरसीट मोबाइल चार्जर और इंजन इंमोबलाइजर का इस्तेमाल किया है. पावर की बात करें, तो 149.2सीसी, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन, 5 स्पीड गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है. नई हीरो मोटोकॉर्प की कीमत सिंगल डिस्क 72,625 रुपये और डबल डिस्क 75,725 रुपये है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

जोलो क्यूब 5.0 का नया वर्जन

जोलो ने अपने स्मार्टफोन जोलो क्यूब 5.0(2जीबी) के नए वर्जन को लॉन्च किया है. कंपनी ने नए मॉडल में जो खास बदलाव किया है, वो यह है कि इस फोन की रैम 2 जीबी है. इस फोन में शानदार सेल्फी कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए है. इस फोन को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बाजारों से खरीद सकते हैं. इस फोन का प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वॉड कोर मीडिया टेक है. इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम 5.0 लॉलीपॉप पर आधारित है. इस फोन में 5 इंच का डिस्प्ले है, जो 720 1280 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. इसके साथ ही फोन का रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल है. कनेक्टिविटी के मामले में फोन में 3जी, वाई-फाई, ब्लूटुथ 4.0, माइक्रो-यूएसबी 2.0, जीपीएस दिया गया है. बैटरी बैकअप की बात करें, तो इसमें 2100 एमएएच पावर की बैटरी है. 8 जीबी इंटरनल मेमोरी के साथ इस फोन में माइक्रो एसडी स्लॉट दिया गया है, जिसकी मदद से मेमोरी को 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इस स्मार्टफोन की कीमत 8,888 रुपये है. ■

फेसबुक का नया स्लिंगशॉट ऐप्प

फेसबुक यूजर्स के लिए एक खुशखबरी. फेसबुक दर्शकों के लिए एक नया ऐप्प लाया है. इस नए आईओएस ऐप्प में यूजर को फोटो एडिटिंग का विकल्प मिलेगा, अब यूजर फेसबुक पर अपनी फोटो एडिट कर सकेंगे. एक अपडेट मिलने के बाद यह ऐप्प लेफ्ट साइड में मैजिक वैंड के नाम से नजर आएगा. जिसमें फिल्टर, दोस्तों को टैग करने का विकल्प, क्रॉप टूल, टेक्स्ट और स्टिकर के विकल्प नजर आएंगे. स्टिकर पैक डाउनलोड करने के बाद आप अपने पसंद के स्टिकर को फोटो में कहीं भी लगा सकते हैं. यही नहीं, यूजर फोटो में स्टिकर का कलर और टेक्स्ट की पोजिशन भी बदल सकते हैं. यह ऐप्प स्नैपचैट की तरह है. पहले ही यूजर को फोटो पोस्ट करने से पहले कैप्शन, इमोशन एड करने का मौका देता है. फेसबुक के स्लिंगशॉट ऐप्प में भी स्नैपचैट के टूल और फीचर हैं, लेकिन स्नैपचैट की तरह इसका कोई समय सीमा नहीं है. स्लिंगशॉट एप्पल और एंड्रयॉड दोनों डिवाइस पर चलता है. ■

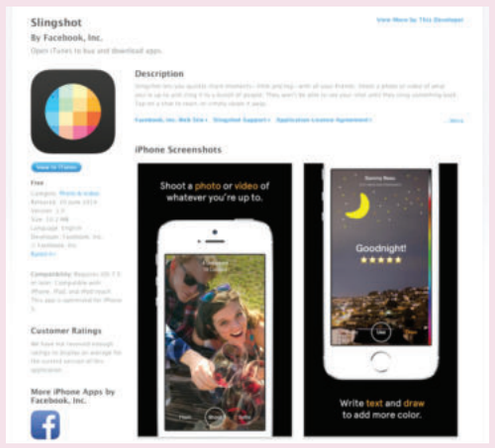

feedback@chauthiduniya.com

पहली बार टेस्ट क्रिकेट में लाल रंग से इतर गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा. खिलाड़ियों के साथ–साथ यह टेस्ट मैच दर्शकों के लिए भी बेहद रोमांचक रहेगा. गुलाबी गेंद के इस्तेमाल को लेकर भी अलग अलग प्रति क्रियाएं सामने आई हैं. जहां ऑस्ट्रलिया पहले डे–नाइट टेस्ट के लिए गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का पक्षधर है वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इससे इत्तेफाक नहीं रखता है. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड टेस्ट में दिन के वक्त लाल गेंद का ही इस्तेमाल करने के पक्ष में है. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी दिन के वक्त लाल गेंद प्रयोग में लाने के पक्ष में हैं.

कितना सफल होगा डे-नाइट टेस्ट

138 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार टेस्ट मैच क्रिकेट दूधिया रोशनी में खेला जाएगा. 15 मार्च, 1877 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था. अब तक क्रिकेट की दुनिया में जितने बड़े बदलाव हुए हैं उन बदलावों की शुरूआत ऑस्ट्रेलिया से ही हुई है. पहली बार दूधिया रोशनी और रंगीन कपड़ों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेली गई, पहली बार कोई कोई विद्रोही क्रिकेट लीग (कैरी पार्कर) ऑस्ट्रेलिया में खेली गई. पहली बार इंडोर स्टेडियम में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया. क्रिकेट की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला पहला अतंरराष्ट्रीय टी–20 मैच भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था. अब इस कड़ी में नया अध्याय डे–नाइट टेस्ट मैच के रूप में जुड़ने जा रहा है.

नवीन चौहान

परिवर्तन प्रकृति का नियम है. यदि कोई परिस्थितियों के अनुकूल ढ़लने में असमर्थ होता है तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है. टेस्ट क्रिकेट के सामने अस्तित्व का संकट लंबे समय से मुंह बाये खड़ा है. टेस्ट क्रिकेट के वजूद को बचाए रखने के कई तरह की योजनायें बनाई गईं, लेकिन उन योजनाओं का कोई जमीनी असर होता नहीं दिखाई दिया. टी–20 क्रिकेट के पदार्पण के बाद टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता में अचानक से गिरावट दर्ज की गई. हालांकि फटाफट क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा. टेस्ट क्रिकेट में भी तेजी आई और अधिकांश टेस्ट मैचों के परिणाम निकलने लगे. परिणाम स्वरूप टेस्ट मैचों में की नीरसता के स्तर में भी कमी आई. बावजूद इसके मैदान में दर्शकों की संख्या में इजाफा नहीं हो सका. लोगों के पास टेस्ट मैच देखने के लिए पांच दिन का समय नहीं है. ऐसे में टेस्ट क्रिकेट में लोगों की रुचि वापस जगाने के लिए डे–नाइट टेस्ट खेले जाने की चर्चा पिछले सात सालों से हो रही थी. लेकिन इस साल 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला डे–नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा.

138 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार टेस्ट मैच क्रिकेट दूधिया रोशनी में खेला जाएगा. 15 मार्च, 1877 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था. अब तक क्रिकेट की दुनिया में जितने बड़े बदलाव हुए हैं उन बदलावों की शुरूआत ऑस्ट्रेलिया से ही हुई है. पहली बार दूधिया रोशनी और रंगीन कपड़ों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेली गई, पहली बार कोई कोई विद्रोही क्रिकेट लीग (कैरी पार्कर) ऑस्ट्रेलिया में खेली गई. पहली बार इंडोर स्टेडियम में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया. क्रिकेट की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला पहला अतंरराष्ट्रीय टी–20 मैच भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था. अब इस कड़ी में नया अध्याय डे–नाइट टेस्ट मैच के रूप में जुड़ने जा रहा है. इस साल नवंबर में न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पहला डे–नाइट मैच खेले जाने की आधिकारिक घोषणा हो गई है. यह मैच 27 नवंबर से खेला जाएगा. तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का यह तीसरा मैच होगा. सफेद जर्सी, दूधिया रोशनी और गुलाबी कोकोबुरा गेंद के साथ दोनों देशों के खिलाड़ी दो–दो हाथ करते नज़र आयेंगे.

क्या कहना है पूर्व खिलाड़ियों का

ऑस्ट्रेलियाई कोच डैरेन लेहमैन सहित कई दिग्गजों ने डे–नाइट टेस्ट की वकालत की थी. पिछले सात सालों से इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे. अब जाकर इसे अंतिम रूप दिया जा सका है. न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज जॉन राइट ने कुछ सालों पहले इस फैसले पर नाख़ुशी जाहिर की थी और कहा था कि वह टेस्ट क्रिकेट के पारंपरिक प्रारूप के शौकीन हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि दिन–रात के टेस्ट टेलीविजन के फायदे के लिए हैं. दिन–रात के टेस्ट भले ही भीड़ जुटाने के लिए हों लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है. पूर्व भारतीय ओपनर आंशुमन गयकवाड़ का कहना है कि यह कुछ अलग है नया है. हमें अभी यह देखना है कि यह कॉन्सेप्ट कैसा करता है. लेकिन ओस इस पूरे परिपेक्ष्य में मुख्य भूमिका होगी. हमें अभी तक यह नहीं मालूम है कि ओस का गुलाबी गेंद पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा. इसके अलावा गेंदबाजी पर ओस का क्या प्रभाव पड़ेगा. यदि ओस की वजह से पिच पर नमी होगी तो इसका फायदा तेज गेंदबाजों को होगा और स्पिनरों को गेंद को ग्रिप करने में परेशानी पेश आएगी. वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज व्यंकटेश प्रसाद का मानना है कि डे–नाइट टेस्ट का आइडिया मुझे पसंद नहीं आया. मेरा टेस्ट क्रिकेट को लेकर रूढ़ीवादी नज़रिया है. टेस्ट क्रिकेट की अपनी एक परंपरा है और हमें इससे दूर नहीं जाना चाहिए. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रिचर्ड हैडली ने ड–नाइट टेस्ट का समर्थन किया है. रिचर्ड ने कहा कि मैं परंपरावादी हूं लेकिन डे–नाइट के प्रयोग को मेरा समर्थन है. जब पहली बार मेरे सामने यह विचार आया था, तब मैं इसके प्रति आशंकित था. यह न्यूजीलैंड के पास इतिहास का हिस्सा बनने का मौका है. मैं दिल से ये भी कहना चाहता हूं कि टेस्ट मैच दिन में ही मैच खेला जाना चाहिए. सभी का मानना है कि खेल विकसित हुआ है. टी–20 और विश्वकप के बाद सफलता के बाद खेल आगे बढ़ रहा है. इसलिए हमें इसका समर्थन करना चाहिए.

क्रिकेट में इस बड़े बदलाव को लेकर हर कोई उत्सुक है. इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी. टेस्ट क्रिकेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ज्यादातर टेस्ट मैच तब खेले जाते हैं जब लोग कार्यालयों में और बच्चे स्कूलों में व्यस्त होते हैं. डे–नाइट टेस्ट होने से लोग कुछ घंटे के खेल का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके साथ ही उन्हें स्टेडियम में जाकर मैच देखने का मौका भी मिल सकता है. 1877 से शुरू हुए टेस्ट क्रिकेट में अब तक कई बदलाव हो चुके हैं. कई नियमों को बदला गया और नए नियम जोड़े गए. डे नाइट टेस्ट खेले जाने की घोषणा के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी जेम्स सदरलैंड ने कहा कि डे–नाइट टेस्ट में प्रशंसकों को तरजीह मिलेगी क्योंकि अधिक दर्शक मैदान पर आ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीविजन पर भी मैच देख पाएंगे. संभावना है कि पहला डे–नाइट टेस्ट एडिलेड में दोपहर ढाई बजे शुरू होगा और रात साढ़े नौ बजे तक चलेगा. पारंपरिक रुप से टेस्ट मैचों में होने वाले ब्रेक से हटकर 40 मिनट का लंबा ब्रेक होगा, जिसे दिन के टेस्ट में लंच के रूप में जाना जाता है. यह पहले सत्र के बजाय दूसरे और तीसरे सत्र के बीच में हो सकता है. इसे डिनर ब्रेक कहा जाएगा. इसी तरह चायकाल पहले सत्र के बाद किया जा सकता है.

पहली बार टेस्ट क्रिकेट में लाल रंग से इतर गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा. खिलाड़ियों के साथ–साथ यह टेस्ट मैच दर्शकों के लिए भी बेहद रोमांचक रहेगा. गुलाबी गेंद के इस्तेमाल को लेकर भी अलग अलग प्रति क्रियाएं सामने आई हैं. जहां ऑस्ट्रलिया पहले डे–नाइट टेस्ट के लिए गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का पक्षधर है वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इससे इत्तेफाक नहीं रखता है. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड टेस्ट में दिन के वक्त लाल गेंद का ही इस्तेमाल करने के पक्ष में है. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर भी दिन के वक्त लाल गेंद प्रयोग में लाने के पक्ष में हैं. डे–नाइट टेस्ट मैचों को अनुमति देते वक्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद(आईसीसी) ने कहा था कि भागीदार देश डे–नाइट टेस्ट मैच खेलने पर आपसी सहमति से राजी हो सकते हैं. घरेलू और मेहमान टीम के बोर्ड खेल के समय तथा गेंद के ब्रांड, टाइप और रंग पर फैसला करेंगे.

गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेले जाने की स्थिति में 80 ओवर के बाद गेंद बदले जाने के नियम में भी बदलाव करना पड़ सकता है. ऑस्ट्रेलिया के युवा गेंदबाज मिचेल स्टार्क का कहना है गुलाबी गेंद को देख पाना मुश्किल है, दर्शकों को भी यह गेंद नहीं दिखाई देगी. गुलाबी गेंद लाल गेंद से बिलकुल अलग व्यवहार करती है. यह लाल गेंद की तुलना में बहुत जल्दी मुलायम हो जाती है. यह लाल गेंद जितनी स्विंग भी नहीं होती है. इसके अलावा रात में ड्यू फैक्टर(ओस) की भूमिका भी अहम हो जाएगी. ड्यू फैक्टर स्पिन गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबब बनेगा. उन्हें गेंद को ग्रिप करने में परेशानी होगी. इसके अलावा गेंद के ओस में भीगने की वजह से गेंद के रंग और गेंद के आकार में भी बदलाव आएगा. इसका सीधा असर खेल पर होगा. इससे बोर्ड, खिलाड़ी, कप्तान और मैच ऑफीशियल्स कैसे पार पाते हैं यह देखना बेहद दिलचस्प होगा. क्रिकेट के नियमों के संरक्षक संस्था एमसीसी के प्रमुख स्टीफनसन का कहना है कि यह घोषणा टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत सकारात्मक कदम है और एमसीसी में इस खबर से खुश है. विश्व के इस सबसे सक्रिय क्रिकेट क्लब ने गुलाबी रंग की गेंद का उपयोग करके डे–नाइट मैचों की संभावना पर काफी शोध किया है. अब डे–नाइट टेस्ट मैच होते हुए देखना रोमांचक होगा. कूकाबुरा के प्रबंध निदेशक का कहना है कि कूकाबुरा की गुलाबी गेंद पिछले पांच वर्षों में एमसीसी, ईसीबी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक परीक्षण किया है और यह गेंद अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच के लिए तैयार है.

एक ही दिन में बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दो तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा. एक दिन में और दूसरी रात में. ऐसे में खिलाड़ियों के लिए टेस्ट मैच ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जायेंगे. इससे एक फायदा तो दिखाई दे रहा है कि खिलाड़ियों के खेल के स्तर में सुधार आएगा. इससे टेस्ट मैच की सामान्य गति पर भी असर पड़ेगा. यदि पिच पर ओस की वजह से नमी होगी तो गेंद स्विंग करेगी, लेकिन गेंद को ग्रिप करने में गेंदबाजों को परेशानी होगी. गुलाबी गेंद बहुत जल्दी मुलायम हो जाएगी ऐसे में उसका 80 ओवर तक चल पाना फिलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है.

जिस तरह एक दिवसीय मैचों में ओस की वजह से सफेद गेंद को मैच के दौरान कई बार बदलना पड़ता था. उसके बाद ही दोनों छोर से नई गेदों का नियम आया. ऐसा ही कुछ डे–नाइट टेस्ट मैचों में भी करने की आवश्यकता भविष्य में पड़ सकती है. हो सकता है कि आगे चलकर दोनों छोर से गुलाबी गेंदों का इस्तेमाल हो और 80 ओवर बाद दोनों छोर की गेंदों को नई गेंद से बदल दिया जाए. यदि ऐसा होगा तो गेंद को रिवर्स स्विंग करा पाना गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो जाएगा. दिन में खेले जाने वाले टेस्ट मैच पर सूरज की रोशनी का भी अच्छा–खासा असर होता है. खेल के साथ मैच के दिन बढ़ने के साथ पिच में दरारें आती जाती हैं. मैच के चौथे और पांचवें दिन ये दरारें गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है. लेकिन डे–नाइट टेस्ट मैच में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर दिन मैच के दूसरे हिस्से में धूप नहीं होगी. इस वजह से किसी एक पक्ष को फायदा मिल सकता है.

टेस्ट मैच में यह विवादास्पद प्रयोग मुख्य रूप से दर्शकों को मैदान पर वापस खींचने के उद्देश्य से किया जा रहा है. इससे आयोजकों को पैसा भी मिलेगा. शाम और रात को कामकाजी लोगों और छात्रों को मैच देखना का मौका मिलेगा. लेकिन इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, कि क्या क्रिकेट प्रशासन का काम केवल पैसा कमाना रह गया है, या फिर उनके कंधों पर इससे बड़ी जिम्मेदारी क्रिकेट के हर पहलू को बचाए रखने की है. क्या वह अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छी तरह से कर रहा है. भले ही डे–नाइट टेस्ट को लेकर मिले जुले विचार सामने आ रहे हैं लेकिन निश्चित तौर पर इससे टेस्ट मैचों के प्रति लोगों में रुचि एक बार फिर जगेगी और क्रिकेट के क्षेत्र में सफलता का एक और आयाम जुड़ जायेगा.■

navinonline2003@gmail.com

सनी लियोन का सपना पूरा हुआ

बड़े सितारों के साथ काम करने का सपना कौन नहीं देखता. हर किसी का ऐसा सपना पूरा नहीं होता, लेकिन सनी लियोन का यह सपना पूरा होता नज़र आ रहा है. सनी लियोन जल्द ही अक्षय कुमार के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. सनी लियोन ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म सिंह इज ब्लिंग में एक छोटा सा कैमियो रोल किया है. सनी लियोन की बीती जिंदगी उनके रास्ते की रुकावट बनती रही हैं. पिछले महीने सनी लियोन गोवा में अपने रियलिटी शो स्प्लिट्सविला की शूटिंग में व्यस्त थीं. उसी दौरान अक्षय कुमार की फिल्म सिंह इज ब्लिंग की शूटिंग भी गोवा में ही चल रही थी. इस दौरान सनी लियोन को अक्षय की फिल्म में कैमियो करने का ऑफर मिला और सनी ने इस रोल के लिए तुरंत हामी भर दी. सनी ने इसकी पुष्टि ट्विटर के माध्यम से की है.■

> सनी लियोन गोवा में अपने रियलिटी शो स्प्लिट्सविला की शूटिंग में व्यस्त थीं. उसी दौरान अक्षय कुमार की फिल्म सिंह इज ब्लिंग की शूटिंग भी गोवा में ही चल रही थी.

परदे पर दिखेगी आलिया और शाहिद की जोड़ी

करण जौहर ने अपने घरेलू प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन की आगामी फिल्म शानदार की रिलीज के लिए 22 अक्टूबर को चुना है. इस दिन दशहरा है

पहली बार आलिया भट्ट और शाहिद कपूर की जोड़ी परदे पर दिखाई देगी. फिल्मकार करण जौहर ने अपने घरेलू प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन की आगामी फिल्म शानदार की रिलीज के लिए 22 अक्टूबर को चुना है. इस दिन दशहरा है. करन के निर्देशन वाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वालीं आलिया भी इसे लेकर उत्साहित दिखीं. इस रोमांटिक फिल्म का निर्देशन क्वीन से प्रसिद्धि पाने वाले विकास बहल ने किया है. इसे करण के धर्मा प्रोडक्शन और फैंटम फिल्म्स ने मिलकर बनाया है.■

सफलता की गारंटी बने वरुण धवन

इस साल की पहली हिट फिल्म वरुण धवन की बदलापुर थी. अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एबीसीडी–2 भी हिट रही है. रमजान का महीना शुरू होने के बावजूद फिल्म को बड़ी ओपनिंग मिली. शुरूआती 10 दिन में ही यह फिल्म 90 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. फिल्म की सफलता को देखकर यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि आज के युवा सितारों में वरुण धवन सबसे आगे निकल चुके हैं. अब तक की उनकी सभी फिल्में हिट हैं, जबकि उनके किसी प्रतिद्वंदी के हाथ ऐसी सफलता नहीं लगी है. इसके साथ वरुण 100 फीसदी सक्सेस रेट वाले स्टार बन गए हैं. ये वरुण का हुनर है या किस्मत, क्योंकि वरुण की सभी 5 फिल्में हिट हैं. वरुण की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द इयर, मैं तेरा हीरो, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां, बदलापुर एक्सप्रेस और एबीसीडी–2 रिलीज हुई हैं इनसभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में सफलता के झंडे गाड़े हैं.

वहीं दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवा सितारों की हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में हैं. आगे वह 6 बहुत उम्दा प्रोजेक्ट्स में तय हो चुके हैं. अभी वे शाहरुख के साथ दिलवाले की शूटिंग कर रहे हैं. इसके बाद भाई रोहित धवन की ढिशुम में जॉन अब्राहम और जैकलीन फर्नांडिस के साथ दिखाई देंगे फिर ऋतिक और सलमान जैसे स्टार्स के स्थान पर फिल्म शुद्धि में करण जौहर ने उन्हें लिया है. रोहित शेट्टी की राम लखन रीमेक में भी वरुण का नाम तय है. पिता डेविड धवन स्क्रिप्ट के साथ तैयार हैं. इंतजार बेटे की डेट्स का है हम्पटी शर्मा के निर्देशक शशांक खेतान के अगले प्रोजेक्ट में भी वरुण होंगे, केवल इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है.■

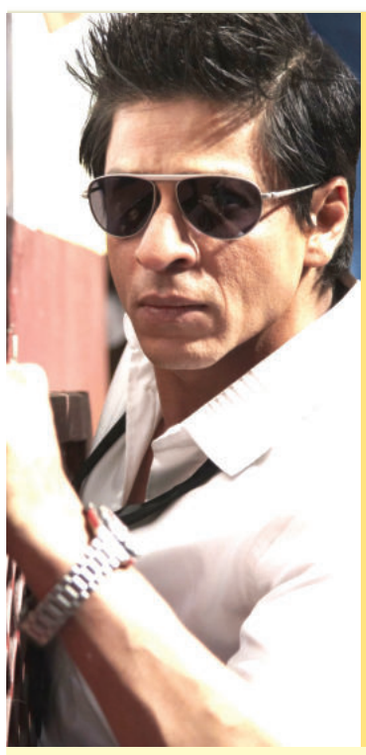

सलमान और शाहरूख होंगे आमने सामने

ऐसा आखिरी बार 2006 में हुआ था. 2006 शाहरुख की डॉन और सलमान की जानेमन रिलीज हुई थी.

अगले साल ईद पर दो सुपरस्टार्स आपस में भिड़ेंगे. अभिनेता शाहरुख खान और सलमान खान अगले साल बॉक्स ऑफिस पर अपनी–अपनी फिल्मों रईस और सुल्तान के साथ टकराएंगे. ऐसा नजारा रोज–रोज देखने को नहीं मिलता हैं. जब दो सुपरस्टार की आपस में भिड़ंत होगी. लेकिन शाहरुख का कहना है, कि वे दोस्त हैं और बॉक्स ऑफिस पर फिल्में की एक साथ रिलीज को टकराव के तौर पर नहीं देखते. शाहरुख ने कहा मेरे और सलमान में अच्छी दोस्ती है, इसको भिडंत के तौर पर नहीं देख सकते. अब में और सलमान अच्छे दोस्त बन गए हैं. इसलिए अब हम सबकुछ साथ में करेंगे. आप सबके लिए ये टकराव हो सकता है, लेकिन हम दोनों लिए मुनाफा बराबर ही होगा.

राहुल ढोलकिया के निर्देशन में बन रही रईस एक एक्शन–थ्रिलर फिल्म है, जिसमें किंग खान के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान, फरहान अख्तर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी होंगे. वहीं दूसरी तरफ सलमान की सुल्तान आदित्य चोपड़ा के बैनर तले बन रही है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

हॉलीवुड ख़बर

जुरासिक वर्ल्ड ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़े

जुरासिक पार्क सीरीज की चौथी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड ने भारत में 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस फिल्म में क्रिस प्रैट और इरफान खान ने अभिनय किया है. कोलिन ट्रेवोरो निर्देशित और कई भाषाओं में बनी यह फिल्म पूरे भारत में प्रदर्शित की गई थी. प्रदर्शन के तीसरे सप्ताह में इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का व्यापार कर लिया था. यह फिल्म हिन्दी, तमिल और तेलगू भाषा में 2,108 पर्दों पर प्रदर्शित की गई. जुरासिक वर्ल्ड पहले ही दुनियाभर में तेजी से एक अरब डॉलर कमाने वाली फिल्म का दर्जा पा चुकी है अब तक इसकी दुनियाभर में कमाई करीब 1.238 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. इस हिसाब से यह सर्वाधिक कमाई करने वाली आठवीं फिल्म बन गई है. जुरासिक वर्ल्ड 1993 की सफल फिल्म जुरासिक पार्क का सीक्वल है. यूनीवर्सल पिक्चर्स इंडिया ने एक बयान में कहा है कि जुरासिक पार्क सीरीज की इस फिल्म ने भारतीय दर्शकों की पुरानी यादों को ताजा किया. इसके अलावा, सभी उम्र के लोगों को रोमांचित करने वाले विषय पर बनी यह फिल्म सभी को पसंद आई है. अभी भी यह फिल्म सिनेमाघरों में लगी है देखते हैं यह फिल्म कमाई के कौन से नए कीर्तिमान बनाती है.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार -झारखंड

13 जुलाई -19 जुलाई 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बयानबहादुरों के बहकते बोल

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बिहार में चुनाव की हवा अभी-अभी तो चली है, अभी काफी कुछ देखना बाकी है. गत संसदीय चुनाव के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं. उन दिनों गिरिराज सिंह- नरेन्द्र मोदी सरकार के मंत्री- ने खुले तौर पर कहा था कि जो लोग हिन्दुत्व की राजनीति का विरोध करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए. भाजपा और उसके सहयोगी दलों की हिंदुत्ववादी राजनीति के विरोधियों को उनका यह मशवरा मतदान के दौरान आया था. उससे पहले भी उन्होंने अनेक बयान दिए थे जिन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था. ये हालात विधानसभा चुनावों के दौरान भी आएंगे, इसकी पूरी आशंका है. हां, इस बार बयान-बहादुर कोई दूसरे राजनेता होंगे. वस्तुतः पात्र बदलते रहते हैं, मानसिकता वही काम करती है- विरोधी विचार की बोलती बंद करने की.

चौथी दुनिया ब्यूरो

चुनाव का मौसम आ गया और इसके साथ ही राजनेताओं के कड़वे और अभद्र बयानों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है. बिहार में राजनेताओं के बयानात में इसके नमूने मिलने भी लगे हैं. सत्तारूढ़ जनता दल(यू) के बाहुबली विधायक अनन्त सिंह की गिरफ्तारी को किसी जाति के खिलाफ अभियान तो किसी जाति की जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है- जातियों की अपने-अपने खेमे में गोलबंद करने के ख्याल से. बड़े-छोटे नेताओं के ऐसे बयानात से राज्य का माहौल सरगर्म होने लगा है. एनडीए की घटक राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के सांसद अरुण कुमार ने कहा,'नीतीश कुमार एक जाति विशेष को निशाने पर ले रहे हैं. हम भी कमजोर नहीं है. उनका कलेजा तोड़ दिया जाएगा.' उनके इस बयान से दल के तौर पर रालोसपा या राजनीतिक गठबंधन के तौर पर एनडीए ने खुद को अलग नहीं किया है. इधर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी पुराने रंग अख्तियार करते दिखे. उन्होंने बिहार के अगड़े समाज को आगाह किया, 'राज्य में पच्चीस साल (सन 1990) पहले के हालात नहीं पैदा होने दिए जाएंगे.' हालांकि राजद सुप्रीमो की भाषा को लेकर किसी ने सवाल नहीं खड़े किए हैं, पर उनकी भंगिमा सद्भाव के संदेश तो कतई नहीं देती है. यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बाहुबली अनन्त सिंह को जेल भेजने का श्रेय खुद लालू प्रसाद सीना तान कर लेते हैं. बयानों का सिलसिला राजद से बर्खास्त मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव भी चला रहे हैं. हालांकि वह ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं जिसे अभद्र और कड़वे भाषा की श्रेणी में रखा जाए, पर उनकी भंगिमा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जैसे नेता के खिलाफ एक दबंग जाति में तनाव बढ़ाने की होती है. इसे जातीय कटुता को विकसित करने का ही नया, मगर खुला, तरीका माना जाएगा.

बिहार में चुनाव की हवा अभी-अभी तो चली है, अभी काफी कुछ देखना बाकी है. गत संसदीय चुनाव के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं. उन दिनों गिरिराज सिंह-नरेन्द्र मोदी सरकार के मंत्री-ने खुले तौर पर कहा था कि जो लोग हिन्दुत्व की राजनीति का विरोध करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए. भाजपा और उसके सहयोगी दलों की हिन्दुत्ववादी राजनीति के विरोधियों को उनका यह मशवरा मतदान के दौरान आया था. उससे पहले भी उन्होंने अनेक बयान दिए थे जिन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था. ये हालात विधानसभा चुनावों के दौरान भी आएंगे, इसकी पूरी संभावना है. हां, इस बार बयान-बहादुर कोई दूसरे राजनेता होंगे. वस्तुतः पात्र बदलते रहते हैं, मानसिकता वही काम करती है- विरोधी विचार की बोलती बंद करने की. हालांकि ऐसे माहौल को विकसित न होने देने के लिए चुनाव आयोग कुछ कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है. खबर है कि उसने अधिकारियों को चुनाव में वोट की गोलबंदी के ख्याल से कटुतापूर्ण बयान देनेवालों पर नज़र रखने को कहा है, विशेषकर उन नेताओं पर जो जाति और धर्म को निशाने पर लेकर बयान जारी करते हैं. इस सिलसिले में प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं के नितान्त निजी घटनाओं को निशाना बनाए जाने की प्रवृत्ति पर भी नज़र रखी जाएगी. ऐसे बयान जारी करनेवाले राजनेता और उनकी बातों का रिकार्ड रखा जाएगा. हालांकि आयोग के लिए फिलहाल करने को बहुत कुछ नहीं है, पर इन फीडबैक का उपयोग आचार संहिता लागू होने के बाद किया जा सकेगा.

यह साफ नहीं हो सका है कि आयोग ने इन सूचनाओं के संरक्षण की जिम्मेवारी किसे दी है और इनका उपयोग कैसे किया जाएगा. यह भी तथ्य है कि चुनाव आयोग की स्थिति नख-दंतहीन विषहीन संस्था की है और राजनीतिक तौर पर निष्ठावान नौकरशाहों को सबक सिखाने के उसके पास सीमित हथियार हैं. लेकिन चुनावी मौसम में राजनेता बयानों से जैसी कटुता फैलाते हैं, उसे नियंत्रित करने में इस और ऐसी कार्रवाई से मदद ही मिलेगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने बिहार विधानसभा के चुनाव को आयोग के लिए चुनौती की संज्ञा दी है. लेकिन उसकी असली अग्निपरीक्षा जातीय और धार्मिक उन्माद को हवा देनेवाले बयानों के साथ-साथ राज-नेताओं- वे चाहे जिस स्तर के हों- की कटुतापूर्ण और अभद्र टिप्पणियों पर अंकुश लगाने के कारगर उपाय ढूंढने और उन्हें लागू करवाने को लेकर होनी है.

वस्तुतः यह राजनीति के विचारहीन और संस्कारहीन होते जाने का प्रमाण तो है ही, दलों में सांगठनिक तंत्र व जनतांत्रिक व्यवस्था की अवहेलना का भी प्रमाण है. सभी दलों में कार्यकर्ता नाम की संस्था समाप्त हो रही है और उनके बदले ठेकेदार-नेताओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है. कार्यकर्ता न होने से जमीनी स्तर पर दल और नेता के लिए काम कर आम जन (वोटर) को गोलबंद करने की प्रक्रिया अधिकांश दलों में समाप्त हो गई है. हालांकि भाजपा जैसे दल में यह बाकी है तो इसलिए कि संघ परिवार के गैर राजनीतिक संगठन चुनाव के महीनों पहले से राजनीतिक कार्य में लगा दिए जाते हैं. फिर, राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं-कार्यकर्ताओं के राजनीतिकरण की प्रक्रिया समाप्त कर दी है. इस राजनीति-शून्य माहौल में कटु, कड़वा, अभद्र, यहां तक कि गाली की भाषा का इस्तेमाल नेता को घंटों में वह प्रचार दे देता है जो वर्षों की तपस्या से उसे नहीं मिलता. लेकिन इससे भी बड़ा मकसद दूसरा है. इस विचार-शून्य व कर्म-शून्य राजनीतिक माहौल में जातीय और क्षेत्रीय भावना को राजनेता हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. बिहार ऐसी राजनीति का एक मात्र तो नहीं, पर अच्छा उदाहरण है. जातिगत गोलबंदी के नाम पर लालू प्रसाद कई वर्षों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे. 1995 के विधानसभा चुनावों के समय यहां भूराबाल साफ करो का नारा दिया गया था. यह भूराबाल चार अगड़ी जातियों के नामों के पहले अक्षरों के समुच्चय हैं. हालांकि तत्कालीन जनता दल और इसके नेताओं ने इस मामले को लेकर एक अखबार पर मुकदमा भी किया था. लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि भूराबाल को साफ करने के नारे से लालू प्रसाद को लाभ ही मिला था. संयोग से कोई दो दशक पहले के लालू प्रसाद की इस राजनीति का सहारा इस बार बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने लिया है- भाजपा से लेकर राजद तक. सभी ने सत्ता पाने के बाद जातियों को सुविधाएं देने का सार्वजनिक आश्वासन देकर वोटों की अपने पक्ष में गोलबंदी की हरसंभव कोशिश की है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर आयोजित एक समारोह में जिस दिन राष्ट्रकवि के एक कथन का हवाला देकर बिहार के विकास में जातिवाद को सबसे बड़ा बाधक बता रहे थे. उन्हीं दिनों उनके एनडीए के दल जातियों के सम्मेलनों के सफल आयोजन में व्यस्त थे. सो, ऐसे छद्म के साथ राजनीति में विचार, शुचिता और संस्कार की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है!

चुनाव पूर्व के राजनीतिक माहौल के ये कुछ नमूने भर हैं. राजनेताओं की गत कई चुनावों से वोटर की सामाजिक (जाति) स्तर पर तीखी गोलबंदी की कोशिश रही है और वे इस में सफल भी होते रहे हैं. विचित्र स्थिति है, जातिवाद को गाली देते हुए जातियों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. सांस्कृतिक और सामाजिक व जनतांत्रिक संघर्ष के इतिहास पुरुष जातियों के घेरे में बांधे जा रहे हैं और उनके नाम पर जातियों को गोलबंद किया जा रहा है. ऐसे में कटु और कड़वे बोल या अभद्र भाषा का उपयोग राजनेता हथियार के तौर पर करते हैं. राजनेताओं की मानसिकता से साफ है कि आसन्न विधानसभा चुनाव में इस हथियार का जबर्दस्त उपयोग किया जाएगा. लालू प्रसाद की भाषा भंगिमा, पप्पू यादव के तीखे जातिवादी तेवर, अगड़े समाज के कुछ राजनेताओं की भाव-मुद्राएं इसके खासे संकेत देते हैं. राजनीति में कथनी और करनी की बढ़ती दूरी भी इस माहौल का एक बड़ा कारण है. चुनाव के समय या प्रतिद्वंद्वी दलों को घेरने के अवसर पर या उन्हें छोटा दिखाने के लिए नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वायदे करते हैं. लेकिन उन्हें पूरा कर पाना आसान नहीं होता. ऐसे में अपने समर्थक सामाजिक समूहों (वोटर समुदाय) को बरगला कर उसे भावनात्मक स्तर पर सरगर्म बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्द्धी राजनीति या विचार को नीचा दिखाना जरूरी होता है और इसके लिए कटु और कड़वे बोल या अभद्र और निम्न-स्तर की भाषा का इस्तेमाल वे जरूरी समझते हैं. यही हो रहा है, मौजूदा राजनीति के विचारहीन और संस्कारहीन होते जाने के कारण माहौल का निरन्तर दूषित होना तय है.■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

चुनावी हलचल

ऊब चुकी है जनता

बायसी महासम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चरण कुमार सिंह ने जनता को सचेत किया कि लालू–और नीतीश कुमार बिहार में हो रहे विकास को अब रोकना चाहते हैं. एनडीए गठबंधन के द्वारा किए गए विकास को अब लालू जी रोक रहा है. उन्होंने कहा कि कहा भी गया है कि संगत से गुण होत है संगत से गुण जात और जंगलराज के साथ मिलकर कहेंगे तो गुण तो आयेगा ही. दोनों नेता जात–पात की राजनीति के पुरोधा हैं. उन्होंने आगे आम जनता की मानसिकता को भी बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के शासन को जनता पहचान चुकी है. भाजपा के सहयोग से सुशासन का पाठ पढ़ाने वाले अब जंगलराज वाला सुशासन लायेंगे. जनता लालू और नीतीश के शासन को देख चुकी है, अब एनडीए के सुशासन के देखेगी. बायसी सम्मेलन में भारी भीड़ के साथ विशिष्ट अतिथि शाहनवाज हुसैन और प्रसिद्ध लोक गायक सुनील छैला बिहारी भी उपस्थित थे.

एकल कथा समारोह का आयोजन

महंत हनुमान शरण कॉलेज, पटना में 'एकल कथा समारोह' का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह ने अपनी कहानी 'मेरे मीत' का कथा–पाठ किया. उनकी कहानी में गंगा–यमुनी की तहजीब को सुनकर लोग अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके. इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विमल नारायण आर्य ने कहा कि डॉ. लालजी प्रसाद सिंह की यह रचना 'मेरे मीत' वास्तव में प्रेरणादायक है. डॉ आर्य ने बताया कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे की पुस्तक 'दि ओल्ड मैन एण्ड दि सी' से किसी भी मामले में 'मेरे मीत' की कहानी कम नहीं है. इनकी कहानियां पढ़ते हुए प्रेम चन्द बरबस याद आ जाते हैं. इनके पात्र जिद की हद तक अपनी समस्याओं से लोहा लेते नजर आते हैं. उक्त एकल कथा समारोह में प्रो.आर. एस. तिवारी, प्रो. वी.के. राय, प्रो. सी.डी. सिंह, प्रो. रंजना कुमारी, प्रो. संजय ठाकुर, प्रो. गुलाम रब्बानी, प्रो. पंकज कुमार, प्रो. मीरा कुमारी, उपेन्द्र कुमार, मनोज कुमार, प्रो. नवीन कुमार, भूपेन्द्र कुमार, प्रो. रीना सिन्हा, प्रो. दीपक कुमार तथा छात्र–छात्राओं में शैलेन्द्र, ज्योतिका, मधु, प्रीति, नदीम, रेहान, माही, अभिषेक, आदित्य इत्यादि मौजूद थे.

– रजनीकांत पांडेय

सुगर(मधुमेह) रोगी और घाव

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. एम. कैसर जावेद M.D. Medicine
हृदय एवं डायबिटीज रोग विशेषज्ञ

घाव से संबंधित जानकारी शेयर किया डॉ. एम..कैसर ने जो गोपालगंज में हृदय और मधुमेह रोग के विशेषज्ञ के तौर पर अपनी पहचान बना रखी है। डायबिटिज रोगी को पैरों में होनेवाले घाव और उससे बचने के लिए निम्नलिखित सलाह दिया है। 1. घाव वाले पैर पर ज्यादा वजन देकर न चलें जबतक घाव ठीक नहीं हो जाय (छड़ी, वाकर का इस्तेमाल करें) 2. नियमित एंटीसेप्टीक ड्रेसिंग कराएं। 3. हर रोज अपने पैरों का निरीक्षण स्वंय करें। 4. किसी भी तरह का वर्जित केमिकल या हर्बल दवा घाव पर न लगाएं। 5. पैर की साफ–सफाई सदैव रखें। 6. खाली पैर न टहलें (घर में या घर के बाहर) 7. रोजाना मोजे बदले (नाईलन का मोंजा ना पहने) 8. ज्यादा टाईट या ज्यादा ढीला चप्पल या जूता ना पहनें, (चप्पल या जुते का तल्ला नरम होना चाहिए, सम्भवत: चमड़े का नरम जूता या चप्पल का इस्तेमाल सही है।) 9. जुते पहनने से पहले झाड़ लें ताकि उसमें कोई कील या पत्थर ना हो। 10. पैरों में दरार, घाव, फफोले, सूजन, पैरों में ठंढे, गरम एवं छुने पर दर्द का पता नहीं चलने पर, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां या उभार होने पर चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। 11. पैरों के तलवे में गरमी, झनझनाहट , जलन अनुभव होने पर चिकित्सक को जरूर बताएं। 12. संध्या समय काम से लौटने पर साबुन एवं पानी से पैरों को अच्छे तरह धोकर सुती कपड़े से सुखालें पैरों के गस्से को भी ठीक से सुखा लें। 13. किसी तरह का घाव या पैर के चमड़े में काला या लाला रंग का बदलाव दिखाई दे तो स्वंय इलाज न करें एवं अविलम्ब अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक से सम्पर्क करें। 14. ब्लड सुगर की जांच चिकित्सक के परामर्श के अनुसार नियमित रूप से कराएं ■

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

चित्रा भारती

सेना में माओवादियों की घुसपैठ!

सुनील सौरभ

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने भारतीय सेना में भी अपनी पैठ बना ली है. इस बात का प्रमाण तब मिला जब 12 जून 2015 को बिहार के गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में सेना के जवान कृष्णा राम, सेना से रिटायर्ड जवान गोपी लाल तथा भाकपा माओवादी के कमांडर इंदल भोक्ता के सहयोगी लेखा सिंह भोक्ता को सात किलो अफीम के साथ पकड़ा गया. सेना के दो जवान को माओवादीं संगठन से जुड़े एक व्यक्ति के साथ बड़ी मात्रा में अफीम के साथ पकड़े जाने पर सेना तथा खुफिया एजेंसियों के होश उड़ गये हैं, इससे यह प्रमाणित होता है कि माओवादियों की पंहुच सैनिक सेंटरो तक हो चुकी है. माओवादी सेना के जवानों को अफीम के सहारे सेना के संबध में गुप्त जानकारी प्राप्त करने मे भी सफल हो सकते हैं. जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक सबित हो सकता है.

पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी, कि नशीले पदार्थो के कुछ सौदागर गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के काहुदाग में हैं. पुलिस ने नाकेबंदी की और एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों को पकड़ा. उन सभी की जब छानबीन की गई तो पुलिस के होश उड़ गये. तील में से दो आर्मी का जवान था, जिनमें कृष्णा राम ग्राम पाली थाना लोहावत जिला जोधपुर राजस्थान का निवासी है और सैनिक अस्पताल, नामकुंम, रांची में कार्यरत है जबकि दुसरा मोतीलाल भी इसी गांव का निवासी है और एक माह पूर्व आर्टीलरी रेजीमेंट रांची से रिटायर्ड हुआ है. तीसरा व्यक्ति लेखा सिंह भोक्ता माओवादी कमांडर इंदल भोक्ता का सहयोगी है. इन तीनों के पास से सात किलो अफीम के साथ चार मोबाइल फोन, एक डिजिटल वेवरिंग मशीन, कई बैंको के एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड समेत अन्य कई समान बरामद किये. बड़ी मात्रा में अफीम के साथ सेना के दो जवान को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कमांडर के एक सहयोगी के साथ पकड़े जाने की सूचना पर ही पुलिस–प्रशासन के साथ–साथ सेना के रांची–गया स्थित सेटरों में भी खलबली मच गई. खुफिया एजेंसियों के होश उड़ गये . सूत्रो के अनुसार अफीम के सहारे बड़ी राशि का लालच देकर सेना में घुंसपैठ करने की माओवादियों की योजना है. साथ ही सेना की गुप्त जानकारी भी प्राप्त कर माओवादी देश की आंतिरक व बाहरी सुरक्षा को संकट मे डालने का काम कर सकते हैं. देश के विभिन्न हिस्सों मे हाल के वर्षो में पुलिस–माओवादी मुठभेड में माओवादियों से बरामद अत्याधुनिक हथियारों से स्पष्ट होता है कि आतंकी संगठन माओवादियों की मदद कर रहे हैं. ऐसे भी आतंकी संगठनों की ओर से देश की आतंरिक सुरक्षा को कमजोर करने के लिए माओवादियों को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्त्ति किये जाने की बात अक्सर आती है.

> **गया जिले का बाराचट्टी क्षेत्र जंगलों –पहाड़ों सें अच्छादित हैं. यहां सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का मुख्यालय भी हाल के वर्षो में बना है. पहाड़ी इलाका व जंगल होने के कारण सेना के जवानों को ट्रेनिग देने का भी उपयुक्त स्थान माना जाता है. यहां झारखंड में स्थित सेना के सेंटरों से अक्सर सेना के जवान फायरिंग की प्रैक्टिस करने आते हैं, जो एक एक पखवाड़े तक यहां के जंगलों में रहते हैं. लेकिन अब यह प्रैटिक्स देश के लिए नुकसान देह साबित हो सकती है.**

गया का वाराचट्टी क्षेत्र इन दिनों अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है. इससे लगे झारखंड के चतरा व हजारीबाग में भी माओवादी पहाड़ी क्षेत्रों मे वन विभाग की भूमि पर अफीम की खेती कराते है. अक्सर सुरक्षा बलों द्वारा अफीम की खेती नष्ट भी करायी जाती है. अफीम की खेती नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का इन दिनों आय का मुख्य स्त्रोत बन गया है. इसी आय से माओवादी अपने संगठनो को मजबूत करते है. लेकिन सेना में अफीम के सहारे घुसकर सेना को क्षति पहुंचाने की जानकारी पुलिस को पहली बार पता चला है. गया जिले का बाराचटटी क्षेत्र जंगलों –पहाड़ों सें अच्छादित हैं. यहां सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का मुख्यालय भी हाल के वर्षो में बना है. पहाड़ी इलाका व जंगल होने के कारण सेना के जवानों को ट्रेनिग देने का भी उपयुक्त स्थान माना जाता है. यहां झारखंड में स्थित सेना के सेंटरों से प्राय सेना के जवान फायरिंग की प्रैक्टिस करने आते है, जो एक एक पखवारे तक यहां के जंगलों में रहते हैं. लेकिन अब यह प्रैटिक्स देश के लिए नुकसान देह साबित हो सकता है. क्योंकि सेना के दोनो जवान ने पूछताछ में बताया कि ट्रेनिंग मे आने के दौरान ही गांव के लोगो से मुलाकात हुई और इसी दौरान लेखासिंह भोक्ता से परिचय हुआ. इसी से अफीम खरीदना शुरु किया. क्योंकि राजस्थान के लोग अफीम का सेवन अधिक करते है.

सेना के जवान व रिटायर्ड जवान ने बताया वे सभी अपने परिवार के लोगो के लिए अफीम खरीदकर ले जा रहे थे. लेकिन सवाल है कि माओवादी बाराचटटी के जंगल मे प्रैक्टिस के लिए आने वाले सेना के जवानो को अफीम तथा रुपये का लालच देकर क्या अपना मतलब नही साध सकते हैं? ऐसी स्थिति रही तो माओवादी आधार वाले क्षेत्रों मे सेना के जवानो का प्रैक्टिस करना सेना के जवानों तथा देशहित में नुकसान देह हो सकता है. हाल के दिनो में सेना–पुलिस के जवानों को माओवादियों के द्वारा बारुदी सुरंग व बड़े हमले कर क्षति पहुंचाने का मामला भी कहीं सेना में माओवादियों की घुसपैठ का परिणाम तो नही है? इस पर विचार करना होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

हर घर दस्तक

बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता इस अभियान के जरिये राज्य के सभी घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा एक करोड़ घरों तक पहुंचना है. उन्होंने कहा कि हमारे करीब दस लाख कार्यकर्ता लोगों से बातचीत करेंगे और हमारी पिछली सरकार के बारे में बताएंगे. इस अभियान के बारे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि इसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक व पंचायत स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे.

चुनावी हलचल

टिकट नहीं मिला तो बागी लड़ूगा : प्रमोद

पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी तो पार्टी को कार्यकर्ताओं का कोपभाजन बनना पडेगा. भाजपा के पास समर्पित कार्यकर्ताओ की कमी नहीं है, लेकिन दूसरे दलों से बाहरी लोगों को लाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का सिलसिला जारी है. यह पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. कल्याणपुर से भाजपा के टिकट की दावेदारी करते हुए प्रमोद गिरि ने कहा, प्रमोद गिरि कोटवा के प्रखण्ड भाजपा अध्यक्ष हैं.15 वर्षो से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे श्री गिरि ने टिकट नहीं मिलने पर बागी उम्मीदवार के रुप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. प्रमोद गिरि जिला कामगार मजदूर संघ के अध्यक्ष भी है. मजदूरों के कल्याण के लिए वर्षो से काम कर रहे गिरि का कहना है कि हजारों मजदूरों के समर्थन के साथ हीं किसानों का पूरा समर्थन प्राप्त हैं. सभी वर्ग और जाति में गहरी पैठ है. गिरि चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं.

– राकेश

चौपाल में पर्चा पर चर्चा सम्पन्न

सदरप्रखंड के मथुरापुर पंचायत में पिछले दिनों रविवार को चौपाल आयोजित कर जदयू पर्चा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन सोने लाल मेहता की अध्यक्षता में सम्पन्न की गई. सोने लाल मेहता ने इस चौपाल कार्यक्रम में कहा कि बिहार का आज तीव्र गति से विकास हो रहा है. बिहार सरकार समय के मूल्यों को समझते हुए लोगों के लिए काम कर रही है, तथा विकास के मार्ग में अथक प्रयास कर रही हैं. एक समय वह था जब बच्चे विद्यालय नहीं जाना चाहते थे, और आज के वर्तमान समय में अब शिक्षा का परिदृष्य बदल चुका है। शिक्षा से बच्चों को जोड़ने के लिए बिहार में आज जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है. उनका अनुकरण आज दुसरे राज्यों में भी किया जा रहा है.जो कि एक गर्व की बात है. इस मौके पर मथुरापुर पंचायत की मुखिया रीता देवी ने कहा कि नितीश कुमार के कार्यकाल में बिहार और बिहारवासियों की छवि को भारत वर्ष में एक अलग स्थान मिल पाया है. जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने राज्य में स्वास्थय सुविधाओं में सुधार की बात कही, जदयू के राज्य सलाहकार समीति के सदस्य अशोक सिंह ने कहा कि नीतिश कुमार ने राज्य में उत्तम आधारभूत सरचंना के विकास पर विषेश बल दिया है. मौके पर जदयू के जिला महासचिव शंभुझा, उमेश सिंह, सुबोध यादव, अरुण कुमार, अर्जुन सिंह, संघर्ष पटेल ने इस चौपाल में भाग लिया.

– गीता कुमार

जनता की सेवा ही धर्म

पिछले विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर डॉ. मुरारी मोहन झा दरभंगा संसदीय क्षेत्र के बहादुरपुर विधान सभा से जोरदार ढ़ंग से लड़े थे. इस चुनाव में उन्हें 12, 444 मत प्राप्त हुए. समाज सेवी डॉ. मुरारी मोहन झा ने समाज सेवा के माध्यम से अपने आप को चुनाव के लिए तैयार किया है. समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ अपने दल के माध्यम से संघर्ष भी किया. प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर इस शहर में जबरदस्त आन्दोलन चलाया. इसके लिए स्कूलों पर धरना प्रदर्शन किया गया लेकिन प्रशासनिक और धनाढ्य लोगों के असहयोग के कारण सफलता नहीं मिल सकी. फिर भी इस आंदोलन ने समाज में अलख जगा दी. जब–जब स्कूलों में नामांकन प्रारम्भ होता है तो अभिभावक अवश्य रूप से सोचते हैं कि अगर इस समय कांग्रेस की इस आन्दोलन की मदद करते तो आज बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में अधिक फीस नहीं देने पड़ती. आज समाज के लिए ज्वलंत मुद्दा है. दरभंगा में चिकित्सक की फीस वृद्धि को लेकर भी श्री झा ने रणनीति बनायी थी. उन्होंने सरकार से आग्रह भी किया कि गरीब मरीजों के लिए चिकित्सकों का फीस नियंत्रित भी किया जाय. इस विषय पर विचार करना पहले से कदम था. उन्होंने दरभंगा जैसे पिछड़े क्षेत्र में केन्द्रीय प्रयास से थर्मल पावर स्थापित करने का प्रयास किया. केन्द्र से आश्वासन भी प्राप्त हो चुका था लेकिन तकनीकी कारण से यहां थर्मल पावर की स्थापना नहीं हो सकी. अगर उनके प्रयास से इस शहर में थर्मल पावर की स्थापना हो जाती तो दरभंगा की तस्वीर अलग बयान करती. उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से आग्रह किया कि बिहार के संसदीय क्षेत्र में कम से कम सीट कांग्रेस के लिए अवश्य मांग की जाए. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सुरक्षा के लिए गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया तो संभव है कि 2015 के चुनाव में महागठबंधन को अगर बहुमत भिन्न जाती है तो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि वरीय नेताओं के द्वारा महागठबंधन तो कर लिया जाता है लेकिन हम जैसे कांग्रेस के सिपाही को बड़ी परेशानी होती है फिर भी संगठन में नीति का पालन करना आवश्यक है. वे इस आन्दोलन को सफल मानते हैं जब लहेरियासराय यही से बहेड़ी मुख्य पथ पर सड़क बनाने के लिए आन्दोलन किया था. इस आंदोलन के फलस्वरूप ही सड़क का निर्माण हो सका. सड़क इतनी जर्जर स्थिति में थी इस पर पैदल चलना मुश्किल था. इस पथ पर बहादुरपुर प्रखंड, थाना, जिला कृषि विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कार्यालय है लेकिन वर्षों से इस सड़क का निर्माण विधायकों के द्वारा नहीं करवाया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने आन्दोलन कर प्रशासन पर दबाव बना कर सड़क का निर्माण करवाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस से टिकट मिले या नहीं लेकिन वे जनता की सेवा करते रहेंगे. उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे जातिवाद, परिवारवाद सम्प्रदायवाद को छोड़कर आंतरिक मन से वोट दें ताकि राज्य में स्वस्थ एवं स्वच्छ सरकार का निर्माण हो सके.■

– कुमार विनोद

माने तो ठीक, नहीं तो हर सीट पर प्रत्याशी : संजय

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे–जैसे करीब आ रहा है, सभी राजनितिक दलों की तैयारी जोर पकड़ती जा रही हं, अगर चुनाव के पहले के माहौल की बात करें तो आगामी चुनाव में एनडीए एवं यूपीए के बीच जबरदस्त टक्कर होने का अनुमान है. बिहार में लालू, नीतीश एंव कांग्रेस का साथ आना एनडीए का राह मुश्किल कर रही है.लेकिन एनडीए इसे भी चुनौती के रूप में लेकर अपने सभी घटकदलों को साथ में लेकर चुनाव की तैयारी में लगी है. बिहार में चुकी वर्षो से चुनाव जातीय समीकरण के आधार पर लड़ा जाता रही है. इसलिए एनडीए अपने इस समीकरण को और भी मजबूत करने का प्रयास कर रही है .

पी.ए संगमा

संजय वर्मा

एनडीए के घटक नेशनल पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी.ए.संगमा ने पार्टी के बिहार अध्यक्ष संजय वर्मा को स्पष्ट निर्देश दिया है, कि ईसाई, सिख, आदिवासी, दलित, दलित मुस्लिम के बीच अपनी पैर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर एनडीए के लिए जनाधार बनाएं पार्टी अपने इस जनाधार में और विस्तार कर मजबूत करने के लिए आगामी 21 अगस्त को कृष्णा मेमोरियल हॉल में दंभ सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है. जिसमें राज्य के दस हजार प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. बिहार के इतिहास में शायद यह पहली घटना है. जब इन वर्गो को विशेष चिहित कर कोई राजनितिक आयोजन किया जा रहा है. अगर यह आयोजन सफल रहा तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को लगभग एक करोड़ मतदाताओं का सीधा लाभ मिलेगा. नेशनल पीपुल्स पार्टी अपने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन–रात मेहनत कर रही है. पार्टी के बिहार अध्यक्ष संजय वर्मा लगातार राज्य में सभाए कर लोगों को आमंत्रित कर रहें है . संजय वर्मा का कहना है, कि आज तक किसी राजनितिक दल ने समाज के इन वर्गो के लोगों के लिए कभी आवाज नहीं उठाया था . नेशनल पीपुल्स पार्टी इस आयोजन के बहाने सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है. उनका मानना है, कि गठबंधन में उन्हें जो भी सीट मिलें उसपर वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे बाकी सभी सीटों पर उनके कार्यकर्ता एनडीए को मदद करने के लिए एड़ी–चोटी लगा देंगे. संजय वर्मा ऐसी उम्मीद करते है, कि एनडीए गठबंधन के द्वारा उन्हें आगे भी जो कार्य बिहार में सौंपा जाता रहेगा उसके लिए वे सब कुछ लगा देंगे. वर्मा सीटों के विषय में पूछे जाने पर बताते हैं, कि जो भी गठबंधन तय करेगा वो उन्हें मान्य होगा. मगर यदि गठबंधन का रुख नकारात्मक रहा तो वे सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे. इसमें कोई दो मत की बात नहीं की अभी तक एनडीए में सब कुछ साफ नहीं हुआ है सभी घटकदल अपने–अपने तरीके से सीटों का दावा कर रहे है. यहां तक कि एक महत्वपूर्ण गठबंधन के घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है. यह सभी बातें एनडीए को नुकसान पंहुचा रही है. एनडीए को अगर दिल्ली चुनाव से सबक मिला हो तो उसे किसी भी घटकदल को बिना नाराज किये तत्काल जनता के सामने स्थिति रखनी होगी नहीं तो इसका सीधा नुकसान एनडीए को होगा. इस सन्दर्भ में सुशील मोदी का बयान तो और भ्रम पैदा करने वाला है, कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सिर्फ रालोसपा, हम एंव लोजपा के साथ ही चुनाव लड़ेंगी. तो भला अमित शाह का नेशनल पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी.ए संगमा को दिये गए आश्वासन का क्या होगा?

संगमा बिहार में एनडीए के लिए नया जनाधार तैयार कर रहें हं. वो भला कहा जाएगा नेताओं को इन बयानों से बचना होगा नहीं तो गठबंधन की राह और भी मुश्किल हो जाएगी. नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष संजय वर्मा से इस सन्दर्भ में पूछे जाने पर कहते है कि अभी तो वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर दंभ की तैयारी में जुटें है, आगे आने वाले समय में देखा जायेगा. उम्मीद है की ऐसी नौबत नहीं आएगी कि यह जनाधार कहीं और जाए, भाजपा बड़े भाई के रूप में हमेशा से अपने घटकदलों को उचित स्थान देती रही है उम्मीद है की बिहार में भी वह वैसा ही करेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

चुनावी हलचल

सुजीत से कई दल संपर्क में

फतुहा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. जिस तरह से युवा नेता सुजीत कुमार यादव लोगों के बीच में हैं. उससे सभी दलों में खलबली मची हुई है. उल्लेखनीय है, कि लोजपा, भाजपा, रालोसपा और हम के कई नेताओं ने इस दौरान सुजीत यादव से संपर्क साधा है, लेकिन सुजीत यादव अभी अपना पूरा ध्यान जनसंपर्क में लगा रहें हैं. सुजीत यादव का कहना है, कि पुरे क्षेत्र में जनता की समस्या सुन रहा हूं. और संभव उसके समाधान के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं. मुझे उम्मीद है, कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे अपना समर्थन देगी. सुजीत ने गुलमहियाचक, निजामपुर, सुकुलपुर, दौलतपुर, खासपुर, नरयाना, अदालपुर, भिखुआ गावं का दौरा किया. सुजीत के साथ क्षेत्र के दौरे में सूरज यादव, डॉ राजेश दास, टीपू कुमार, राम प्रवेश यादव, जयपाल सिंह, शिव शंकर प्रसाद और अन्य लोग मौजूद थे.

– रजनीकांत पाण्डेय

बिहार में चरम पर अपराध : वरुण

औरंगाबाद विधानसभा सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का जमवाड़ा तो रहा ही साथ ही बिहार प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का अगामन हुआ. इसी मंच से नीतीश–लालू के दोस्ती को बन्दर–मगरमच्छ वाली दोस्ती की संज्ञा देते हुए वरुण कुमार सिंह ने कहा कि बिहार अब जंगलराज 2 की स्क्रीप्ट लिखने की तैयारी कर रहा है और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे. उन्होंने लालू–नीतीश की दोस्ती को स्वार्थ की पराकाश्टा कहते हुए बताया कि ऐसी दोस्ती का हाल आप सभी लोग जानते हैं. जनता की कमाई को जंगलराज 2 में नहीं लगने दिया जायेगा. उन्होंने सम्ममेलन में लोगों से जागृत हो बिहार को बचाने की अपील की और कहा कि दुबारा जंगलराज जाने से हमें बचाना होगा क्योंकि जंगलराज का ट्रेलर अभी से ही दिखने लगा है.

– भारती

जिलाध्यक्ष बने अशोक कुमार सहनी

पूर्वी चम्पारण के युवा नेता अशोक कुमार को जदयू सेवा दल का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है. मोतीहारी के अगरवा मोहल्ला स्थित सहनी के निवास पर जदयू सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष लालबाबू गोप ने मनोनयन किया. सहनी के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने भी जदयू सेवा दल की सदस्यता स्वीकार की. मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष गोप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार कलावती देवी को विजयी बनाने का अहवान किया उन्होंने उम्मीद जताई कि अशोक कुमार सहनी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों और नीतीश कुमार के द्वारा किये गये कार्यो को घर–घर पहुंचायेंगे. मौके पर सहनी ने कहा कि पर्चा पर चर्चा और हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत सेवा दल के साथियों के सहयोग से एक–एक व्यक्ति तक पार्टी का संदेश पहुचाऊंगा. सहनी का युवाओं में बहुत अच्छी पकड़ है. इस अवसर पर प्रभाश प्रताप सिह, पप्पू सहनी, पप्पू कुमार दास, हरेंद्र बैठा, अर्जुन सहनी,लाल बाबू पासवान, श्याम बाबू पटेल, हरेंद्र सहनी, रविन्द्र सहनी, दिनेश सहनी, बलिराम सहनी, जयश्री सहनी, राजेश सहनी, जय प्रकाश सहनी,चुनचुन सहनी सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद थे.■

– राकेश

परबत्ता में प्रत्याशियों की बाढ़

गीता कुमार

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के कई भावी प्रत्याशियों ने अपनी–अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है. लगता है इस क्षेत्र में किस्मत आजमाने वाले नेताओं की बाढ़ ही आ गई है. रालोसपा के अंगद कुशवाहा, भाजपा से प्यूस हजारी, राजद से अखिलेश्वर दास, लोजपा प्रत्याशी प्रो. सुहैली मेहता, भाजपा नेता अखिल कुमार व मन्टु राय, भाजपा से सुमीता देवी राय, छात्र नेता एवं क्रातिकारी समाजसेवी बाबूलाल शौर्य के अलावा राजद से रणवीर यादव, पूर्व मंत्री विधासागर निशाद की पुत्र वधू रंजीता कुमारी निशाद, कांग्रेस से डा.चंदन यादव, विनोद मालाकार, एआईसीसी के सदस्य व पूर्व जिला अध्यक्ष लाल बिहारी सिंह, जयकांत सिह निशाद हम से सम्राट चौधरी की पत्नी एवं इनके पिता शकुनी चौधरी के चुनाव लड़ने की संभावना दिख रही है. सनद रहे कि प्रो. सुहेली मेहता पटना मगध कॉलेज की प्रो. है और समाजसेवा के हर कार्यो में आम जनताओं के सुख–दुख में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने वाली एक मिलनसार महिला प्रत्याशी है. उधर अखिल कुमार राय व मिन्टु राय की भी छवि कुछ कम नहीं है. ये बिहार बॉली बॉल ऐसोशिएसन के उपाध्यक्ष एंव भाजपा के वरिष्ठ चहेते नेता रहे हैं. ये राजनीतिक के क्षेत्र में एक नया मोड़ लाने को बेताब है, और विगत कई वर्षो से जनता की सेवा में निरंतर समर्पित भाव से विचारात्मक व भावनात्मक रूप से चलते रहे हैं. इनके जन उपयोगी कार्य तथा कुशल व्यक्तित्व से परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की सरजमीं पूरी तरह से वाकिफ है. महागठबंधन के प्रत्याशी की बात करें तो सर्वप्रथम रणवीर यादव का नाम परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. गौरतलब है कि परबत्ता से वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी राकेश कुमार व सम्राट चौधरी ने जदयू–भाजपा प्रत्याशी आरएनसिंह को शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया था. रणवीर यादव के नाम के साथ ही साथ यहां कृष्णा कुमारी यादव की भी चर्चा है. उन्होंने बताया कि परबत्ता की जनता चाहती है तो वो साधुवाद के पात्र हैं. परंतु हमारे दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एंव राबड़ी देवी परबत्ता से टिकट देंगे तो मैं निश्चित ही चुनाव जीतकर लालू–राबड़ी के हाथों को मजबूत करूंगी. वहीं भाजपा–लोजपा व रालोसपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में परबत्ता के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी व चौथम के पूर्व प्रमुख तथा भोजपुरी फिल्म के अभिनेता नरेश बादल की भी चर्चा हो रही है. राजनीतिक सुझ–बुझ वाले व्यक्ति का मानना है कि नरेश बादल चौरसिया समाज से आते हैं, ऐसे में इन्हें यहां से लोजपा प्रत्याशी बनाया जाता है, तो भाजपा समीकरण उपेंद्र कुशवाहा के समीकरण इत्यादि वर्गो के समर्थन प्राप्त कर जीत सुनिश्चित कर सकते हैं. जबकि युवा व समाजसेवी बाबूलाल शौर्य भी अपने कार्यकौशल एवं कई बार आम जनता के लिए धरना व प्रदर्शन कर सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने अपने जन–आंदोलन के बदौलत जनता के बीच पहचान बनाई है. ये भी अपनी दावेदारी दिखाने में किसी से पीछे नहीं है. वहीं खगड़िया भाजपा जिलाध्यक्ष रामानुज चौधरी को अगर देखा जाए तो वे छोटी से छोटी समस्याओं में आमलोगों के साथ हमेशा नजर आते हैं. ग्रामीणों से लेकर शहरी परिवेश में भी उन्होंने एक अलग पहचान बना रखी हैं. श्री चौधरी भी टिकट पाने के जुगत में बड़े नेताओं के संपर्क में हैं.

वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्पित एवं निष्ठावान सिपाही विनोद झा जो भाजपा को मजबूत करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता हमेशा दिखायी एवं अपने 30 वर्षो के राजनीतिक जीवन में करीबन सात बार जेल यात्रा की. मृदुभाषी विनोद झा अपने जूनून के कारण वर्ष 1990 से 2000 तक हिन्दु हृदय सम्राट कहलाये. लेकिन इस निष्ठावान सिपाही की गरीबी इनके लिए अभिशाप है. क्या नेतृत्व इस सच्चे सिपाही को एक अवसर प्रदान कर कार्यकर्ता को सम्मान देगी. परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की भी संख्या कुछ कम नहीं है. यहां चौरसिया समाज का मत भी एक निर्णायक मत माना जाता है. जबकि वैश्य सहनी, पासवान, लागर, दलित व महादलित एवं पचपनियां मतदाता की भी अच्छी खासी संख्या है. इस विधानसभा क्षेत्र में जहां भाजपा, लोजपा व रालोसपा के संयुक्त उम्मीदवार को स्वर्ण, वैश्य, मारवाड़ी, चौरसिया, पासवान आदि समुदाय के मतों को लोग जोड़कर चल रहे है. इसी समीकरण में भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार का जाति के आधार पर भी आंका जा सकता है. अब आगामी चुनाव में देखना यह है कि यहां जाति समीकरण कामयाब होती है, या विकास का आधार इन सब परिस्थियों के बावजूद भी अखिल कुमार राय के लिए परेशानी वाली बात यह हो सकती है कि 2014 के विधानसभा उपचुनाव में राजग के घटक दल लोजपा की प्रत्याशी रही सुहेली मेहता क्षेत्र में अपनी सक्रीयता बनायी हुई हमेशा से नजर आयी है. उपचुनाव में यहां भाजपा ने लोजपा को सीट दी थी और उम्मीदवार के रूप में सुहेली मेहता रही थी. सुहेली मेहता पुन चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी दिख रही है. उधर हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा से सम्राट चौधरी या इनके परिवार के किसी भी एक सदस्य की चर्चा जोरों पर है. बहरहाल जो भी हो विकास की राजनीति ही कामयाब होनी चाहिए. क्योंकि पहले की उपेक्षा मतदाता अब ज्यादा शिक्षित और जागरूक हुए हैं. इसका निर्णय अब वक्त आने पर खुद ही स्पष्ट हो पायेगा.■

अखिल कुमार राय, बाबू लाल, सुहेली मेहता, कृष्ण यादव, आरएन सिंह, विनोद झा, नरेश बादल, प्रदीप तिवारी

पिछले अंक से आगे SBI PO PHASE 1 REASONING TEST

सुबोध कुमार, Director
S.T.C., Motihari

24. किसी कोड भाषा में GO कैसे लिखा जाता है.
I) उस कोड भाषा में GO home now को jo ho na लिखा जाता है. II) उस कोड भाषा में come home leter को pa ta ho लिखा जाता है.

25. D का M से क्या संबंध है–
I) K और N, D की दो बहनें हैं.
II) K का पिता M का भाई है.

26. 40 विद्यार्थियों की कक्षा में उपर से समीर का क्रमांक कौन सा है–
I) निखिल जो समीर से पांच क्रमांक नीचे है, वह नीचे से दसवां है.
II) सुरेश जो समीर से छह क्रमांक पर है. वह उपर से बीसवां है-
a) 813 b) 479 c) 564 d) 385 E) 792

27. प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिये जाये तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी–
a) 813 b) 479 c) 564 d) 385 E) 792

28. निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक है–
a) 1 b) 7 c) 6 d) 8 E) 9

29. यदि सफेद को काला, काला को लाल, लाल को नीला, नीला को पीला तथा पीला को धूसर कहेंगे तो आकाश का रंग क्या होगा–
a) नीला b) लाल c) पीला d) Not determined e) N-t

30. क्या भारत में थर्मल पावर प्लांट लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिये– तर्क:– (4) हां, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि रोकने का यही एक तरीका है. (II)– नहीं, देश के अधिकांश भागों में बिजली की बहुत कमी है. अत: बिजली का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है. (III)– नहीं बहुत से विकसित देशों ने अपने यहां थर्मल पावर प्लांट लगाना जारी रखा है–
a) कोई ठोस नहीं है b) केवल I ठोस है c) केवल II ठोस है d) केवल III ठोस है E) या तो I या II ठोस है

31. **कथन:** क्या बड़े शहरों में सड़क की मरम्मत का काम केवल देर रात को किया जाना चाहिये. तर्क: (I)– नहीं, इस तरह काम पूरा नहीं होगा. (II) नहीं, बिजली का अनावश्यक उपयोग होगा (iii)– हां, दिन के दौरान मरम्मत का काम होने पर आने–जाने वालों को बहुत कठिनाई होगी–
a) कोई ठोस नहीं है b) केवल I ठोस है c) केवल III ठोस है क) केवल II और III ठोस है E) केवल I और II ठोस है

32. **कथन:** क्या भारत में सिंचाई हेतु भूमिगत जल खिंचने पर उच्चतम सीमा लगायी जानी चाहिये. तर्क: (I)– नहीं, भारत में खाद्यान उत्पादन हेतु सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के बहुत से भागों में यह भूमिगत जल पर निर्भर है. (II)– हां, देश के कुछ भाग जहां सिंचाई भूमिगत जल पर निर्भर है, वहां भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है. इसका नतीजा पर्यावरण के लिये गंभीर हो सकता है. (III)– हां, भारत अब भूमिगत जल खिंच नहीं सकता क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इसके खिलाफ भारत को चेतावनी दी है.
a) I और II ठोस हैं b) II और III ठोस है c) I और III ठोस है d) I, II और III ठोस है E) इनमें से कोई नहीं.
a) केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है. b) केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है c) यदि या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है. d) यदि न तो I और II अनुसरण करता है. E) यदि I और II दोनों अनुसरण करता है.

33.– कथन S¾R>¬Q, P<Q
निष्कर्ष: (I)– S>¬P (II)– R>P

34. **कथन:** S>¬M<Y=Z>F>T
निष्कर्ष: (I)& S>F (II) Y>T

35. जिस प्रकार सरसों संबंधित है बीज से, उसी प्रकार गाजर संबंधित है ---- से
a) फल b) तना c) फूल d) जड़ E) इनमें से कोई नहीं

अगले अंक में भी

वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र

लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित भाजपा यहां से इस बार विधान सभा चुनाव जीतने को भी बेताब है तथा उसे भरोसा है कि इस सीट पर इस बार कमल खिलेगा. लेकिन एनडीए व राजद, जदयू, कांग्रेस गठबंधन के गणित को बसपा, सपा जैसे दल गड़बड़ाने की क्षमता रखते हैं. पड़ोसी राज्य यूपी से लगे होने के कारण इन दलों के समर्थक व संगठन भी यहां मौजूद हैं. भाजपा से यहां चुनाव लड़ने के लिए कई लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं. लेकिन सबसे प्रमुख रूप से इन सबके बीच धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह का नाम उभर कर सामने आ रहा है.

राजेश सिंह

धीरेंद्र प्रताप सिंह

संजय सिंह

बगहा लोकसभा क्षेत्र के अधीन पड़ने वाला 01 वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र एक तरफ नेपाल तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से जुड़ा है. जिसका असर कई बार यहां के चुनाव में पड़ता है. 2010 में विधानसभा के नये परिसीमन में धनहां विधानसभा का विलोपन कर वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ. जिसमें बगहा विधानसभा क्षेत्र के वाल्मीकि नगर समेत कुछ नये क्षेत्रों को इसमें समाहित किया गया था. इस विधानसभा को गंडक नदी दो भागों में विभाजित करती है. गंडक नदी द्वारा विभाजित इस विधानसभा में पड़ने वाले चार प्रखंड ठकराहां, भितहां, मधुबनी, पिपरासी का भौगोलिक जुड़ाव उत्तर प्रदेश से सहज होने के कारण यहां की राजनीति पर भी इसका प्रभाव हर चुनाव में नजर आता है. इसी के कारण यूपी की राजनीति में काफी रसूख रखने वाले बसपा, सपा जैसे दल भी यहां के चुनाव नतीजों पर असर डालने की कूव्वत रखते हैं. वर्तमान विधायक राजेश सिंह पहली बार बसपा के टिकट पर ही यहां से विजयी हुए थे. वोटों के होने वाले इस बिखराव या ध्रुवीकरण का असर हर बार यहां के चुनाव परिणाम पर पड़ता नजर आता है. जिस पर राजनैतिक दल समेत प्रत्याशी की पैनी नजर हर चुनाव में रहती है. विगत चुनाव के आंकड़े पर गौर करे तो इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 289269 है. जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 131453 तथा पुरूष मतदाताओं की संख्या 157816 है. इस विधानसभा में बूथों की कुल संख्या 272 है. अभी इस सीट पर जदयू के विधायक राजेश सिंह का कब्जा है. पहली बार बसपा के टिकट पर निर्वाचित श्री सिंह लगातार यहां से चार बार विधायक निर्वाचित हुए हैं. लेकिन भाजपा-जदयू गठबंधन के टूटने के बाद होने वाले विधान सभा चुनाव में इनकी मुश्किलों में इजाफा होना तय माना जा रहा है. क्योंकि पूर्व में भाजपा जदयू गठबंधन के तहत यहां की बगहा लोकसभा सीट भी जदयू के पास थी. जहां से जदयू के वैद्यनाथ महतो सांसद चुने गये थे. लेकिन गठबंधन टूटने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा से यह सीट जदयू से छीन ली तथा यहां से नरकटियांगज के तत्कालीन भाजपा विधायक सतीश चंद्र दूबे सांसद चुने गये. लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित भाजपा यहां से इस बार विधान सभा चुनाव जीतने को भी बेताब है तथा उसे भरोसा है कि इस सीट पर इस बार कमल खिलेगा. लेकिन एनडीए व राजद, जदयू, कांग्रेस गठबंधन के गणित को बसपा, सपा जैसे दल गड़बड़ाने की क्षमता रखते हैं. पड़ोसी राज्य यूपी से सटा होने के कारण इन दलों के समर्थक व संगठन भी यहां मौजूद है. भाजपा से यहां चुनाव लड़ने के लिए कई लोग अपनी दावेदारी कर रहें है. लेकिन सबसे प्रमुख रूप से इन सबके बीच धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह का नाम उभर कर सामने आ रहा है. रिंकू सिंह ने वर्ष 2010 में बसपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा जदयू के लहर के सामने उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था. चुनाव के कुछ अर्से बाद वह भाजपा में शामिल हो गये.

भाजपा के संभावित उम्मीदवार धीरेंद्र प्रताप शाही उर्फ रिंकू सिंह की माने तो उनका जुड़ाव सीधा जनता से है. विगत विधान सभा चुनाव के समय से ही वह यहां की जनता के बीच उनके हर दुख दर्द में साथ है. श्री सिंह ने बताया कि वह पार्टी के सिपाही हैं. अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है तथा यहां से टिकट देती है, तो वह चुनाव अवश्य लड़ेंगे. भाजपा-जदयू गठबंधन टूटने का सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा. ऐसा उनका मानना है. उन्होंने कहा कि नौरंगिया गोली कांड से यहां की जनता आज तक उबर नहीं पाई है.

भौगोलिक रूप से गंडक के रहमो करम पर आधारित कृषि ही यहां के निवासियों के जीवनयापन का मुख्य साधन है. मुख्य फसल के रूप में गंड़क के दियारा क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर गन्ना की खेती होती है. जिसे किसान यहां के एक मात्र उद्योग बगहा स्थित चीनी मिल को देते है. राज्य के एक मात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में पर्यटन की अपार संभावनायें हैं. लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिये आज तक बेहतर व सार्थक प्रयास सरकारी अथवा गैरसरकारी स्तर पर नहीं किये जा सके. स्थानीय लोगों की माने तो प्राकृतिक सुंदरता से ओत-प्रोत वाल्मीकि टाइगर रिर्जव में अंग्रेजी राज में शिकार करने के लिए काफी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया था. आज भी उस जंगल में कई जगह बंगले आदि भी है. जिसमें हर बुनियादि सुविधा पूर्व में मौजूद थी. लेकिन शिकार पर सरकारी प्रतिबंध के बाद इनके समुचित रखरखाव की तरफ से ध्यान हटने लगा. जिससे इन जगहों पर बुनियादी सुविधाओं में कमी हो गयी. अगर सरकार इनके रख-रखाव को बेहतर कर इसका उपयोग पर्यटन को बढ़ावा देने में करने की व्यवस्था कर सके तो इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है. जिससे कृषि पर लोगों की निर्भरता कम होगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध हो पायेंगे. हालांकि सरकार के तरफ से इक्का- दुक्का प्रयास दोन क्षेत्र में टूरिस्ट हट्ट, वाल्मीकि नगर में जंगल सफारी व होटल को शुरू किया गया. लेकिन बेहतरीन व्यवस्था की कमी व इसका समुचित प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण यह पर्यटकों को काफी संख्या में आकर्षित नहीं कर पाया. इस विधानसभा क्षेत्र स्थित गंडक के पार के चार प्रखंड ठकराहां, मधुबनी, भितहां व पिपरासी के लोग आजादी के बाद से आज तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहे है. आज भी इन गांवों का प्रखंड मुख्यालय से बेहतर सड़क संपर्क नहीं हो पाया है. यहां तक की आजादी के बाद से आज तक इन चारों प्रखंड के गांवों में बिजली नहीं पहुंच पायी है. शुद्ध पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाओं से यहां की आबादी महरूम है. हालांकि चौतरवा व धनहां को जोड़ने वाले नवनिर्मित सड़क पुल ने जिला मुख्यालय समेत राज्य के अन्य हिस्सों से इन प्रखंड के लोगों को सीधा सड़क संपर्क मयस्सर कराया है.

रिपोर्ट कार्ड:-

यहां के विधायक राजेश सिंह की माने तो उन्होंने जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस समय इस क्षेत्र में अपराध चरम पर था. उन्होंने गंडक, गन्ना, गुंडा को मुद्दा बनाया तथा जीतने के बाद अपराध पर करीब करीब पूर्णत: लगाम लगाने का काम किया. उनके प्रयास से ही निर्धारित समय से पहले गंडक नदी पर धनहा से चौतरवा के बीच सड़क पुल का निर्माण संपन्न हो पाया. पीपी तटबंध पर भितहां से मधुबनी के बीच 27 करोड़ की लागत से पक्की सड़क का निर्माण कराया गया है. अब इस सड़क का विस्तार ठकराहां व पिपरासी तक कराया जायेगा. बांसी से धनहा-चौतरवा स्टेट हाइवे पर 40 करोड़ की लागत से पुल निर्माण भी कराया जा रहा है. भितहां के मुशहरी में सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा के लिये अंबेडकर आवासीय विद्यालय शुरू कराया जा रहा है. जिसमें दलित बच्चों के साथ सामान्य वर्ग के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर पायेंगे. ठकराहां में बिजली ग्रिड निर्माण का कार्य शुरू हुआ है. जिसे गोपालगंज व बेतिया स्थित ग्रिड से जोड़ा जायेगा. इसे यूपी के कुशी नगर से जोड़े जाने की भी योजना है जिसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री से उन्होंने समय मांगा है, ताकि इस संबंध में आगे बातचीत हो सके. साथ हीं बिजली से वंचित गंड़क पार के चारों ब्लाक में तार पोल आदि लगाने का कार्य जल्दी ही शुरू होगा. साथ ही मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधी से क्षेत्र में कई सारे पुल- पुलिया, नाला अदि का निर्माण कराया गया है.

भाजपा के संभावित उम्मीदवार धीरेंद्र प्रताप शाही उर्फ रिंकू सिंह की माने तो उनका जुड़ाव सीधा जनता से है. विगत विधान सभा चुनाव के समय से हीं वह यहां की जनता के बीच उनके हर दुख दर्द में साथ है. श्री सिंह ने बताया कि वह पार्टी के सिपाही हैं. अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है तथा यहां से टिकट देती है, तो वह चुनाव अवश्य लड़ेंगे. भाजपा-जदयू गठबंधन टूटने का सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा. ऐसा उनका मानना है. उन्होंने कहा कि नौरंगिया गोली कांड से यहां की जनता आज तक उभर नहीं पाई है. उस कांड में मारे गये लोगों के परिजनों को अभी तक सरकार न्याय नहीं दिला पाई है ओर न हीं इसके लिये दोषियों को सही ढ़गं से न्याय की परिधि में लाया जा सका है. जिसका लोगों में आक्रोश है. स्थानीय विधायक द्वारा जनहित तथा विकास का कार्य नहीं कराये जाने का आरोप भी श्री सिंह ने लगाया. उन्होंने कहा कि चंपापुर गोनौली में पार्टी के विधानसभा सम्मेलन में लोगों के उत्साह व उपस्थिति ने यह तय कर दिया कि विधानसभा चुनाव में जीत भाजपा की होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

श्रीमते रामानुजाय नमः स्थापित-1978 श्री धन्वत्तरये नमः
स्वामी राघवेन्द्राचार्य तिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
करजरा स्टेशन गया (बिहार), Website : www.srtacollege.com
सत्र 2015-16 में बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा सम्बद्ध एवं सीसीआईएम एवं आयुष द्वारा पाँच साल की स्थाई मान्यता प्राप्त बिहार का एक मात्र आर्युवेद महाविद्यालय है।
बी.ए.एम.एस. नामांकन सूचना
Admissions OPEN
सत्र 2015-16 में नामांकन हेतु इच्छुक छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं नामांकन आवेदन पत्र कार्यालय से रू. 1500/- एक हजार पांच सौ मात्र जमाकर तथा डाक टिकट द्वारा रू. 1550/- एक हजार पाँच सौ पचास मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य के पदनाम से जो गया में देय हो भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
योग्यता: इन्टर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या समकक्ष (50% अंक अनिवार्य)
प्रवेश फार्म की अन्तिम तिथि - 31-07-2015
प्राचार्य:- 09771511031, कार्यालय-09430657935, 09431476551
जी.बी. सदस्य - 09608204094
-नामांकन फार्म प्राप्ति कैम्प कार्यालय-
रामानुज मठ (देवघाट) पो.-चांदचौरा, गया- 823001
डॉ. प्रेम नारायण तिवारी प्राचार्य

पूर्वी भारत में पहली बार विश्व की आधुनिकत्तम तकनीक द्वारा निर्मित
मजबूती की गारंटी
Top Line™
Every Drop Counts
हिन्दुस्तान का गौरव स्वास्थ्य का रखे पूरा ध्यान
JAS-ANZ ISO 9001:2008 CERTIFIED
GUARANTEE 31 3 Layer YEARS
GUARANTEE 21 2 Layer YEARS
3 Layer & 2 Layer
Blow Moulded Tanks
HIGHER STRENGTH & UNBREAKABLE
100% VIRGIN RAW MATERIAL
UV STABLE
FOOD GRADE MATERIAL
स्वास्थ्यवर्द्धक पानी की टंकियाँ हर घर के लिए
Top Line
Top Line
Top Line
For Trade Enquiry : M/S. CRESTIA POLYTECH PVT. LTD.
Patna - Contact No. : 0612-2320226, 2321343, 09534789999, 09162414121
E-mail : crestiapolytech@yahoo.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

13 जुलाई –19 जुलाई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

यूपी में पीसीएस से लेकर दारोगा, क्लर्क, सिपाही भर्ती तक में यादव भरे जा रहे हैं

नौकरशाह का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश सरकार के पक्षपातवाद के खिलाफ प्रदेश के नौकरशाहों में जबरदस्त नाराजगी व्याप्त होती जा रही है. इस वजह से आला नौकरशाही में विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं. उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की शीर्ष परीक्षा से लेकर दारोगा और सिपाहियों तक की भर्ती में सरकार पर पक्षपात के सीधे आरोप लगे कि केवल यादव जाति के लोगों को ही अप्रत्याशित लाभ दिया जा रहा है. इस पर तमाम विरोध प्रदर्शन भी हुए और कई मामले अदालत तक भी पहुंचे.

अब प्रदेश के आला नौकरशाह सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव सूर्य प्रताप सिंह ने सपा सरकार में खुलेआम भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि समूह ग की भर्ती में एक खास जाति और खास क्षेत्रों के लोगों की भर्ती हो रही है. साथ ही कमाई और गैर कमाई वाले विभागों में भर्ती के लिए रिश्वत के अलग-अलग रेट तय किए गए हैं. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह के मुताबिक इन भर्तियों में सभी पदों पर खास तौर पर यादव जाति के लोगों को ही भरा जा रहा है. इसमें न मुसलमानों को कोई फायदा पहुंचाया जा रहा है और न पिछड़े वर्ग के अन्य लोगों को.

प्रमुख सचिव ने कहा है कि यादवों में भी सिर्फ छह-सात खास जिलों के अभ्यर्थियों की ही भर्ती की जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया है कि अन्य जिलों के यादवों की भर्ती क्यों नहीं हो रही, उनका क्या दोष है. उन यादवों ने भी तो सपा को वोट दिया था. भर्ती के बारे में उन्होंने कहा है कि रेट तय हैं. अगर कमाई वाले विभाग में नौकरी चाहिए तो 20-25 लाख, वरना 15-20 लाख देने पर नौकरी मिल रही है. उन्होंने असली मेरिट लिस्ट को दरकिनार करने और आरटीआई के जरिए सूचना नहीं देने का आरोप भी लगाया है.

सूर्य प्रताप सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जब भर्ती प्रक्रिया पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव ने सवाल खड़े किए तो प्रोन्नति के बहाने उन्हें हटा दिया गया. आयोग में आठ सदस्यों के पद खाली थे, लेकिन सिर्फ तीन सदस्य रखकर ही भर्तियां की जा रही हैं. इनमें से अध्यक्ष राजकिशोर यादव और दूसरे वरिष्ठ सदस्य का नाम सुरेश यादव है. प्रमुख सचिव ने कहा कि मायावती ने 2007 में भर्ती में भ्रष्टाचार पर आयोग को भंग कर दिया था. सपा सरकार ने 25 जून 2014 को फिर से आयोग का गठन कर समूह ग में तीन लाख भर्तियों का फैसला किया और फिर से भ्रष्टाचार की शुरुआत कर दी.

भर्ती संबंधी नियमावली 11 मई 2015 को बनी थी. इस दौरान पशुधन समेत कई और बदनाम विभागों में विभागीय भर्ती हुई. सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि एक न एक दिन यह भर्तियां अनियमित घोषित होंगी. प्रमुख सचिव के मुताबिक 100 नंबर में से लिखित परीक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन हथकरघा विभाग में 159 पदों पर लिखित परीक्षा नहीं हुई. एक घंटे में ही मेरिट लिस्ट बना दी गई. खास इलाकों को छिपाने के लिए चुने गए लोगों के नाम-पते नहीं दिए गए. सही फोटो न लगाने की बात कहकर सैकड़ों आवेदन खारिज हुए. श्री सिंह ने पूछा कि आयोग कैसे जानता है कि फोटो सही नहीं हैं? उल्लेखनीय है कि इससे पहले सूर्य प्रताप सिंह ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने उस वक्त फेसबुक पर लिखा था, अन्नदाता मुसीबत में और यह राजनीतिक चकल्लसबाजी में समय खराब क्यों? पूरे देश में बर्बाद हुई 185 लाख हेक्टेयर फसल में से 75 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ. सरकारी आंकड़े के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में 1100 करोड़ रुपये कीमत की फसल का नुकसान हुआ. फिर अब तक सिर्फ 175 करोड़ के मुआवजे का ही वितरण क्यों किया गया? किसान का 7500 करोड़ का गन्ना मूल्य बकाया है, पूर्व के वर्षों का भी बकाया है. किसान कहां जाए? अन्नदाता मुसीबत में आत्महत्या कर रहा है और वह कह रहे हैं, कोई नहीं मर रहा, क्यों परेशान हो, यह तो सब चलता है! सौ से ज्यादा किसान मर चुके हैं, अब तो जागना चाहिए.

सूर्य प्रताप सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को खास तौर पर निशाने पर लिया था. लखनऊ में आयोजित इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के क्रिकेट खेलने में समय गंवाने पर उन्होंने फेसबुक पर लिखा, अन्नदाता मुसीबत में और लखनऊ में ग्रामीण क्रिकेट लीग का ग्लैमर. इसके साथ उन्होंने सात किसानों ने जान दी की हेडिंग वाली एक अखबार की कटिंग भी पोस्ट की थी. उसी फोटो के ठीक नीचे मुख्यमंत्री की क्रिकेट खेलते हुए फोटो पोस्ट की गई थी और उसके साथ ही क्रिकेट लीग में डांस करने वाली चीयर लीडर्स की भी फोटो चस्पा थी. सूर्य प्रताप सिंह इससे पहले फेसबुक पर नकल रोको अभियान चला चुके हैं. वे यह कहकर चर्चा में आ चुके हैं कि प्रदेश में दस हजार करोड़ का नकल का कारोबार है.

इन वजहों से सूर्य प्रताप सिंह, जिन्हें एसपी सिंह भी कहते हैं, इन दिनों राज्य सरकार की आंख में खूब चुभ रहे हैं. उन्होंने इसके पहले नकल विरोधी अभियान चलाया था और 26 जिलों के 151 परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल पकड़ी गई. एक केंद्र पर एक मंत्री की बेटी नकल करती पकड़ी गई. इस पर प्रशंसा के बजाय सरकार उन्हें ही निशाना बनाने लगी. डेढ़ वर्ष में छह तबादले झेल चुके एसपी सिंह जब माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव थे, तो उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में संगठित नकल को रोकने के लिए ठोस योजनाएं बनाईं, लेकिन उन पर ठीक से अमल हो पाता, उसके पहले ही नकल माफियाओं ने उनकी छुट्टी करवा दी. तकरीबन महीनेभर में ही उनका तबादला हो गया. 2000 करोड़ के नकल उद्योग से लड़ने के अलावा सिंह ने किसानों की आत्महत्या के सवाल को भी बड़ा सवाल बनाया. उन्होंने बड़े अधिकारियों सहित राज्य की सत्ता को भी इसके लिए कठघरे में खड़ा किया. श्री सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ज्यादातर अधिकारी राजनीतिक रूप से निष्पक्ष नहीं रह गए हैं. अपनी सुविधा और फायदे के लिए वे सत्ता की राजनीति से जुड़ जाते हैं और इसके बाद उन्हें किसी जवाबदेही की जरूरत नहीं रह जाती.

बगावती तेवरों से सरकार के लिए असहज स्थितियां पैदा कर रहे वरिष्ठ आईएएस डॉ. सूर्य प्रताप सिंह और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर सरकार कड़े कदम उठाने का मन बना रही है. शासन का मानना है कि सूर्यप्रताप सिंह और अमिताभ ठाकुर न सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार के कार्यकलापों के बारे में तल्ख टिप्पणियां करते हैं, बल्कि कई मामलों में तो सक्रिय एक्टिविस्ट और राजनीतिकों की तरह काम भी करते हैं. वे अखबार और टीवी चैनलों पर सरकार के विरुद्ध टिप्पणियां कर रहे हैं. आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर अवकाश ले कर विवादास्पद मामलों में स्वयंभू जांच करने चले जाते हैं और सरकार असहज स्थिति में पड़ जाती है. पत्रकार जगेंद्र सिंह को आग लगा कर मार डाले जाने का मामला हो या कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी का घर फूंकने की घटना में पुलिस महानिदेशक (अब पूर्व) एके जैन के लिप्त रहने का, अमिताभ ठाकुर ने इसे उजागर करने में सक्रिय भूमिका निभाई. अमिताभ ने ही नेताओं को दी जाने वाली गार्ड ऑफ ऑनर का चलन खत्म करने की मांग की थी. हाल ही में अमिताभ ठाकुर ने सेवानिवृत्ति के बाद आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति पर सवाल उठाए. मुख्यमंत्री के खास शंभू सिंह यादव और आजम खान के निजी सचिव के एक्सटेंशन को आधार बना कर उठाया गया यह मामला जनहित याचिका के रूप में तब्दील होकर हाईकोर्ट में विचाराधीन है.

कभी आईएएस संवर्ग के ही दो सदस्यों ने वोट डाल कर अपने बीच का महाभ्रष्ट चुना था, इसमें अखंड प्रताप सिंह और नीरा यादव का नाम आया था. इस लड़ाई के सूत्रधार रहे पूर्व आईएएस अधिकारी धर्म सिंह रावत सरकारी तंत्र के खिलाफ 1986 में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना पर भी बैठ गए थे. रावत कहते थे कि लोकतंत्र में असली सत्ता जनता के हाथों में होती है. उनका कहना था कि असली बात जवाबदेही और पारदर्शिता है, यह होगी तो भ्रष्टाचार खुद-ब-खुद खत्म हो जाएगा. रावत जैसे ईमानदार और नैतिक व्यक्ति की मृत्यु घोर उपेक्षा और किल्लत में हुई.

उंगली पर गिने-चुने नौकरशाह अपने दम पर आवाज भले ही उठा रहे हों, लेकिन जमीनी परिदृश्य यही है कि सत्ता पर कोई भी पार्टी आसीन हो, वह सत्ता में रहे पूर्ववर्ती दल के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है. अखिलेश यादव की सरकार में उन सभी नौकरशाहों को संरक्षण और शक्ति मिली हुई है, जिन्होंने मायावती के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कारनामे किए. ऐसा कोई जिला नहीं, जहां प्रशासन के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप न हो. राज्य के 25 से ज्यादा बड़े अधिकारियों के खिलाफ बड़ी जांचें चल रही हैं, लेकिन नोएडा प्लॉट आवंटन मामले में सजायाफ्ता राजीव कुमार जैसे अधिकारी नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव बने हुए हैं और नौकरशाहों की नियुक्तियां फाइनल करते हैं. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर में वापस भेज दिए गए विवादास्पद आईएएस अफसर सदाकांत भी बड़े ओहदे पर तैनात हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

ऐसे छाई यादव-मेधा

उत्तर प्रदेश पीसीएस-2011 की मुख्य परीक्षा के नतीजे जब 2013 में आए तो प्रदेशभर में तहलका मच गया था. उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पीसीएस परीक्षा में छुट कर चला यादववाद उजागर हुआ. उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव पर ऐसी बेजा हरकतें करने का आरोप लगा. लेकिन इन आरोपों से क्या फर्क पड़ता है, जब शीर्ष सत्ता के संरक्षण में यह सब हो रहा हो तो. पी-सीएस-2011 के नतीजों में चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित 86 छात्रों में से करीब 50 छात्र यादव जाति के ही थे और एकाध अपवाद को छोड़कर यादव जाति के सभी सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 200 में से 135 से 140 के बीच अंक दिए गए. परीक्षा परिणाम ऐसा मजेदार बना कि यादव जाति के जिन छात्रों को मुख्य परीक्षा में तमाम दूसरे छात्रों से कम अंक मिले थे, उन्हें भी साक्षात्कार में अधिकतम अंक दिए गए. समाजवादी पार्टी की सरकार में योग्यता की कद्र यह है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को साक्षात्कार में औसतन 115 अंक ही दिए गए. ओबीसी के गैर यादव छात्रों को औसतन 110 अंक और अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को साक्षात्कार में औसतन 105 अंक दिए गए. यहां तक कि पीसीएस के टॉपर हिमांशु कुमार गुप्ता को भी साक्षात्कार में महज 115 अंक ही मिले. बेशर्मी इतने पर ही नहीं रुकी. सामान्य श्रेणी में जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र अपग्रेड हुए, वे सारे छात्र भी सिर्फ यादव जाति के थे. यह समाजवाद की असली लीला है.

यूपीपीसीएस का कमाल : 86 एसडीएम में 54 यादव

यह योग्यता के बजाय तिकड़म की मेधा का कमाल है कि सपा शासन में आए यूपीपीसीएस परीक्षाफल में एसडीएम चुने गए 86 लोगों में 54 यादव जाति के हैं. अतिपिछड़ा समाज मंच के संयोजक श्रीकांत गुप्त साहू ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार केवल यादवों के कल्याण में जुटी हुई है. राज्य में 40 फीसद आबादी अतिपिछड़ों की है, लेकिन 27 फीसदी आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी चार फीसद भी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों के साथ भी सरकार में सौतेला व्यवहार हो रहा है. प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश चौरसिया ने मिर्जापुर के आरटीओ चुन्नीलाल प्रजापति से अभद्रता की, वहीं बांदा में देवीदयाल कुशवाहा की हत्या कर दी गई, लेकिन इन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों पर अब तक सपा सरकार ने कार्रवाई नहीं की. अति पिछड़ा समाज मंच ने सरकार की इस पक्षपातपूर्ण नीति के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

विधानसभा अध्यक्ष पर अवैध नियुक्ति के आरोप

अंशुमान प्रांजल

उत्तर प्रदेश में गंगा बह रही है और सत्तासीन दल के लोग हाथ धोने की होड़ में लगे हैं. खूब नहा रहे हैं. इसी नहाने-धोने में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय का भी नाम आ गया, जिन्होंने अपने दो दामादों को विधानसभा में चुपचाप नौकरी दे दी. राज्यपाल राम नाईक तक शिकायत पहुंची है. मामला विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ा है, इसलिए विधायी तौर पर मामला गंभीर तो है ही.

विधानसभा अध्यक्ष के दो दामादों को विधानसभा में दी गई नौकरी का मसला सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने उठाया और इसे राज्यपाल तक पहुंचा दिया. राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में डॉ. ठाकुर ने लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने अपने दोनों दामादों को नियमों को दरकिनार कर विधानसभा के वरिष्ठ पदों पर नियुक्त कर लिया है. उन्होंने एक दामाद को संपादक के पद पर तो दूसरे को ओएसडी बनाया है. 22 मार्च 2013 को प्रदीप कुमार मिश्र पुत्र दुखहरण प्रसाद मिश्र (बलरामपुर) को विधान सभा सचिवालय में संपादक के पद पर नियुक्त किया गया. उनका वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वाले स्तर का है. आदेश के अनुसार 21 मार्च 2015 को संपादक दुखीराम के मुख्य संपादक के पद पर तरक्की से खाली हुए स्थान पर प्रदीप कुमार मिश्र की नियुक्ति हुई.

राज्यपाल से की गई शिकायत में कहा गया है कि इस नियुक्ति में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो स्पष्ट रूप से बड़ी अनियमितता की तरफ इशारा कर रहे हैं. प्रदीप कुमार मिश्र विधान सभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय के सगे बड़े दामाद हैं. इसी वजह से इस मामले में आनन-फानन में सारी कार्यवाही हो गई. 21 मार्च को दुखीराम प्रोन्नत हुए और दो दिन के अन्दर नई नियुक्ति भी कर दी गई. जाहिर है इतने कम समय में नियुक्ति की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ. नूतन ठाकुर ने लिखा है कि इस मामले में न तो कोई विज्ञप्ति निकाली गई और न आवेदन आमंत्रित किए गए. चुपके-चुपके यह नियुक्ति कर दी गई. इस पद के लिए पूर्व में निर्धारित न्यूनतम अर्हता की भी अनदेखी कर दी गई. 16 जनवरी 1986 और 08 अगस्त 1988 के इस पद के लिए प्रकाशित सूचना के अनुसार न्यूनतम आवश्यक अर्हता साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित थी और साथ ही संपादन कार्य में पांच वर्ष का अनुभव या ऐसा नहीं होने पर विधान मंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर पांच वर्ष की सेवा की शर्त थी. प्रदीप मिश्र एमकॉम हैं न कि साहित्य अथवा सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर. इसी प्रकार प्रदीप मिश्र की विधान मंडल में पांच साल की निर्धारित सेवा भी नहीं थी. प्रदीप मिश्र के पास कोई भी निर्धारित न्यूनतम अर्हता नहीं थी. प्रदीप मिश्र की योग्यता केवल इतनी ही थी कि वे विधान सभा अध्यक्ष के दामाद थे.

इसी तरह 12 मई 2015 को डॉ. नरेंद्र शंकर पांडेय, 106 ए ब्लाक, ओसीआर बिल्डिंग, लखनऊ (विधानसभा अध्यक्ष को विधायक के रूप में आवंटित आवास का पता) को वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे स्तर पर विधान सभा अध्यक्ष के निजी स्टाफ में विशेष कार्याधिकारी के राजपत्रित समूह-क पद पर नियुक्त किया गया. इस नियुक्ति में भी नियम और प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन किया गया. इस पद के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई आवेदन आमंत्रित किए गए. डॉ. नरेन्द्र पांडेय की नियुक्ति का कारण भी माता प्रसाद पांडेय का छोटा दामाद होना बताया जा रहा है. नियुक्ति पत्र में डॉ. नरेन्द्र का पता हूबहू वही है, जो इटवा (सिद्धार्थनगर) विधायक के रूप में माता प्रसाद पांडेय का विधान सभा के अभिलेखों में दर्ज है.

नियम विरुद्ध की गई इन नियुक्तियों के सन्दर्भ में राज्यपाल से संज्ञान लेने को कहा गया है. राज्यपाल राम नाईक विधान परिषद के लिए मनोनयन की सूची लौटाकर पहले ही यह संदेश दे चुके हैं कि सत्ताई अंधेरगर्दी की कोई हद होनी चाहिए. अब विधानसभा अध्यक्ष के ताजा मामले पर राज्यपाल का फैसला क्या होगा, इस पर लोगों की निगाहें टिक गई हैं. ■

राज्यपाल से की गई शिकायत में कहा गया है कि इस नियुक्ति में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जो स्पष्ट रूप से बड़ी अनियमितता की तरफ इशारा कर रहे हैं. प्रदीप कुमार मिश्र विधान सभा अध्यक्ष माता पसाद पांडेय के सगे बड़े दामाद हैं. इसी वजह से इस मामले में आनन-फानन में सारी कार्यवाही हो गई. 21 मार्च को दुखीराम प्रोन्नत हुए और दो दिन के अन्दर नई नियुक्ति भी कर दी गई.

कारखानों से निकलने वाली राख मचा रही तबाही

महेंद्र अग्रवाल

विश्व के मानचित्र पर ऊर्जा-राजधानी के रूप में अपनी पहचान बना चुके पावर बेल्ट में एशिया का बृहदतम जलाशय गोविन्द बल्लभ पन्त सागर तो स्थित है ही साथ ही लगभग दो हजार दो सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला कोयले का प्रचुर भंडार भी है, जिससे दो सौ साल तक बीस हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है. इस क्षेत्र में स्थापित सरकारी व गैरसरकारी बिजलीघरों से लगभग नौ हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन तथा कोयले की खुले मुंह की खदानों से डेढ़ लाख टन कोयला प्रतिदिन निकाला जा रहा है. स्थापित तापीय बिजलीघरों में लगभग एक लाख पच्चीस हजार टन कोयला रोज जलाया जा रहा है, जिससे लगभग पचास हजार टन फ्लाई ऐश निकल रहा है. फ्लाई ऐश के रखरखाव एवं उपयोग के लिए वास्तविक धरातल पर सरकार और बिजलीघरों के पास कोई कारगर कार्य योजना नहीं है. फलस्वरूप समूचे ऊर्जांचल क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक देश के दस सर्वाधिक क्षेत्रों में ऊर्जांचल भी शामिल है. बिजलीघरों से निकलने वाले फ्लाई ऐश का लगभग दस फीसदी हिस्सा तो चिमनियों द्वारा वायुमंडल में छोड़ कर वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है और अधिकांश हिस्सा ऐश पॉन्ड के माध्यम से अथवा सीधे ही राष्ट्रीय धरोहर गोविन्द बल्लभ पन्त सागर में बहा कर जल प्रदूषण किया जा रहा है. जलाशय में फ्लाई ऐश के बहाये जाने से भूगर्भी जल भी जलाशय के पानी के साथ-साथ विषाक्त हो चुका है. बिजलीघरों द्वारा आसपास के सरकारी व गैरसरकारी रिहायशी क्षेत्रों में भी फ्लाई ऐश का भराव किया जाना प्रदूषण जनित संक्रमण रोगों को बढ़ा रहा है. गौरतलब है कि मरकरी सहित आर्सेनिक, लेड जैसे हानिकारक एवं अघुलनशील तत्वों का मुख्य ोत कोयला ही है. कोयले को जलाने के बाद ये विषाक्त तत्व फ्लाई ऐश के माध्यम से वायुमण्डल एवं जल में पहुंच कर मनुष्यों, पशु-पक्षियों और वनस्पतियों में प्रवेश कर जा रहे है. जिस कारण इस क्षेत्र में निवास करने वाले हजारों-लाखों लोग विभिन्न प्रकार के संक्रमण एवं खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त होकर जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहे है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं की विभिन्न जांचों, डाक्टरों के निरीक्षण में यह बात सामने आयी है कि कोयला खदानों के क्षेत्र से लेकर रिहन्द जलाशय के जल में तथा वातावरण में अत्यधिक विषाक्त पदार्थ जैसे क्लोरोफार्म, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, आयरन, पेस्टिसाइड, एल्डरिन, इन्डोसुलफेन, कार्बन डाइआक्साइड, सल्फर डाईआक्साइड, नाइट्रोजन डाईआक्साइड, सिलिकान डाइआक्साइड, आयरन आक्साइड, मैगनीशिया, सल्फर ट्राईआक्साइड, सोडियम आक्साइड आदि तत्व निर्धारित मानकों से काफी अधिक मात्रा में विद्यमान हैं, जिसके कारण आंख, नाक, गले की तकलीफें बढ़ जाती हैं. सांस नलिका में व्यवधान आता है. सूंघने और प्रजनन की शक्ति कम होती है. मनुष्य शिथिल एवं बीमार महसूस करता है. मृत्यु दर बढ़ जाता है. मांसपेशियों में शिथिलता, शरीर में ऐंठन, उल्टी, लकवा, हड्डियों का अनियमित बढ़ना, फ्लोरोसिस, जनन क्षमता में ह्रास, स्नायुओं में विकृतियां, गर्भपात आदि की शिकायतें होती हैं. माताओं में दूध कम बनना, प्वाइजनिंग, दांतों का कमजोर होना, बालों का असमय सफेद होना व झड़ना आम बात है. क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश नागरिक पेट सम्बन्धी रोगों से बुरी तरह ग्रसित हैं. वनस्पतियों में पत्तियों का झड़ना, क्लोरोसिस की कमी से पत्तियों का रंग बदलने के साथ-साथ पौधों, वृक्षों, जड़ों का विकास प्रभावित होता है. खाद्य पदार्थों, सब्जियों, फलों आदि में भी पेस्टिसाइड पाया गया है. फ्लाई ऐश के रखरखाव तथा उपयोग के लिए वैसे तो नियम, दिशा निर्देश एवं योजनाएं बहुत हैं, लेकिन वे केवल फाइलों में बन्द हैं और वातानुकूलित कमरों में होने वाले डिबेट तक सीमित हैं. जमीन पर उनका क्रियान्वन नहीं हो रहा है. सरकारों और उसके सम्बद्ध विभागों को इसकी कोई फ्रिक नहीं है. ऊर्जांचल क्षेत्र में शासन-प्रशासन की यह गैरजिम्मेदारी कहीं भी देखी जा सकती है. क्षेत्र के नागरिकों के लिए यह विकराल समस्या बन गयी है. फ्लाई ऐश के बेतरतीब रखरखाव एवं प्रदूषण के सम्बन्ध में पर्यावरणविदों और समाज के लिए संजीदा कुछ पत्रकारों का कहना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अनगिनत पत्र लिख कर लाखों की जिंदगी बचाने और आवश्यक कार्रवाई के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. बस इतना हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और फिर सब वैसे ही रह गया. बढ़ते प्रदूषण की यह स्थिति है कि म्योरपुर और चोपन ब्लॉक के दो दर्जन गांवों में महामारी की स्थिति है. रोहनिया डामर और पढ़नरवा गांव में बच्चे से लेकर बूढ़े तक फ्लोराइड के चलते विकलांग हो चुके हैं. किसी के हाथ-पैर टेढ़े हैं, तो किसी की गर्दन टेढ़ी है. डाला, बिल्ली, चोपन और ओबरा के दो सौ क्रशर प्लांट के चलते लोग सांस की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सकों का भी कहना है कि पिछले करीब एक दशक से इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की वजह से लोग सांस से लेकर पेट तक की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. गोविन्द बल्लभ पंत सागर का पानी पीने लायक नहीं रहा है, लेकिन लोगों के सामने उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है. इतने बड़े जलाशय में बिजली कारखानों को फ्लाई ऐश और केमिकल कारखानों के घातक रसायनों का उत्सर्जन फौरन रोका जाना चाहिए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ऊर्जांचल क्षेत्र में शासन-प्रशासन की यह गैरजिम्मेदारी कहीं भी देखी जा सकती है. क्षेत्र के नागरिकों के लिए यह विकराल समस्या बन गयी है. फ्लाई ऐश के बेतरतीब रखरखाव एवं प्रदूषण के सम्बन्ध में पर्यावरणविदों और समाज के लिए संजीदा कुछ पत्रकारों का कहना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अनगिनत पत्र लिख कर लाखों की जिंदगी बचाने और आवश्यक कार्रवाई के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

कल-कारखाने काल बन रहे हैं

एशिया के सबसे बड़े जलाशय गोविन्द बल्लभ पंत सागर के अस्तित्व में आने के बाद मिर्जापुर जिले के दक्षिणांचल के पठारी वन क्षेत्र और इससे सटे मध्य प्रदेश व बिहार के आदिवासी तथा अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र में विकास की नींव पड़ी और रिहन्द जलाशय के चारों तरफ बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के स्थापित होने से क्षेत्र का औद्योगिकीकरण हुआ. लेकिन पर्यावरण को होने वाले नुकसानों की अनदेखी और परियोजनाओं को होने वाले आर्थिक फायदे को प्राथमिकता दिए जाने के कारण स्थिति अत्यंत भयावह हो गई है. बढ़ते प्रदूषण के कारण ही ऊर्जांचल को देश के पच्चीस सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में सोनभद्र शुमार है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टाक्सीकोलोजिकल रिसर्च सेन्टर आदि ने पिछले दस-बारह साल के अपने सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट में क्षेत्र में लगातार बढ़ते प्रदूषण के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त की है. सर्वेक्षण में क्षेत्र के वायु, जल, ध्वनि, कम्पन को अत्यधिक प्रदूषित, मानकों के विपरीत और समस्त मानव, पशु, वनस्पतियों के लिए विषाक्त पाया है. रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि हिंडाल्को एवं हाईटेक कार्बन अपना प्रदूषित जल रिहन्द नदी में बहा रहे हैं, जिसमें आगे ओबरा थर्मल पावर प्लांट का भी प्रदूषित राख मिश्रित जल आ रहा है. जलाशय के किनारों पर अवस्थित विद्युत गृहों के लापरवाह एवं भ्रष्ट प्रबन्धन के चलते भारी मात्रा में (हजारों टन) राख को प्रदूषित जल के साथ जलाशय में बेधड़क बहाया जा रहा है. अनपरा तापीय परियोजना तो लगभग दस हजार टन राख को प्रदूषित जल के साथ प्रतिदिन रिहन्द जलाशय में खुलेआम बहा रहा है, लेकिन इस ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है. रिहन्द जलाशय में क्लोरिफार्म, मरकरी, आर्सेनिक की बहुत अधिक मात्रा पाई गई है. साथ ही अन्य रसायन भी काफी मात्रा में हैं. इसी तरह ओबरा में रेणुका नदी में भी मरकरी और रेणुकूट के आसपास पेस्टिसाइड अत्यधिक मात्रा में पाया गया है. थर्मल पावर प्लांटों से धूल कण मानक से अत्यधिक ज्यादा उत्सर्जित किये जा रहे हैं. रिपोर्ट में पब्लिक सेक्टर के थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने की बात कही गई है. सर्वेक्षण में एनटीपीसी का सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन को मानकों का उल्लंघन करते पाया गया था. लखनऊ स्थित इंडस्ट्रियल टॉक्सीकोलॉजिकल रिसर्च सेन्टर ने काफी अरसा पहले ही 63 नमूनों का फिजिकल, केमिकल एवं बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण कर पानी में लेड, मरकरी, आर्सेनिक, केडमीनियम, सल्फेट पाया था. हवा में भी मरकरी, सेलेनियम, बारोन, फ्लोरिन, केडमियम, निकल, आर्सेनिक के कण मानक के विपरीत अधिक मात्रा में पाये गए थे. उल्लेखनीय है कि मरकरी से मिनामाटा नामक बीमारी होती है, जिससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता में ह्रास होता है, बोलने, देखने की शक्ति कम होती है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता के साथ-साथ स्नायुतंत्र में भी विकृति पैदा होती है. नवजात शिशुओं के विकास पर कुप्रभाव पड़ता है. इसके विषाक्त प्रभाव से मस्तिष्क को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है. ऊर्जांचल में कम्पन को भी पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ने का प्रमुख कारण माना जा रहा है. जिओ माइनिंग के मानकों के विपरीत कम्पन पैदा होने का कुप्रभाव जमीन के साथ-साथ मनुष्यों, वनस्पतियों पर तो पड़ ही रहा है, क्षेत्र के भवनों आदि पर भी बुरा असर पड़ रहा है. पीक पार्टिकल वेलोसिटी (पीपीवी) 12 एमएम प्रति सेकेंड के निर्धारित मानक का सर्वाधिक उल्लंघन क्षेत्र की कोयला खदानों में ब्लास्टिंग करके किया जा रहा है. ऊर्जांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण से भी बात साफ हो जाती है कि यहां रहने वाले लोग दूसरे गैर औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तुलना में अत्यधिक रोगग्रस्त हैं. यहां के उद्योगों द्वारा लोगों को स्लो प्वाइजन दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता पर सवाल

दीनबंधु कबीर

कानून व्यवस्था की बदहाली से जूझ रही उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी अधिकारी को नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है, जिसे कुछ ही अर्सा पहले कानून व्यवस्था का महकमा ठीक से नहीं संभालने के चलते हटाया गया था. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जाति प्रेम पिछले तीन साल से प्रदेश पर भारी पड़ रहा है. अब प्रदेश के आठ-आठ आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता को ठेंगा दिखाते हुए जगमोहन यादव को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक बना दिए जाने से मुख्यमंत्री की इस प्राथमिकता को और बल मिल गया है. जगमोहन यादव को डीजीपी बनाए जाने के ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी पुलिस के लिए नए वाहनों को हरी झंडी दिखा रहे थे. दूसरे ही दिन सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश की पुलिस की स्टीयरिंग एक कमजोर ड्राइवर के हाथों सौंप दी गई. जगमोहन यादव अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के सातवें डीजीपी हैं. इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2015 तक तक रहेगा. लेकिन अभी से पुलिस के लोग यह मान कर चल रहे हैं कि यादव जी को तो एक्सटेंशन मिलेगा ही. अब यादव जी अपने रहते हुए प्रदेश के पंचायत चुनाव निपटवाएंगे.

योग्यता और अनुभव के हिसाब से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व रेल पुलिस के एडीजी जावेद अहमद डीजीपी पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार थे. लेकिन योग्यता कोई मापदंड नहीं होती. अगर योग्यता का सम्मान होता, तो अरुण कुमार गुप्ता को महीनेभर में ही रिटायर नहीं हो जाना पड़ता. अखिलेश यादव ने अरुण गुप्ता को एक्सटेंशन नहीं दिया, लेकिन रागदरबारी गाने में लगे रहे अरविंद कुमार जैन को कार्यकाल विस्तार बड़े आराम से मिल गया. जगमोहन यादव मौजूदा सपा सरकार में एसी शर्मा, बीआर नागर, रिजवान अहमद, एएल बनर्जी, अरुण गुप्ता और एके जैन के बाद सातवें डीजीपी हैं. 1979 बैच के वरिष्ठम आईपीएस अधिकारी रंजन द्विवेदी, 1980 बैच के सुलखान सिंह, 1981 बैच के मलय कुमार सिन्हा, 1982 बैच के विजय कुमार गुप्ता और प्रवीण सिंह समेत प्रदेश के आठ वरिष्ठ अधिकारी कतार में थे. लेकिन यादव सरकार की पसंद 1983 बैच के आईपीएस जगमोहन यादव ही निकले.

वरिष्ठता क्रम में सबसे ऊपर 1979 बैच के रंजन द्विवेदी का नाम था. इसके बाद 1980 बैच के डीजी प्रशिक्षण सुलखान सिंह का कार्यकाल सितंबर 2017 तक है. 1981 बैच के मलय कुमार सिन्हा फिलहाल केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं. 1981 बैच के ही कमलेन्द्र प्रसाद (डीजी नागरिक सुरक्षा) मथुरा में संकल्प दंपति की विवादास्पद आत्महत्या के प्रकरण में उलझे हैं. 1981 बैच के विजय सिंह (डीजी पीटीएस) पर बसपा के करीबी होने का ठप्पा है. 1982 बैच के डीजी पुलिस आवास निगम और पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड का दायित्व संभाल रहे विजय कुमार गुप्ता पहले भी डीजीपी की दौड़ में मजबूत दावेदारों में रहे थे. 1982 बैच के प्रवीण सिंह (डीजी अग्निशमन) भी निर्विवाद छवि के हैं और उनका नाम डीजीपी के दावेदारों में समय-समय पर चलता रहा है. 1982 बैच के डॉ. सूर्य कुमार शुक्ला (डीजी टेलीकॉम) के नाम पर पिछली बार तो दावे किए जा रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला. 1983 बैच के ओपी सिंह और आरआर भटनागर केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर हैं. लेकिन इन सारे अधिकारियों की वरिष्ठता लांघ (सुपरसीड) कर जगमोहन यादव उत्तर प्रदेश के डीजीपी बन गए और कतार में खड़े उन सारे अधिकारियों की उम्मीदों का पटाक्षेप हो गया.

याद करते चलें कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विफलता को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जताते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) के पद पर तैनात रहे जगमोहन यादव को हटा दिया था. उनके स्थान पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार को कानून व्यवस्था महकमे का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया था. जगमोहन यादव तब तकनीकी सेवा के एडीजी की शंटिंग पोस्ट पर तैनात किए गए थे. लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि जगमोहन यादव को कानून व्यवस्था के महकमे से हटा कर छाया-क्षेत्र में डालना सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया था. अयोग्यता ही जगमोहन के लिए वरदान साबित होने वाली थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

बड़ी चालाकी से लाए गए जगमोहन

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जगमोहन यादव को प्रदेश का डीजीपी बनाने का मोहरा उसी समय फिट कर दिया था, जब उन्हें कानून व्यवस्था में लापरवाही बरतने के नाम पर किनारे किया गया था. उस तबादले के बाद से जगमोहन यादव बिल्कुल लो-प्रोफाइल में चले गए. हमेशा चर्चा में रहने वाले जगमोहन यादव अचानक ही चर्चा से उठ गए. यहां तक कि वे मुख्यमंत्री के यहां दावत से भी गायब रहे, ताकि वे न दिखें और न चर्चा हो. अरुण कुमार गुप्ता को भी डीजीपी इसीलिए बनाया गया था ताकि आगे की गोट सेट हो सके. गुप्ता को महीने भर में ही किनारे लगा कर एके जैन को ला दिया गया. गुप्ता को सेवा में विस्तार नहीं दिया, लेकिन जैन को विस्तार दे दिया, क्योंकि बिसात पर गोट बढ़ाने के लिए यह जरूरी था. दरअसल, आनंद लाल बनर्जी के रिटायर होने के बाद से डीपीसी के जरिए जगमोहन को सामने लाने की कवायद शुरू हो गई थी. बनर्जी के रिटायर होने के बाद डीजी स्तर के अफसरों में 1977 बैच के अरुण कुमार गुप्ता और सुब्रत त्रिपाठी, 1979 बैच के रंजन द्विवेदी और एके जैन, 1980 बैच के सुलखान सिंह, 1981 बैच के मलय कुमार सिन्हा, कमलेन्द्र प्रसाद व विजय सिंह, 1982 बैच के विजय कुमार गुप्ता और प्रवीण सिंह कतार में थे. डीपीसी में एडीजी से प्रोन्नत होकर डीजी स्तर पर आए जगमोहन यादव के बारे में उसी समय से यह संकेत मिल रहे थे कि सरकार उन्हीं पर मेहरबान होगी. केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश कैडर में आइपीएस के 15 पद बढ़ा दिए जाने से भी डीजी के दो पद पर तरक्की का रास्ता खुल गया था.

पुलिस गति में, कानून दुर्गति में

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस को गति देने के लिए 54 करोड़ रुपये की लागत से 1056 नए वाहनों से पुलिस महकमे को सुसज्जित किया. इन वाहनों के प्राप्त होने से एक हजार थानों पर पुलिस को अब एक नहीं बल्कि दो वाहन उपलब्ध हो जाएंगे. अखिलेश यादव ने खुद कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा इतनी संख्या में एक साथ चार-पहिया वाहन पुलिस विभाग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इस कार्यक्रम की हास्यास्पद खूबी यह रही कि मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक एके जैन की सराहना करते हुए कहा कि कम समय में ही उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने का अच्छा काम किया. मुख्यमंत्री की इस थोथी प्रशंसा के बरक्स सच्चाई यह है कि जैन के कार्यकाल में राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अपराध की घटनाएं खूब बढ़ीं और उन पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं रहा. बहरहाल, पुलिस महकमे को जो वाहन दिए गए उन्हें 1000 थानों में तैनात किया जाएगा. इसके अलावा, दूसरे चरण में 37 करोड़ रुपये की लागत से 526 चार-पहिया वाहनों को बाकी बचे थानों को दिया जाएगा. इस तरह प्रदेश के सभी थाने दो-दो वाहनों से लैस हो जाएंगे.

पहले ही आ गई थी डीजीपी की हनक

उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक बनने के पहले ही जगमोहन यादव ने अपने विभाग सीबीसीआईडी में निरंकुशता का सिक्का चलाना शुरू कर दिया था. विभाग में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के होते हुए उन्होंने अपने चहेते पीसीएस अधिकारी पंकज कुमार को सीबीसीआईडी मुख्यालय का प्रभारी बना दिया था. सीबीसीआईडी मुख्यालय में तैनात आईपीएस अफसर शचि घिल्डियाल, उदय शंकर जायसवाल, गीता सिंह समेत कई तेज तर्रार अधिकारी मुंह ही ताकते रह गए. सीबीसीआईडी महकमे में जगमोहन यादव के मंगरू राम गोपनीय सहायक थे. मंगरू के रिटायर होने के बाद जगमोहन ने सरकार की औपचारिक मंजूरी लिए बगैर उनकी सेवा में विस्तार दे दिया और सीक्रेट फंड से उसे वेतन भी देना शुरू कर दिया. मंगरू की तो लॉटरी खुल गई. पेंशन भी और वेतन भी. इस अंधेरगर्दी के खिलाफ दारोगा रवींद्रनाथ चौबे ने साहस करके आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा, तो जगमोहन के मातहत आईपीएस विजय कुमार दीक्षित ने आरटीआई में फर्जी रिपोर्ट बनाकर जवाब भेज दिया. जबकि सच्चाई यह है कि रिटायर होने के बाद भी मंगरू राम सरकारी जीप और ड्राइवर का सुख भोगते रहे. इसके लिए दस्तावेजों में हेरफेर किया जाता रहा. मंगरू सरकारी खर्चे पर सीयूजी फोन का आनंद और सीक्रेट फंड से प्रति माह वेतन उठाते रहे. फंड रजिस्टर में उक्त धनराशि अंकित है. मंगरू को मिलने वाली पेंशन की रकम 30 हजार रुपये प्रति माह इसके अतिरिक्त है. जगमोहन के खास रहे मंगरू तभी तो कहते फिरते थे कि वे सीएम के आदेश से तैनात हैं.

विधान परिषद मनोनयन: राज्यपाल ने पांच विवादास्पद नाम लौटाए, चार को मंजूरी दी

अखिलेश को दी संविधान के पालन की हिदायत

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने विधान परिषद के लिए मनोनीत किए जाने वाले नौ सदस्यों की सूची में से पांच नाम फिर काट दिए. राज्यपाल ने इसके पहले भी मनोनयन की सूची को विवादों से भरा बता कर उसे वापस कर दिया था. लेकिन समाजवादी पार्टी को फिर भी आत्मशुद्धि का कोई विचार नहीं आया. उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने वाली समाजवादी पार्टी के नैतिक-चर्म पर इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि पत्रकार की हत्या के मसले पर राज्यपाल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया या विधान परिषद के मनोनयन की प्रक्रिया में संविधान को ताक पर रख देने के प्रति कितनी बार आगाह किया. पिटने के बाद देह झाड़ कर फिर मुस्कुराने लगने में सपा को विशेषज्ञता हासिल है. विधान परिषद में नौ सदस्यों को मनोनीत करने के लिए राजभवन को दोबारा भेजी गई सूची में से राज्यपाल रामनाईक ने केवल चार सदस्यों के नाम पर मंजूरी की मुहर लगाई. अन्य पांच विवादास्पद नामों के बारे में मिली शिकायतें सरकार को अग्रसारित कर राज्यपाल ने जांच रिपोर्ट देने को कहा है. राज्यपाल ने एसआरएस यादव, जीतेंद्र यादव, रामवृक्ष यादव और लीलावती कुशवाहा के नामों पर अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है. जीतेंद्र यादव राजद नेता लालू यादव के रिश्तेदार हैं. राज्यपाल ने डॉ. कमलेश पाठक, संजय सेठ, रणविजय सिंह, अब्दुल सरफराज खां और डॉ. राजपाल कश्यप की शिकायतों के बारे में जांच रिपोर्ट मांगी है. मुख्यमंत्री सह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 20 मई को ही विधान परिषद में मनोनयन के लिए नौ सदस्यों की सूची राज्यपाल को सौंपी थी. इस सूची की समीक्षा करने के बाद राज्यपाल ने उन सभी के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी थी. इस बीच विभिन्न स्रोतों, संगठनों और नागरिकों की ओर से राज्यपाल को तमाम प्रत्यावेदन दिए गए, जिनमें चुने गए नामों के विवादास्पद होने की जानकारी दी गई.

इसके बाद राजभवन ने अपने स्तर से भी मामले का परीक्षण कराया. राज्यपाल द्वारा पहली सूची वापस कर दिए जाने के बावजूद अखिलेश यादव उसी सूची पर अड़े रहे. पांच नामों के बारे में राज्यपाल राम नाईक को 200 से ज्यादा शिकायतें मिली थीं. इससे पहले मई में भी इन नामों के बारे में शिकायतें मिली थीं. इसके बाद ही राज्यपाल ने सरकार से जवाब मांगा था. सरकार की ओर से सूची के साथ पूरा शपथ पत्र भेज दिया गया. सरकार के इस जवाब से राज्यपाल संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने इस बारे में बाकायदा कानूनी राय ली और सरकार से इन नामों के बारे में स्पष्ट सूचनाएं मांगीं. सरकार से जानकारी नहीं मिल पाने पर राज्यपाल ने पांच नाम खारिज कर दिए. अब विधान परिषद सचिवालय के चार लोगों को ही विधान परिषद सदस्य नामित करने की अधिसूचना जारी करेगा. राज्यपाल ने कहा कि सरकार आरोपों के खिलाफ शिकायतों की जांच करवाएं. दो जुलाई को राज्यपाल ने अखिलेश यादव को राजभवन बुलाया और मनोनयन की सूची के पांच नामों पर अपनी औपचारिक सहमति देने से इंकार कर दिया. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से शेष पांच लोगों द्वारा दिए गए शपथ पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है. राज्यपाल ने इन पांचों के बारे में प्राप्त शिकायती पत्रों को मुख्यमंत्री को भेजते हुए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत कराने के लिए कहा है. राज्यपाल द्वारा फिलहाल खारिज किए गए पांचों लोगों पर शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाने की शिकायतें हैं. शपथ पत्र देकर भी पूरी जानकारी नहीं दी गई और जानकारी छुपाकर इन सभी ने संवैधानिक-अपराध किया है. लिहाजा, इनके नाम पर आगे भी विधिक अड़चन आने की आशंका है.

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को हिदायत दी है कि मनोनयन की प्रक्रिया में भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 (5) में वर्णित कुल पांच क्षेत्रों, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन व समाज सेवा में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के नामों की संस्तुति किए जाने की दृष्टि से भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 (ई) सपठित अनुच्छेद 171 (5) का हूबहू उसकी भावना (लैटर एंड स्प्रिट) के साथ ध्यान रखा जाए. राज्यपाल की इस हिदायत से यह स्पष्ट हुआ कि भेजी गई सूची में संदर्भित नामों को उन्हीं विशेषज्ञता वाली विधा से जुड़ा हुआ बताया गया था. राज्यपाल के इस दृढ़ फैसले से विधान परिषद में मनोनयन का मसला फिलहाल अधर में लटक गया है. समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार दोनों नैतिकता के कठघरे में तो खड़ी है ही. ■

-चौथी दुनिया ब्यूरो

खारिज नामों की विशेषज्ञता

संजय सेठ - अपराध आरोपित व्यक्ति को देश के बाहर जाने में मदद देने का आरोप. वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप. शपथ पत्र में जिक्र नहीं. हाल ही में आयकर के छापे की राज्यपाल को रिपोर्ट नहीं मिली.

कमलेश पाठक - थानों में 19 मामले दर्ज. शिकायतकर्ताओं ने राज्यपाल को केस नंबर तक भेजा. शपथ पत्र में जिक्र नहीं.

रणविजय सिंह- थानों में मामले दर्ज, संविधान में योग्यता के लिए तय किए गए क्षेत्रों में से किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते. मुकदमों का शपथ पत्र में जिक्र नहीं.

राजपाल कश्यप- विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज, छात्र नेता रहने के दौरान किए कई बवाल, अशांति फैलाने के कई आरोप, शपथ पत्र में जिक्र नहीं.

सरफराज खां- सांसद के नाम पर हवाई यात्रा करने की कोशिश में हवाई अड्डे पर ही पकड़े गए थे. पांच दिन की जेल हुई थी. शपथ पत्र में जिक्र नहीं.

सरकार आपदा राहत घोटाले पर पर्दा डालना चाहती है

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड सरकार सूचनाधिकार से सामने आए आपदा राहत घोटाले पर परदा डालने की तैयारी में है. इस मामले को शासन सूचनाधिकार के तहत गलत सूचनाएं देने के मामले के तौर पर पेश कर सूचना देने वाले लोक सूचनाधिकारियों के मत्थे मढ़ सकता है. अब शासन गलत सूचनाएं मुहैया कराने के लिए कुछ लोक सूचनाधिकारियों यानी निचले स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिराकर आपदा के दाग मिटाने की कोशिश कर करने में लगा है. मुख्य सचिव ने आपदा ग्रस्त जिलों के जिलाधिकारियों से मिली रिपोर्ट की पड़ताल के लिए जिस अनौपचारिक समिति का गठन किया था, उसने जो रिपोर्ट अब तक तैयार की है, उसमें कहा गया है कि आपदा के दौरान अनियमितता नाम मात्र की ही हुई है. पिछले दिनों सूचना आयोग में आए एक मामले से जून 2013 की आपदा के बाद राहत कार्य, मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आई थीं. राज्य सूचना आयोग ने इस मामले में सूचना आवेदक भूपेंद्र कुमार के हवाले से गंभीर टिप्पणी की थी कि अधिकारी-कर्मचारी आपदा पीड़ितों की मदद करने गए थे या पीड़ित लोगों की लाशों पर पिकनिक मनाने गए थे. यही नहीं आयोग ने सरकार से मामले की सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद यह प्रदेश का बड़ा सियासी मुद्दा भी बन गया है. इस मुद्दे पर भाजपा अब तक सरकार को घेरने की कोशिश में है. बहरहाल मामला खुलने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव को मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद मुख्य सचिव एन. रविशंकर ने आपदा प्रभावित पांच जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की. रिपोर्ट आने के बाद मुख्य सचिव जिलों से मिली रिपोर्टर की जांच के लिए चार सचिवों की एक अनौपचारित समिति गठित कर दी है. इस समिति में सचिव पर्यटन उमाकांत पंवार, सचिव (वित्त) भास्करानंद, सचिव लोनिवि अमित सिंह नेगी व सचिव आपदा प्रबंधन मीनाक्षी सुंदरम को शामिल किया गया था. आपदा घोटाले की जांच आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े अधिकारियों को ही सौंपने के बाद यह सवाल उठने लगे थे कि विभागीय अधिकारी अपने विभाग के खिलाफ जांच कैसे कर सकते हैं. बहरहाल मुख्य सचिव ने इस अनौपचारिक समिति या अफसरों के समूह को पांचों जिलों से भेजी गई 100 पेजों से ज्यादा की रिपोर्ट का अध्ययन कर 25 जून तक एक ठोस संक्षिप्त ब्योरा बनाने को कहा था. सूत्रों के मुताबिक अब तक जो संक्षिप्त ब्योरा तैयार हुआ है, इसमें नाममात्र की अनियमितितता पाई गई है. यही नहीं यह भी कहा गया है कि मामले ने लोक सूचनाधिकारियों द्वारा गलत दस्तावेज देने के कारण तूल पकड़ा. मसलन ईंधन की रसीद में जिस वाहन का नंबर था एमबी में वह नहीं बल्कि सही नंबर था. इसी तरह की अन्य गड़बड़ियों को लोक सूचनाधिकारी की गलती माना गया है और और कहा गया है कि आपदा के दौरान एक फीसद से कम अनियमिततता हुई. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्य सूचना आयोग ने इस मामले में सूचना आवेदक भूपेंद्र कुमार के हवाले से गंभीर टिप्पणी की थी कि अधिकारी-कर्मचारी आपदा पीड़ितों की मदद करने गए थे या पीड़ित लोगों की लाशों पर पिकनिक मनाने गए थे. यही नहीं आयोग ने सरकार से मामले की सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की थी.

गोमती नदी पर सरकार करा रही है कब्जा

सूफी यायावर

अवध की पहचान गोमती नदी भी किस्म-किस्म के प्रयोगों और दुष्प्रयोगों से गुजर रही है. राजधानी लखनऊ में गोमती की दशा तो नाले से भी खराब है, लेकिन अब भी वह नेताओं, नौकरशाहों, ठेकेदारों और दलालों की कमाई का जरिया बनी हुई है. गोमती नदी के किनारे को कभी मैरीन ड्राइव बनाने के नाम पर बेचा जाता है, तो कभी गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर. शासन-प्रशासन की बेशर्मी के कारण गोमती नदी पहले से ही नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, अब उसके दोनों पाटों पर आधिकारिक अतिक्रमण कर लिया गया है. यानी, अब गोमती स्थायी तौर पर संकरी गली में बहेगी, उसकी स्वाभाविकता और प्राकृतिक गति पर धनपशुओं के मोटर बोट चलेंगे और पैसे कमाएंगे. अब गोमती नदी मिट्टी के किनारों को नहीं छू पाएगी, वह सीमेंट-गारे से बने पाट से टकराएगी और चूर-चूर हो जाएगी.

गोमती नदी के किनारे पर अभी धुंआधार काम हो रहा है. लेकिन सारे सरकारी विभाग यह कह कर पल्ला झाड़ रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, उन्हें नहीं मालूम. सिंचाई विभाग ने तो यहां तक कह दिया कि कोई परियोजना ही नहीं चल रही. अब सिंचाई विभाग के मंत्री शिवपाल यादव हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बड़े जोर-शोर से गोमती सफाई के नाम पर गोमती रिवर फ्रंट का काम शुरू करा चुके हैं. गोमती सफाई के नाम पर चल रही परियोजना का काम गैमन इंडिया को दिया गया. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर मंत्री शिवपाल यादव तक इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं. लेकिन पर्यावरण, जल निगम, एलडीए, जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग तक इस परियोजना को लेकर रहस्य बनाए हुए हैं. लिहाजा, अखिलेश यादव के ड्रीम प्रॉजेक्ट गोमती सफाई अभियान पर सवाल खड़े होने लगे हैं. गोमती में सफाई का काम कौन करा रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, तो यह मामला अत्यंत गंभीर है. सामाजिक संस्था जनाधिकार के कर्ताधर्ता अशोक शंकरम की आरटीआई के जरिए यह उजागर हुआ कि गोमती सफाई नाम की ऐसी कोई परियोजना ही नहीं चल रही है. जबकि विडंबना यह है कि परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव दीपक सिंघल की मौजूदगी में अपने सरकारी आवास पर किया था.

बहरहाल, अखिलेश सरकार ने जो सपना दिखाया है, उसके मुताबिक गोमती नदी का विकास विदेशों की तर्ज पर होगा. इसमें दोनों किनारों पर हरियाली, पार्क, साइकिल व तांगा ट्रैक, घाट व क्रीड़ा स्थल विकसित किए जाएंगे. बोटिंग कराने की भी योजना है. गोमती के किनारे-किनारे घूमने के लिए वॉकिंग-ट्रैक भी तैयार किया जाएगा. 656 करोड़ की गोमती रिवर फ्रंट योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि दो साल में यह काम पूरा हो जाएगा. यानी समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में गोमती नदी के अतिक्रमण का काम पूरा कर लेगी. सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना का काम चल रहा है. गोमती रिवर फ्रंट को विश्व के अच्छे शहरों की तरह विकसित किया जाएगा. इसके लिए जापान के टोक्यो व ओसाका शहर का भी भ्रमण किया जा चुका है. मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा था कि रिवर फ्रंट के साथ ही इसमें पर्यटन के कई स्थल विकसित किए जाएंगे. पर्यटन विभाग से इसके लिए बात चल रही है. भविष्य में इसमें रिवर क्रूज चलाने की योजना है. क्रूज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही लोग इसमें खाने-पीने का भी लुत्फ उठा सकेंगे. मुख्यमंत्री ने परियोजना को दो साल में पूरा होने की बात कही तो मुख्य सचिव ने इसे घटा कर डेढ़ साल कर दिया और कहा कि डेढ़ साल में ही इसे लखनऊ वासियों को समर्पित कर दिया जाएगा. सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव दीपक सिंघल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को दो महीने में तैयार किया गया और आनन-फानन में कैबिनेट से भी पास करा लिया गया और मुख्यमंत्री के आदेश पर वित्त विभाग ने तत्काल 600 करोड़ रुपये दे भी दिए. इसमें बजट की कोई कमी नहीं. गोमती नदी के दोनों किनारों पर डायफ्राम वॉल बनाकर नदी को व्यवस्थित किया जाएगा. गोमती के किनारे हरियाली होगी. इस योजना के तहत गोमती को लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर साफ किया जाएगा.

हास्यास्पद विरोधाभास यह है कि गोमती रिवर फ्रंट के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे मुख्य सचिव आलोक रंजन एक साल पहले गोमती को लेकर कुछ और ही कह रहे थे. आलोक रंजन 2014 में कह रहे थे कि गोमती नदी का विकास अहमदाबाद की साबरमती की तर्ज पर किया जाएगा. गुजरात की साबरमती की ही तरह गोमती नदी के दोनों किनारे विकसित किए जाएंगे और पार्क बनाए जाएंगे. एक ही साल में आलोक रंजन साबरमती से जापान और लंदन पहुंच गए. बहुप्रचारित कथित रिवर फ्रंट डेवेलपमेंट से गोमती नदी 15 मीटर संकरी हो जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शहर तो नहीं, लेकिन लखनऊ से जुड़े गोमती नदी के किनारे बसे ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ जाएगा. 1971 में आई बाढ़ के बाद बांध बनाकर गोमती नदी को पहले से ही समेट कर रख दिया गया था, अब और भी कसर पूरी की जा रही है. रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत हो रहे काम में एक बार फिर गोमती का फ्लड प्लेन संकरा किया जा रहा है. फ्लड प्लेन में अतिक्रमण पहली बार नहीं हो रहा. इस पर दशक दर दशक कब्जा होता रहा है और इसके हिस्से की जमीन पर मकान खड़े किए जाते रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लड प्लेन पर एक बार फिर से किया जा रहा अतिक्रमण पर्यावरण को भीषण नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि 1970 में शहर में गोमती नदी करीब 70 मीटर चौड़ी थी. इसके फ्लड प्लेन में मौजूदा पेपर मिल कॉलोनी और राणा प्रताप मार्ग शामिल हैं. बाद में इस पर पूरी तरह अतिक्रमण हो गया. 1971 की बाढ़ के बाद गोमती के तटबंधों को काफी ऊंचा कर दिया गया. पहले इनकी ऊंचाई मौजूदा ऊंचाई की आधी ही थी. गोमती की अब की चौड़ाई केवल 50 मीटर रह गई है और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के बाद इसकी चौड़ाई 35 से 40 मीटर रह जाने की आशंका है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक डॉ. वीके जोशी कहते हैं कि गोमती की जमीन पर आवास नहीं बन सकते. न तो कानून इसकी इजाजत देता है और न ही पर्यावरण. लेकिन गैरकानूनी बसावट ने पूरे फ्लड प्लेन को लील लिया. नदी विशेषज्ञ डॉ. वेंकटेश दत्ता का मानना है कि बसपा सरकार के कार्यकाल में गोमती के फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण हुआ था. समता मूलक चौराहे के आसपास निर्माण चल रहा था. तब भारी बरसात हुई थी और आसपास बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी. अंबेडकर पार्क में पानी भर गया था. यह गोमती के फ्लड प्लेन पर पक्के निर्माण की वजह से ही हुआ था. ऐसी ही कोशिश समाजवादी सरकार के कार्यकाल में फिर से हो रही है. लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आईबी सिंह कहते हैं कि गोमती को संकरा करके गहरा करने का कोई मतलब नहीं है. गोमती समेत गंगा बेसिन की नदियों की खासियत है कि वे अपने साथ काफी सिल्ट लाती हैं. जब किनारे कच्चे होते हैं तो नदियां सेडिमेंट किनारों पर छोड़कर बढ़ जाती हैं. जब दीवार पक्की हो जाएगी तो किनारे विस्तार नहीं ले सकेंगे, जबकि नदियों के साथ सेडिमेंट आता जाएगा. अब सेडिमेंट केवल गोमती की तलहटी में जमा होगा, जिससे गहराई पटती जाएगी और एक दिन नदी ही समाप्त हो जाएगी.

वाकई, गोमती ने अपने लिए रास्ते हजारों साल में बनाए हैं. इसमें किसी तरह का कृत्रिम बदलाव नहीं होना चाहिए. यह गोमती का अपना प्राकृतिक बहाव है. रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में गोमती के किनारे बनने वाली डायफ्रम वॉल इसके सर्पीले आकार को खत्म करके सीधा और सपाट करेगी जो गोमती को नुकसान करने का ही कारण बनेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सूख रही है गोमती

एक सर्वेक्षण रिपोर्ट यह कहती है कि प्रशासनिक-सामाजिक हरकतों के कारण गोमती नदी कई जगहों पर सूख रही है. यह रिपोर्ट उस भविष्यवाणी की पुष्टि करती है कि 32 वर्षों में गोमती पूरी सूख जाएगी. सरकार जिस तरह की हरकतें कर रही है उससे गोमती के नष्ट हो जाने में कुछ कम ही वक्त लग सकता है. फिर सूखी हुई गोमती के किनारे नेतागण अपना-अपना तांगा चलाएंगे. मिशन कल के लिए जल अभियान चलाने वाले चंद्रभूषण पांडेय ने मुख्यमंत्री से यह मांग भी की थी कि लखनऊ में गोमती तट पर कब्जा करने के लिए लालयित बिल्डरों, ठेकेदारों और भूमाफियाओं के दबाव में तट सौन्दर्यीकरण के नाम पर बनाए गए कांट्रेक्टर ड्रिवेन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर अविलंब रोक लगाई जाए. संपूर्ण गोमती के प्रवाह क्षेत्र के लिये पर्यावरण मित्र, नदी हितैषी और प्रकृति के संरक्षण की नीतियों के साथ सरकार को आगे आना चाहिए. लेकिन यह मांग करते समय उन्हें यह कहां पता था कि गोमती-गोरखधंधे में सत्ताधारी नेता ही शामिल हैं.

हास्यास्पद विरोधाभास यह है कि गोमती रिवर फ्रंट के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे मुख्य सचिव आलोक रंजन एक साल पहले गोमती को लेकर कुछ और ही कह रहे थे. आलोक रंजन 2014 में कह रहे थे कि गोमती नदी का विकास अहमदाबाद की साबरमती की तर्ज पर किया जाएगा. गुजरात की साबरमती की ही तरह गोमती नदी के दोनों किनारे विकसित किए जाएंगे और पार्क बनाए जाएंगे. एक ही साल में आलोक रंजन साबरमती से जापान और लंदन पहुंच गए. बहुप्रचारित कथित रिवर फ्रंट डेवेलपमेंट से गोमती नदी 15 मीटर संकरी हो जाएगी.

इधर नेता का कब्जा, उधर माफियाओं का

लखनऊ में गोमती नदी के दोनों किनारे अब सरकार के जरिए नेताओं के कब्जे में होंगे. खूब धंधा चलेगा. धन बरसेगा. उधर थोड़ी दूर चलें तो गोमती के किनारे भूमाफियाओं का कब्जा मिलेगा. अब वह समय भूल जाएं जब गोमती नदी के किनारे सैकड़ों एकड़ जमीन पर जंगल की तरह पेड़ खड़े मिलते थे. गोमती के किनारों की हरियाली काट कर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा लिया है. अब तो गोमती की धारा तक खेती की जा रही है. यह हाल गोमती के किनारों पर कहीं भी देखा जा सकता है. शहरी क्षेत्र से अलग गोमती के किनारे-किनारे अवैध कॉलोनियों का बेतहाशा विस्तार हो रहा है. इसमें भूमाफियाओं के साथ-साथ सत्ताधारी दल के नेता भी शामिल हैं. गोमती नगर विस्तार में दर्जनों अवैध कॉलोनियां बस रही हैं. सूचना यह भी है कि अखिलेश यादव सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की कंपनी एमजीए की कॉलोनी भी इनमें एक है. इनके अलावा दिलीप सिंह बाफिला, डीएस मनराल, हीरा सिंह बिष्ट और ऐसे ही कई अन्य नाम भी इस कड़ी में शामिल हैं. इन अवैध कालोनियों में 10 हजार से ज्यादा प्लॉट बेचकर आम लोगों से अरबों रुपये वसूले जा चुके हैं. कई लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा जमीनों में फंसा हुआ है. अधिक कॉलोनियों की सूची सामने है, लेकिन इनमें से एक पर भी कार्रवाई नहीं हो सकती है. गोमती नगर विस्तार और उसके आस-पास के इलाके मल्हौर, भरवारा, हरिहरपुर जैसे अन्य कई इलाकों में ऐसी ही कई कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं. अवैध कॉलोनियों की सूची में लक्ष्मी विहार-2 शिवकुमार पाल, छोटा भरावन, एमजीए कॉलोनाइजर हरिहरपुर, सुल्तानपुर रोड, प्रेमचन्द्र यादव, छोटा भरवारा, गोमतीनगर विस्तार, सचिव साईं फार्म, रॉयल रेजार्ट, सिकंदरपुर लौलाई, न्यू एमिटी कैम्पस, सौरभ सिंह, भुजंगी पुरवा मल्हौर समेत कई अन्य कॉलोनियां शामिल हैं. गोमती नदी के किनारे-किनारे जमती जा रही बस्तियों के बारे में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है.

सभी फोटो-*विनय गुप्ता*